



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2016/आश्विन 8, 1938

No. 316]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2016/ASVINA 8, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2016

अंतिम जांच परिणाम

**विषय :** चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'ट्रेलर के लिए एक्सल' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच ।

**फा. सं. 14/17/2015-डीजीएडी.—** समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए

**क. मामले की पृष्ठभूमि**

2. यतः मै. यार्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्रा. लि. (जिसे आगे आवेदक या घरेलू उद्योग भी कहा गया है) ने संबंधित अधिनियम और नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने दिनांक 9 जून, 2004 को चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'ट्रेलर के लिए एक्सल' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरुआत करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति का आरोप लगाया गया और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया।

3. और यतः प्राधिकारी ने जाँच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 1 जनवरी, 2016 के शुद्धिपत्र के साथ पठित दिनांक 28 दिसम्बर, 2015 अधिसूचना सं. 14/17/2015-डीजीएडी द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसमें नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्धपाटनरोधी जाँच की शुरुआत की गई ताकि कथित पाटन की मौजूदगी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

**ख. प्रक्रिया**

4. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- i. आवेदन की प्रारंभिक जाँच से कतिपय कमियों का पता चला जिन्हें बाद में आवेदक द्वारा सुधार दिया गया। अतः आवेदन को उचित रूप से दस्तावेजयुक्त माना गया। प्राधिकारी ने जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन के विरुद्ध जाँच की शुरुआत करने का निर्णय लिया।
- ii. प्राधिकारी ने संबंधित नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जाँच की शुरुआत करने से पहले पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया।
- iii. जाँच की शुरुआत के बाद प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादक/निर्यातक ज्ञात आयातक/प्रयोक्ता और घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार जाँच शुरुआत अधिसूचना की एक-एक प्रति भेजी और जाँच शुरुआत अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
- iv. प्राधिकारी ने संबंधित नियम 6(3) के अनुरूप संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावास को इस आवेदन के अगोपनीय पाठ की प्रति उपलब्ध कराई थी। भारत में संबद्ध देश के दूतावास को उनके देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का भी अनुरोध किया गया। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी चीन जन. गण. के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ उन्हें भी भेजी गई थी।
- v. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों से संगत सूचना मंगाने के लिए उन्हें प्रश्नावलियां भेजीं:
  - 1) शानडोंग जिनशेंग एक्सल मैनुफैक्चरिंग कं. लि.,  
शानडोंग, चीन जन. गण.
  - 2) गुआंगडोंग फुवा इंजीनियरिंग मैनुफैक्चरिंग कं. लि.,  
गुआंगडोंग प्रदेश, चीन जन. गण.
  - 3) फोशान यांगलिताइ एक्सल कं. लि.  
गुआंगडोंग चीन जन. गण.
  - 4) एलियन मैनुफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग लि.  
हेनान, चीन जन. गण.
  - 5) गुआंगझू टीएनडी एक्सल कं. लि.  
गुआंगडोंग, चीन
- vi. जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना और सूचना के उततर में चीन जन. गण. से निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर भरकर प्राधिकारी को उत्तर दिया है:
  1. गुआंगडोंग फुवा इंजीनियरिंग मैनुफैक्चरिंग कं. लि.
  2. गुआंगडोंग फुवा हैवी इंडस्ट्रीज कं. लि.
  3. शानडोंग जिनशेंग एक्सल मैनुफैक्चरिंग कं. लि.
- vii. चीन जन. गण. से उक्त प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों में से गुआंगडोंग फुवा इंजीनियरिंग मैनुफैक्चरिंग कं. लि. और गुआंगडोंग फुवा हैवी इंडस्ट्रीज कं. लि. ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार चीन जन. गण. के गैर बाजार अर्थव्यवस्था होने की मान्यता का खंडन करते हुए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) प्रश्नावली का उत्तर भी प्रस्तुत किया है। तथापि मौके पर सत्यापन से पहले गुआंगडोंग फुवा इंजीनियरिंग मैनुफैक्चरिंग कं. लि. और गुआंगडोंग फुवा हैवी इंडस्ट्रीज कं. लि. ने बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करने के उनके दावे को वापस ले लिया है।
- viii. भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आवश्यक सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावलियां भेजी गई थी:
  1. ट्रांस्टार हैंडलिंग वेयरहाउसिंग प्रा. लि.
  2. किंग कावेरी ट्रेडिंग कंपनी

3. एच. डी. ट्रेलर्स प्रा. लि.
4. टाटा इंटरनेशनल डीएलटी प्रा. लि.
5. सीमलैस आटोटेक प्रा. लि.
6. ब्लेक डायमंड मोटर्स प्रा. लि.
7. डेक्कन वेहिकल्स प्रा. लि.
8. अरिहंत आटोट्रेड्स
9. शिवम मोटर्स प्रा. लि.
10. ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन्स इंडिया प्रा. लि.
11. वंदना ट्रेलर्स एंड बाॅडी मैन्युफै. (प्रा.) लि.
12. सेट्रेक इंजीनियरिंग प्रा. लि.
13. श्री दुर्गा फेब्रिकेशन
14. शीतल मोटर्स
15. वी.एस. ट्रेलर्स
16. लोह इंडिया आटोमोटिव प्रा. लि.
17. टिप्पर्स एंड ट्रेलर्स इंडिया प्रा. लि.
18. जगतजीत आटोमोटिव कं. प्रा. लि.

ix. इसके प्रत्युत्तर में निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक प्रश्नावली के उत्तर और अनुरोधों के माध्यम से उत्तर दिया है:

1. किंग कावेरी ट्रेडिंग कंपनी
2. एच.डी. ट्रेलर्स प्रा. लि.

x. इसके अलावा निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने अनुरोध करके पत्र लिखकर प्राधिकारी को उत्तर दिया है परंतु यथा लागू आयातक प्रश्नावली के उत्तर नहीं दिया है:

1. सेट्रेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लि.
2. सेफटेक ट्रेलर्स पार्ट्स एलएलपी
3. सिनर्जिक ट्रेलर्स एंड आटो सॉल्यूशंस प्रा. लि.
4. शिवम मोटर्स प्रा. लि.
5. ब्लेक डायमंड मोटर्स प्रा. लि.
6. वंदना ट्रेलर्स एंड बाडी मैन्युफै. (प्रा.) लि.
7. एमएस ट्रेलर पार्ट्स एलएलपी

xi. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश को हितबद्ध पक्षों द्वारा निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाइल के रूप में खुला रखा।

xii. सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की उचित लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत को ज्ञात किया गया है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा अथवा नहीं।

xiii. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करावें।

- xiv. घरेलू उद्योग और निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना का सूचना प्रदान करने वाले पक्षों के परिसर में आवश्यक सीमा तक कार्यस्थल पर सत्यापन किया गया था। जहां आवश्यक हो आवश्यक सुधार के बाद ऐसी सत्यापित सूचना पर ही वर्तमान वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ भरोसा किया गया है।
- xv. प्राधिकारी ने पीओआई के रूप में 1 अप्रैल, 2014 से 30 जून 2015 (15 महीने) पर विचार किया गया है ताकि सबसे हाल के आकड़ों का विश्लेषण किया जा सके। इस प्रकार, जॉच 1 अप्रैल 2014 से 30 जून 2015 (पीओआई) की अवधि के लिए की गई थी। तथापि क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जॉच में अप्रैल 11-मार्च 12, अप्रैल 12- मार्च 13, अप्रैल 13-मार्च 14 और जॉच की अवधि की अवधियां शामिल हैं।
- xvi. गौण स्रोत (आईबीआईएस) के अनुसार आयात सूचना आवेदक द्वारा आवेदन में उपलब्ध कराई गई है। आईबीआईएस के अनुसार विभिन्न पाटनरोधी जॉचों में भारत में दी गई पीयूसी के देश वार मात्रा और आयातों के मूल्य की जानकारी के लिए अनेक पिछली जॉच में भी प्राधिकारी द्वारा भरोसा किया गया है। प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा प्रस्तुत आईबीआईएस के अनुसार आयात आकड़ों पर भरोसा किया है। तथापि, इन आकड़ों को डीजीसीआईएंडएस के आकड़ों के साथ उचित ढंग से जोड़ा गया है और यह नोट किया जाता है विपथन की कोई प्रवृत्ति नहीं है।
- xvii. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से सुनने के लिए 5 मई, 2016 को आम सुनवाई आयोजित की जिसमें हितबद्ध पक्षों/उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हितबद्ध पक्षों को लिखित अनुरोध और खंडन यदि कोई हों, प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। संगत समझी गई सीमा तक इस वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में हितबद्ध पक्षों से प्राप्त लिखित अनुरोधों और खंडनों पर विचार किया है।
- xviii. हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित निवेदनों/प्रत्युत्तरों में दिए गए तर्कों को जहां कहीं भी प्रासंगिक पाया गया है, उन पर इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- xix. पाटन-रोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए अनिवार्य तथ्यों को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकटन किया गया है और उन पर उनसे प्राप्त टिप्पणियों पर जहां कहीं भी प्रासंगिक पाया गया है, इस अंतिम जांच परिणाम में उचित विचार किया गया है।
- xx. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जॉच की प्रक्रिया के दौरान उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया है या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है तो प्राधिकारी ने ऐसे पक्षों को असहयोगी माना है और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में दर्ज किया है।
- xxi. इस अंतिम जॉच परिणाम में ‘\*\*\*’ किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का द्योतक है।
- xxii. पीओआई के लिए अम. डा. को रुपये में बदलने की विनियम दर को सीमाशुल्क आकड़ों के अनुसार 62.13 रूपए = 1 अमरीकी डॉलर के रूप में लिया गया है।

## **ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

### **ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

5. वर्तमान जॉच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ट्रेलरों के लिए एक्सल है।
6. ट्रेलर के लिए एक्सल अनिवार्य रूप से बीम/बार और ब्रेकड्रम, ब्रेक शूज, बीयरिंग आदि जैसे अन्य घटकों का संयोजन है जो किसी ट्रेलर के दोनों पहियों को जोड़ते हैं और ट्रेलर के एक्सल के रूप में कार्य करते हैं।
7. संबद्ध वस्तु को विभिन्न प्रकारों में विनिर्मित और बेचा जाता है। तथापि, इन सभी प्रकारों की मूल उत्पाद विशेषताएं और अंतिम प्रयोग समान रहता है और ट्रेलर एक्सल के ऐसे प्रकार पीयूसी के दायरे में शामिल हैं जूँकि ये प्रकार तुलनीय मूल विशेषताओं और समान कार्यों/प्रयोगों के साथ समतुल्य पीयूसी बनाते हैं।
8. विचाराधीन उत्पाद एक वाहन (ट्रेलर) कलपुर्जा और सहायक सामान है, जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 87 के अंतर्गत और इसके अलावा उपशीर्ष सं. 87169010 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। चूँकि उपशीर्ष समर्पित वर्गीकरण नहीं है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है। तथापि ट्रेलर के अलावा वाहन के लिए एक्सल को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है। आवेदक ने यह भी अनुरोध किया गया है कि एक्सलों को ड्राइव या लाइव एक्सल और डेड या डम्मी एक्सल के रूप में व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जाता है। पीयूसी डेड या डम्मी एक्सल के अंतर्गत आता है और ड्राइव या लाइव एक्सल वर्तमान जॉच के दायरे से बाहर हैं।

9. भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित घरेलू समान उत्पाद के समान है। आवेदक के उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है और ये दोनों भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं और आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु के बीच कोई खास अंतर नहीं है और ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

#### ग. 2 निर्यातक, आयातक, प्रयोक्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोध

10. प्रतिवादी यह अनुरोध करता है कि प्रतिवादियों द्वारा बेचे गए और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एक्सलों की गुणवत्ता में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। विशेष रूप से, प्रतिवादी का एक्सल फुवा इंजीनियरिंग ग्रुप लि. (बाजार आसूचना के अनुसार चीन जन. गण. में जिसका 80 प्रतिशत बाजार हिस्सा है) द्वारा उत्पादित यूनिक वन-पीस है जिसे घरेलू उद्योग द्वारा चार (4) अलग-अलग हिस्सों की वैल्विंग के विपरीत हाट फार्मिंग स्पिंडलस प्रौद्योगिकी से वन-पीस बीम के प्रयोग द्वारा बनाया जाता है। घरेलू उद्योग का उत्पाद कमजोर/अस्थिर होता है और बाजार आसूचना के अनुसार वह दैनिक प्रयोग से बेकार हो जाता है। इसके अलावा, प्रतिवादियों द्वारा बेचे जाने वाले एक्सल में सस्पेंशन कार्य और रख-रखाव लागत के संबंध में भी लाभ है। बाजार आसूचना से पता चलता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एक्सलों के संबंध में उपभोक्ताओं में काफी असंतोष है।

11. एक प्रतिवादी हितबद्ध पक्ष ने यह कहते हुए विचाराधीन उत्पाद के दायरे और वर्णन पर प्रश्न उठाया है कि दो तरह के एक्सल होते हैं लाइव या ड्राइव एक्सल और डेड या डमी एक्सल और पीयूसी केवल डेम या डम्मी एक्सल है और इस संबंध में जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का अतिलिखन किया गया है और उस सीमा तक यह शून्य है। केकेटीसी द्वारा उनके खंडन संबंधी अनुरोध में यह बताया है कि पीयूसी और समान वस्तु का दायरा मामले के गुणों के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निर्णय किया जाना चाहिए।

#### ग.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

12. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ट्रेलरों के लिए एक्सल है। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया कि संबद्ध वस्तु को विभिन्न प्रकारों में विनिर्मित किया और बेचा जाता है। तथापि, इन सभी प्रकारों की मूल उत्पाद विशेषताएं और अंतिम प्रयोग समान रहता है और ट्रेलर एक्सल के ऐसे प्रकार पीयूसी के दायरे में शामिल हैं। यह देखा गया है कि ये प्रकार तुलनीय मूल विशेषताओं और समान कार्य/प्रयोगों के साथ अनिवार्य रूप से समनुरूपी विचाराधीन उत्पाद बनाते हैं।

13. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद एक वाहन कलपुर्जा और सहायक सामान है, जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 87 के अंतर्गत और इसके अलावा उपशीर्ष सं. 87169010 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। चूंकि उपशीर्ष समर्पित वर्गीकरण नहीं है इसलिए सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जाँच में निर्धारित उत्पाद के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

14. विचाराधीन उत्पाद के दायरे और वर्णन संबंधी आपत्ति के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में पीयूसी को स्पष्ट रूप से ट्रेलरों के लिए एक्सल के रूप में परिभाषित किया गया और ट्रेलरों से इतर वाहनों के एक्सलों को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया और आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए सभी अन्य अनुरोधों की भी जाँच की गई है।

15. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में समान वस्तु को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

*“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जाँच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;*

16. प्राधिकारी ने दावों की जाँच की है और यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। उक्त के मद्देनजर, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को पाटनरोधी नियमावली के संबंधित नियम 2 (घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान घरेलू वस्तु माना जा रहा है।

**घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति****घ. 1 निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षों के अनुरोध**

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में निर्यातकों/आयातकों/प्रयोक्ताओं/अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए विभिन्न अनुरोधों की निम्नानुसार जाँच की गई है:

- आवेदक द्वारा संबद्ध वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का दावा सही प्रतीत नहीं होता है।
- काफी बाजार प्रतिस्थापन हुआ है जो उत्पाद के लिए नये वाहन खंड से भी अधिक है और लुधियाना जैसे स्थानों से लघु उत्पादक भी उत्पादन कर रहे हैं और ऐसे बाजार और उत्पादकों के उत्पादन पर विचार नहीं किया गया है।
- टाटा ग्रुप ने कच्ची सामग्री का आयात और स्वदेशी रूप से खरीद की है जो टाटा ब्रांड के अधीन तीसरे पक्ष के आयातों के अलावा कुछ नहीं हैं। प्राधिकारी इस बात की जाँच कर सकते हैं कि क्या ऐसी स्वदेशी खरीद भारत में वास्तव में निर्मित थी अथवा नहीं।
- आवेदक की ग्रुप कंपनी अर्थात् टाटा मोटर्स को आवेदन में अवश्य भागीदारी करनी चाहिए थी।
- भारतीय उत्पादन के अनुमानित आकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
- याचिकाकर्ता ने स्पष्ट नहीं किया है कि याचिकाकर्ता अनुमानों तक कैसे पहुँचा है और यह समझना संभव नहीं है कि आवेदक ने उनके लिखित अनुरोध में प्रदत्त रूप से एक्सल की बिक्रियों की जरूरत के आधार पर भारतीय उत्पादन (अन्य भारतीय उत्पादकों का अनुमानित उत्पादन) के अनुमान कैसे ज्ञात किये हैं।
- भारत में मांग को याचिका में गलत बताया गया है। "एसआईएएम" द्वारा प्राप्त आकड़ों के अनुसार एक्सल की संख्या और भारत में अपेक्षित उनकी मात्रा (मी.ट. में) वित्तीय वर्षों 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में परिकलित की गई है जो निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	पीओआई वार्षिकीकृत
मांग - याचिका के अनुसार	एमटी	13,892	8,762	16,639
मांग - एसआईएएम आकड़ों के अनुसार परिकलित	एमटी	18,593	13,109	27,644

- मांग में काफी असमानता है और याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त आकड़े गलत हैं और किसी साक्ष्य के बिना हैं। यह भी नोट किया जाए कि ट्रक के ऐसे उत्पादक हैं जो एसआईएएम का हिस्सा नहीं हैं और उनके आकड़ों को शामिल नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि मांग बताए गए कि तुलना में काफी अधिक है।
- कुल उत्पादन के आकड़ों को कम बताए जाने के आलोक में, घरेलू उत्पादन में याचिकाकर्ता का हिस्सा और संदिग्ध हो जाता है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि उत्पादन का हिस्सा पीओआई में यह मानने पर भी केवल 47 प्रतिशत है कि प्राइम मूवर्स की बिक्रियों को एक्सल के उत्पादन के परिकलन के लिए प्रयोग किया जाए। इसका सत्यापन नीचे तालिका से किया जा सकता है:

विवरण	इकाई	
एक्सल की मांग (प्रमुख मूवर्स की बिक्री के आधार पर निर्धारित)	एमटी	27,644
आयात	एमटी	6,600
भारत में उत्पादन (मांग - आयात)	एमटी	21,044
घरेलू उद्योग का उत्पादन (याचिका के अनुसार)	एमटी	9,959
घरेलू उत्पादन में हिस्सा (घरेलू उद्योग का उत्पादन)	एमटी	47.3%

- x. आटोमोटिव एक्सलस लि. ने याचिका का समर्थन किया है। तथापि यह नोट किया जाए कि समर्थक कंपनी एक्सल की नियमित उत्पादक नहीं है और तभी एक्सल का उत्पादन करती है जब मांग की जाए।
- xi. आटोमोटिव एक्सलस लि. का समर्थन संदिग्ध है।
- xii. यह संदेह है कि याचिकाकर्ता का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा न हो।
- xiii. याचिकाकर्ता के भरोसे पर लाया गया सांविधिक आदेश सहायक नहीं है - इसमें ट्रेलरों के लिए जरूरी एक्सलों की संख्या नहीं बताई गई है बल्कि 1996 में मौजूद वाहनों के प्रकार पर आधारित अधिकतम सुरक्षित एक्सल भार बताया गया है। 5 वर्ष पहले बाजार की वास्तविकताएं अलग थी जहां सिंगल एक्सल ट्रेलर लोकप्रिय थे और डबल एक्सल ट्रेलरों को अधिकांशतः सभी ट्रेलरों में प्रयोग किया जाता था।
- xiv. यह अवश्य नोट किया जाए कि सिंगल एक्सल ट्रेलरों को बहुत कम प्रयोग किया जा रहा है और यदि प्रयोग किया जाता है तो उसे सार्वजनिक सड़कों पर बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता। यदि यह मान भी लें कि प्रमुख मूर्वर्स से जुड़े 10 प्रतिशत ट्रेलरों में सिंगल एक्सल है तो यह अनुमान कि 80 प्रतिशत 2 एक्सल का प्रयोग करते हैं तो वह बाजार की वास्तविकता से बिल्कुल अलग होगा।
- xv. याचिकाकर्ता का अनुमान कि प्रमुख मूर्वर्स से जुड़े 10 प्रतिशत ट्रेलरों में सिंगल एक्सल का, 80 प्रतिशत 2 एक्सल और शेष 10 प्रतिशत 3 का प्रयोग करते हैं, गलत है। परिणामस्वरूप, एक्सल की कुल आवश्यकता अर्थात् 57472 जो याचिकाकर्ता ने ज्ञात की है, गलत है।
- xvi. इस मान्यता कि प्रमुख मूर्वर्स की बिक्री का उत्पादन का अनुमान लगाने में प्रयोग किया जा सकता है, से उत्पादन के आकड़ों की भारी अल्प प्रतिनिधित्व होगा क्योंकि उसमें नहीं बिके एक्सल शामिल नहीं हैं, रिप्लेसमेंट बाजार में उत्पादित एक्सल नहीं शामिल हैं और एसआईएम में प्रमुख मूर्वर्स के अनेक उत्पादक शामिल नहीं हैं।

## घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

17. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए विभिन्न अनुरोधों की निम्नानुसार जाँच की गई है:

- i. यह आवेदन मैं. योर्क ट्रांसपोर्ट इन्क़िपमेंट (इंडिया) प्रा. लि. द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया है। मैं. योर्क ट्रांसपोर्ट इन्क़िपमेंट (इंडिया) प्रा. लि. संबद्ध वस्तु का सबसे बड़ा भारतीय विनिर्माता है। आटोमोटिव एक्सल लि. ने आवेदन का समर्थन किया है। आवेदक कंपनियों का उत्पादन घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। अंतः प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर आवेदक कंपनियों को पात्र घरेलू उद्योग मान सकते हैं।
- ii. आवेदक और समर्थक कंपनी को छोड़कर, निम्नलिखित कंपनियां भी या तो बाजार या आबद्ध खपत के लिए संबद्ध वस्तु के उत्पादन में शामिल हैं। अन्य उत्पादकों ने हमारी जानकारी के अनुसार न तो वर्तमान जाँच का समर्थन किया है न विरोध।
  - क. टाटा मोटर्स
  - ख. अशोक लेलैंड लि.
  - ग. जोस्ट इंडिया आटो कंपोनेंट प्रा. लि.
  - घ. जी.एस. आटो इंटरनेशनल लि.
- iii. प्रदत्त सूचना से पता चलता है कि आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक है और उसके पास कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा है और वह स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है। यद्यपि क्षति संबंधी सूचना केवल आवेदन पर आधारित है, एक अन्य भारतीय उत्पादक मैं. आटोमोटिव एक्सलस लि. ने आवेदन/याचिका का समर्थन किया है।
- iv. कतिपय विरोधी हितबद्ध पक्षों ने कुछ विरोधी दावे किए हैं ताकि स्थिति और घरेलू उद्योग के रूप में पात्रता संबंधी घरेलू उद्योग के अनुरोधों पर प्रश्न उठाया जा सके। तथापि प्राधिकारी नोट कर सकते हैं कि ऐसे विरोधी अनुरोध वास्तविक रूप से सही नहीं हैं और वह संबद्ध वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन के बढ़ा-चढ़ा कर लगाये गए अनुमानों पर आधारित है जो संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन की वास्तविक स्थिति को देखते हुए सही नहीं हैं।
- v. प्रतिवादी हितबद्ध पक्ष अर्थात् केकेटीसी ने भारत में प्रमुख मूर्वर्स के उत्पादन के संबंध में एसआईएम द्वारा प्रकाशित कतिपय आकड़ों के वास्तविक गलत व्याख्या पर अपने तर्क को आधारित किया है जिसमें ऐसे ट्रेलरों के टनभार के रूप में संबद्ध वस्तु अपेक्षित होती है जिसे 35 टन और 40 टन और उससे अधिक के ट्रेलरों में विभाजित किया जा सकता है। केकेटीसी ने अपने अनुरोध में निम्नानुसार आकड़ों पर संक्षेप में विचार किया है:

विवरण	केकेटीसी के अनुसार एसआईएम पर आधारित प्राइम मूवर्स की संख्या
	2014-15
<b>35 टन</b>	
अशोक लेलेंड	1,937
एएमडब्लू मोटर्स	1
आयशर	61
महिन्द्रा एंड महिन्द्रा	74
टाटा मोटर्स	3,292
ट्रेलर एक्सल की जरूरत वाले कुल प्रमुख मूवर्स	<b>5,365</b>
<b>40 टन और उससे अधिक</b>	
अशोक लेलेंड	8,044
एएमडब्लू मोटर्स	113
आयशर	316
महिन्द्रा एंड महिन्द्रा	402
टाटा मोटर्स	13,916
ट्रेलर एक्सल की जरूरत वाले कुल प्रमुख मूवर्स	<b>22,791</b>
<b>केकेटीसी के अनुसार प्राइम मूवर्स के उत्पादन पर आधारित एक्सल की कुल जरूरत कुल = (5365*2+22791*3)</b>	<b>79,103</b>

- vi. केकेटीसी के अनुरोधों के अनुसार भारतीय उत्पादन के आकड़े दर्शाते हैं कि केकेटीसी ने यह माना है कि सभी 35 टन प्राइम मूवर्स में ट्रेलर के साथ जुड़े 2 एक्सल ही होते हैं और 40 टन और उससे अधिक के सभी में उनसे जुड़े ट्रेलरों में 3 एक्सल फिट होते हैं और उन्होंने इस मान्यता के आधार पर एक्सलों की आवश्यकता ज्ञात की है जो वास्तविकता नहीं है। केकेटीसी ने 5365 प्राइम मूवर्स को 2 एक्सल से गुणा कर दिया है और 22791 प्राइम मूवर्स को 2014-15 के दौरान 79103 एक्सल की कुल आवश्यकता को ज्ञात करने के लिए 3 एक्सल से गुणा कर दिया है। इस प्रकार से केकेटीसी ने दावा किया है कि 35 टन और उससे अधिक के ट्रेलरों में सिंगल एक्सल प्रयोग नहीं होते हैं जो सही नहीं है।
- vii. हम केकेटीसी के बिल्कुल काल्पनिक अनुमानों पर प्रश्न उठाते और उनसे असहमत हैं जिनमें उनके तर्क के अनुकूल उत्पादन के आकड़ों को बढ़ा कर बताया गया है और इसके विपरीत हम प्राधिकारी के समक्ष नीचे दिए गए आकड़ों को प्रस्तुत करते हैं जो बाजार के तथ्यों और वास्तविकताओं पर आधारित हैं और भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन और बिक्री की पद्धति के संदर्भ में है। मोटे तौर पर ऐसे तीन पहलू हैं जिन्हें आसानी से केकेटीसी द्वारा आवेदक की स्थिति पर प्रश्न उठाने के लिए यथोक्त रूप से एक्सल की काफी उच्च संख्या निकालते समय भुला दिया गया है जिसपर नीचे चर्चा की गई है।
- viii. केकेटीसी का दावा ऐसे अनुरोध के समान है कि 35 टन या उससे अधिक के ट्रेलरों में एकल एक्सल का प्रयोग नहीं होता है। यह कतिपय ट्रेलरों की विशेषताओं से स्पष्ट है जिनमें दर्शाया गया है कि 35 टन और अधिक टनभार के होते हुए सिंगल एक्सल का प्रयोग किया जाता है। यही बात दर्शाती है कि केकेटीसी का तर्क गलत है और केकेटीसी द्वारा परिकल्पित भारतीय उत्पादन अव्यवहार्य है। इसके अलावा, सिंगल एक्सलों को 40 टन और उससे अधिक आदि सहित टनभार के व्यापक रेंज में भी प्रयोग किया जाता है।



- ix. केकेटीसी के दावे में दूसरी त्रुटि यह है कि उन्होंने दावा किया है कि 40 टन या अधिक के ट्रेलरों में अनन्य रूप से 3 एक्सलों का प्रयोग होता है और यह भी दावा किया गया है कि 40 टन या अधिक के ट्रेलरों में अनिवार्य रूप से 3 एक्सलों के प्रयोग की सांविधिक अपेक्षा है। इस संबंध में आवेदक ने अधिकतम सकल वाहन भार और अधिकतम सुरक्षित एक्सल भार के विनिर्देशन से संबंधित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिनांक 18.10.1996 की अधिसूचना सा.आ. 728 (अ) पर भरोसा किया है। इस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से केकेटीसी द्वारा अपनायी गई मान्यता कि 40 टन या अधिक के ट्रेलरों में अनिवार्य रूप से 3 एक्सलों की जरूरत होती है, गलत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार 40 टन या अधिक के ट्रेलरों में 2 एक्सल भी हो सकते हैं और बाजार की यही सत्यता है। 40 टन या अधिक के ट्रेलरों में दो एक्सलों का भी व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इस आधार पर भी, केकेटीसी की संबद्ध वस्तु की भारी आवश्यकता ज्ञात करने की गणना अव्यवहार्य है।
- x. केकेटीसी द्वारा विचार नहीं किया गया तीसरा बिंदु यह है कि प्राइममूवर्स की संख्या को सीधे नई एक्सल जरूरत में बदलना गलत है क्योंकि कुछ प्राइम मूवर्स बाजार की मांग को पुराने एक्सलों और रेल के पुराने एक्सलों से पूरा किया जाता है और इसके साथ ही प्राधिकारी को प्रदान किए गए हैं। कुल मिलाकर, केकेटीसी द्वारा ज्ञात की गई एक्सलों की संख्या तथ्यों और वास्तविकता के अनुसार नहीं है और प्राधिकारी द्वारा जाँच प्रक्रिया पर आधारित नहीं हो सकती है क्योंकि यह अत्यंत त्रुटिपूर्ण और स्वअनुकूल है। इस प्रकार आवेदक केकेटीसी द्वारा प्रस्तुत ट्रेलर एक्सलों की कुल जरूरत के आकड़े से इनकार करता है क्योंकि यह वास्तविकता के अनुसार नहीं है।
- xi. आवेदक ने प्राइम मूवर्स के उत्पादन से संबंधित 2014-15 और 2015-16 की पहली तिमाही की अवधि के लिए विस्तार से उपलब्ध एसआईएएम के आकड़ों पर भी विचार किया है ताकि ट्रेलर में एक्सल की कुल जरूरत के अनुमान को ऐसे प्राइम मूवर्स के साथ पहले संबद्ध वस्तु की जरूरत से जोड़ा जा सके और उसके आधार पर पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु का कुल भारतीय उत्पादन ज्ञात किया जा सके:

विवरण	प्राइम मूवर्स का उत्पादन (एसआईएएम आकड़ों के अनुसार)		
	2014-15	क्यू1 15-16	पीओआई
<b>35 टन</b>			
अशोक लेलेंड	1,937	592	2,529
एएमडब्लू मोटर्स	1	6	7
आयशर	60	14	74
महिन्द्रा एंड महिन्द्रा	72	17	89
टाटा मोटर्स	3,292	699	3,991
ट्रेलर एक्सल की जरूरत वाले कुल प्राइम मूवर्स	<b>5,362</b>	<b>1,328</b>	<b>6,690</b>
<b>40 टन और उससे अधिक</b>			
अशोक लेलेंड	2,663	661	3,324
एएमडब्लू मोटर्स	108	10	118
आयशर	267	99	366
महिन्द्रा एंड महिन्द्रा	402	177	579
टाटा मोटर्स	13,916	3,743	17,659
ट्रेलर एक्सल की जरूरत वाले कुल प्राइम मूवर्स	<b>17,356</b>	<b>4,690</b>	<b>22,046</b>
एसआईएएम के अनुसार प्राइम मूवर्स के उत्पादन पर आधारित एक्सल की कुल जरूरत कुल = (10%*1+80%*2+10%*3)	<b>45,436</b>	<b>12,036</b>	<b>57,472</b>

- xii. हमारा यह तर्क संगत अनुमान है कि 10 प्रतिशत प्राइम मूवर्स के पास सिंगल एक्सल ट्रेलर उनसे जुड़े हुए हैं, 80 प्रतिशत प्राइम मूवर्स में 2 एक्सल है और अन्य 10 प्रतिशत 30 अंश और 40 टन से अधिक की श्रेणी के 3 एक्सल ट्रेलर हैं। उस आधार पर उक्त तालिका में पीओआई में लगभग 57,472 के एक्सल की जरूरत दर्शाई गई है।
- xiii. संख्या के अनुसार ज्ञात कुल भारतीय उत्पादन और आवेदक का हिस्सा निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है जिसमें कुल भारतीय उत्पादन में यार्क का हिस्सा 63.20 प्रतिशत दर्शाया गया है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यार्क पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित योग्यता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है और यार्क कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है। यह भी नोट किया जाए कि ऐसी जरूरत के कुछ हिस्से को वास्तव में पुराने और पुराने रेल एक्सलों से पूरा किया जाता है जिसे गणना में नहीं दर्शाया गया है और इसे शामिल करने से पीओआई के दौरान नए एक्सलों की कुल जरूरत और कम हो जाएगी। ऐसे एक्सलों पर विचार करने पर यार्क का हिस्सा संबद्ध वस्तु की कुल अनुमानित भारतीय उत्पादन में और अधिक हो जाएगा।

विवरण	एसआईएम के प्राइम मूवर्स के आकड़ों के अनुसार एक्सलों की जरूरत - मात्रा सं. में		
	2014-15	क्यू 15-16	पीओआई
एक्सल की जरूरत	45,436	12,036	57,472
सभी देशों से आयात	17,918	5,157	23,075
भारतीय उत्पादकों द्वारा बेचे गए एक्सल	27,518	6,879	34,397
याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्रियां	14,834	3,846	18,680
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री के अनुमान	12,684	3,033	15,717
अन्य भारतीय उत्पादकों का अनुमानित उत्पादन	13,352	3,193	16,544
यार्क का उत्पादन	22834	5584	28,418
कुल भारतीय उत्पादन			44,962
यार्क का हिस्सा			63.20
समर्थक के साथ यार्क का हिस्सा			69.60%

- xiv. आवेदक ने भारत में संबद्ध वस्तु के सभी ज्ञात उत्पादकों के ब्योरे उपलब्ध कराए हैं और पीओआई के दौरान भारत में संबद्ध वस्तु के कुल उत्पादन का पता लगाने के लिए तर्कसंगत पद्धति अपनायी गई है इस प्रकार आवेदक की स्थिति के दावे की सत्यता के परीक्षण के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। आवेदक द्वारा प्राधिकारी के समक्ष उसकी स्थिति की वास्तविक दशा को रिकार्ड में लाने के सभी प्रयास किए गए हैं। इसके होते हुए भी प्राधिकारी सभी अन्य भारतीय उत्पादकों को पत्र लिख सकते हैं और उनसे पीओआई के दौरान उनके द्वारा संबद्ध वस्तु के वास्तविक उत्पादन का प्रकटन करने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा एक विकल्प के रूप में प्राधिकारी संबंधित उत्पाद शुल्क विभाग को पीओआई के दौरान ऐसी अन्य कंपनियों द्वारा संबद्ध वस्तु के उत्पादन का ब्यौरा देने के लिए पत्र लिख सकते हैं। ऐसे उत्पादकों द्वारा उत्पादन की वास्तविक सूचना और उनके सहयोग के अभाव में आवेदक द्वारा किए गए दावों को सही और विश्वसनीय माना जाना चाहिए और इस संबंध में प्रतिवादी पक्षों के तर्कों को खारिज किया जाना चाहिए।
- xv. हितबद्ध पक्षों द्वारा दिया गया एक तर्क यह है कि टाटा मोटर्स लि. आवेदक का एक संबंधित पक्ष है और उसे वर्तमान जाँच में भागीदारी करनी चाहिए थी। तथापि इस दलील में कोई कानूनी या वास्तविक व्यवहार्यता नहीं है। टाटा मोटर्स लि. और आवेदक की भी की वार्षिक रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में है। वार्षिक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि दोनों कंपनियां अलग-अलग धारक कंपनियों के अधीन अलग विधिक कंपनियां हैं और हितबद्ध पक्षों द्वारा बताए गए अनुसार संबंधित पक्ष नहीं हैं जिसमें यार्क टाटा मोटर्स को वर्तमान जाँच में भागीदारी करने के लिए कहने की किसी शक्ति का प्रयोग करे। जहां तक यार्क का संबंध है टाटा मोटर्स या कोई अन्य उत्पादक याचिका का समर्थन या विरोध करने के लिए स्वतंत्र है और यार्क का उनके इस निर्णय में कोई योगदान नहीं है। यार्क नियम 2(ख) की अपेक्षाओं को पूरा करता है और टाटा मोटर्स की भागीदारी करने या नहीं करने संबंधी चर्चा का घरेलू उद्योग के गठन को शासित करने वाले नियम के अधीन कोई अंतर नहीं है। नियम में संक्षेप में कुल उत्पादन में 25

प्रतिशत से अधिक के उत्पादकों के स्पष्ट समर्थन की बात है और वर्तमान मामले में समान वस्तु के कुल उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक के समर्थन के साथ यार्क के पास अकेले ही कुल भारतीय उत्पादन का 63 प्रतिशत हिस्सा है। (स्पष्टीकरण के साथ पठित नियम (5), (3), (क) और (ख))।

- xvi. उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह दोहराया और अनुरोध किया जाता है कि मै. यार्क ट्रांसपोर्ट इन्क़िपमेंट (इंडिया) प्रा. लि. के पास अपेक्षित योग्यता है और उन्हें वर्तमान जॉच और संगत जॉच परिणामों के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए।
- xvii. प्रतिवादी पक्षों के इस दावे के संबंध में कि आवेदक द्वारा संबद्ध वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का दावा सही प्रतीत नहीं होता है और काफी बाजार प्रतिस्थापन हुआ है जो उत्पाद के लिए नये वाहन खंड से भी अधिक है और लुधियाना जैसे स्थानों से लघु उत्पादक भी उत्पादन कर रहे हैं और ऐसे बाजार और उत्पादकों के उत्पादन पर विचार नहीं किया गया है, यह अनुरोध किया जाता है ये दलीलें गलत हैं। पीयूसी का कोई प्रतिस्थापन बाजार नहीं है क्योंकि एक्सल की लाइफ ट्रेलर की लाइफ के बराबर या उससे अधिक होती है। इसके अलावा प्रतिवादी पक्ष द्वारा कुछ उत्पादन करने वाले लघु उत्पादकों के बारे में सही सूचना नहीं दी गई है और ऐसी कल्पनाओं का कोई महत्व नहीं होता है।
- xviii. इस दलील के संबंध में कि टाटा ग्रुप ने कच्ची सामग्री का आयात और स्वदेशी रूप से खरीद की है जो टाटा ब्रांड के अधीन तीसरे पक्ष के आयातों के अलावा कुछ नहीं हैं। प्राधिकारी इस बात की जाँच कर सकते हैं कि क्या ऐसी स्वदेशी खरीद भारत में वास्तव में निर्मित थी अथवा नहीं, यह अनुरोध किया जाता है ऐसी दलीलों की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि आवेदक एक अलग विधिक कंपनी है और कोई संबंधित पक्ष नहीं है।
- xix. इस दलील के संबंध में कि आवेदक की ग्रुप कंपनी अर्थात् टाटा मोटर्स को आवेदन में अवश्य भागीदारी करनी चाहिए थी यह अनुरोध किया जाता है आवेदक पाटनरोधी नियमावली के अधीन योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है और किसी भी मामले में टाटा मोटर्स लि. कानून की दृष्टि से संबंधित कंपनी नहीं है।
- xx. इस दलील के संबंध में कि भारतीय उत्पादन के अनुमानित आकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और याचिकाकर्ता ने यह नहीं बताया है कि याचिकाकर्ता इस अनुमान पर कैसे पहुँचा है और संबद्ध वस्तु के उत्पादन के अनुमान के आधार पर प्राइम मूवर्स के उत्पादन को मानने पर भी आवेदक का हिस्सा केवल 47 प्रतिशत है, यह अनुरोध किया जाता है प्रतिवादी पक्षों ने माना है कि आवेदक का अकेले हिस्सा लगभग 47 प्रतिशत है। यह सूचना गोपनीय रखी गई है और उस नियम के अधीन अनुमत्य है और ऐसे दावों का औचित्य आवेदन में बताया गया है।
- xxi. इस दलील के संबंध में कि आटोमोटिव एक्सलस लि. ने याचिका का समर्थन किया है। तथापि यह नोट किया जाए कि समर्थक कंपनी एक्सल की नियमित उत्पादक नहीं है और तभी एक्सल का उत्पादन करती है जब मांग की जाए और आटोमोटिव एक्सलस लि. द्वारा समर्थन संदिग्ध है, यह नोट किया जाता है कि ये दावे निराधार हैं। आटोमोटिव एक्सलस लि. द्वारा प्रदत्त स्पष्ट समर्थन पत्र है। इसके अलावा इस दावे में कोई वास्तविक या विधिक आधार नहीं है कि आटोमोटिव एक्सलस लि. एक नियमित उत्पादक नहीं है।
- xxii. इस दलील के संबंध में कि यह संदेह है कि याचिकाकर्ता का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा नहीं हो सकता है, यह अनुरोध किया जाता है कि ऐसे संदेह निराधार हैं क्योंकि साक्ष्य दर्शाते हैं कि आवेदक के पास भारतीय उत्पादन में अधिकांश हिस्सा है। वास्तव में प्रतिवादी पक्षों ने यह माना है कि यार्कभारत में संबद्ध वस्तु के सबसे बड़ा उत्पादक है।

### घ.3 प्राधिकारी द्वारा जॉच

18. पाटन रोधी नियमावली का नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

*“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में घरेलू उद्योग पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।*

19. यह नोट किया जाता है कि वह आवेदन जिसके आधार पर वर्तमान पाटनरोधी जॉच की शुरुआत की गई है भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उद्योग की ओर से मै. यार्क ट्रांसपोर्ट इन्क़िपमेंट (इंडिया) प्रा. लि. द्वारा दायर किया गया है। यह पाया गया है कि आवेदक मै. यार्क ट्रांसपोर्ट इन्क़िपमेंट (इंडिया) प्रा. लि. संबद्ध वस्तु का सबसे बड़ा भारतीय विनिर्माता है। इसके अलावा, मै. आटोमोटिव एक्सलस लि. ने स्पष्ट रूप से आवेदन का समर्थन किया है।

20. यथोक्त आवेदक उत्पादक और समर्थक उत्पादक के अलावा आवेदक ने निम्नलिखित कंपनियों को या तो आवद्ध खपत के लिए या व्यापारी बाजार के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादक के रूप में अभिज्ञात किया है।

- क. टाटा मोटर्स  
ख. अशोक लेलैंड लि.  
ग. जोस्ट इंडिया आटो कंपोनेंट प्रा. लि.  
घ. जी.एस. आटो इंटरनेशनल लि.

21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त किसी अन्य उत्पादक ने जाँच का उत्तर नहीं दिया है। इसलिए इन कंपनियों ने न तो आवेदन का समर्थन और न ही विरोध किया है। नियम 5 के स्पष्टीकरण में बताया गया है कि इस नियम के प्रयोजनार्थ आवेदन को तब घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से माना जाएगा यदि वह उन घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित हो जिनका समग्र उत्पादन आवेदन का समर्थन या विरोध, जैसा भी मामला हो, करने वाले घरेलू उद्योग के उस हिस्से द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन के पचास प्रतिशत से अधिक बनता हो। वर्तमान मामले में आवेदक का समर्थन या विरोध करने वाले घरेलू उद्योग के उस हिस्से द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है।

22. यह भी देखा गया है कि कुल भारतीय उत्पादन के संबंध में सूचना सार्वजनिक डोमेन में तत्काल उपलब्ध नहीं है और आवेदक ने कुल भारतीय उत्पादन के अनुमान की पद्धति तैयार की है और ऐसे अनुमानित कुल भारतीय उत्पादन में आवेदक का अकेले हिस्सा और समर्थक के साथ हिस्सा बताया है। यह प्राइममूवर्स के उत्पादन आकड़ों पर भरोसा करता है जिनमें ट्रेलर लगा होता है जिनमें संबद्ध वस्तु का प्रयोग होता है जिसे बाद में सोसाइटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैनुफेक्चरर्स (एसआईएम) ने भारत में संबद्ध वस्तु की मांग का पता लगाने का आधार माना है और भारत में संभावित घरेलू उत्पादन की गणना की है। एसआईएम के आकड़े पूरी पीओआई के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। एसआईएम द्वारा सूचित प्राइममूवर्स के उत्पादन की कुल संख्या में से आवेदक ने लगभग 10 प्रतिशत के लिए उसमें 1 एक्सल पर विचार किया है और 80 प्रतिशत को 2 एक्सल वाला माना है और शेष 10 प्रतिशत को 3 एक्सल वाला माना है। पीओआई के लिए विचारित प्राइम मूवर्स की संख्या में विभिन्न प्रकार के ट्रेलर जैसे 35 टन, 40 टन आदि शामिल हैं। नीचे दिए गए आकड़े ऊपर दिया गया आधार उपलब्ध कराते हैं जिसमें कुल भारतीय उत्पादन में अकेले आवेदक के हिस्से और समर्थक के साथ हिस्से की तुलना में निम्नलिखित स्थिति दर्शाई गई है। निम्नांकित तालिका ऐसे अनुमान के आधार के रूप में स्वतः स्पष्ट है:

विवरण	एसआईएम द्वारा प्रकाशित और आवेदक द्वारा दावा किए गए प्राइम मूवर्स के आकड़ों के अनुसार एक्सलों की आवश्यकता – मात्रा सं. में		
	2014-15	क्यू 1 15-16	पीओआई
एक्सल की जरूरत (क) (प्राइम मूवर्स का उत्पादन $10\% \times 1 + 80\% \times 2 + 10\% \times 3$ जैसे ऊपर वर्णित है)	45,436	12,036	57,472
सभी देशों से आयात (ख)	17,918	5,157	23,075
भारतीय उत्पादकों द्वारा बेचे गए एक्सल	27,518	6,879	34,397
याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्रियां (क)	14,834	3,846	18,680
अन्य भारतीय उत्पादकों की अनुमानित बिक्रियां (ख)	12,684	3,033	15,717
अन्य भारतीय उत्पादकों का अनुमानित उत्पादन	13,352	3,193	16,544
यार्क का उत्पादन	22834	5584	28,418
कुल भारतीय उत्पादन			44,962
यार्क का हिस्सा			63.20
समर्थक के साथ यार्क का हिस्सा			69.60%

23. उपर्युक्त सूचना यह दर्शाती है कि आवेदक अकेले कुल भारतीय उत्पादन का 63.20% उत्पादन करता है और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लगभग 69.60% का शेयर हो जाता है। चूंकि विस्तृत जांच से प्राप्त स्पष्ट तथ्यों के आधार पर भारत में ऐसी सम्बद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन में आवेदक के उत्पादन का "एक प्रमुख अनुपात" है, प्राधिकारी का यह पता लगाने का प्रस्ताव है कि आवेदक स्थायी

मानदंडों को पूरा करता है और एडी नियमों के नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग को स्थापित करता है। प्राधिकारी यह पाते हैं कि आवेदक आधार के मानदंड को पूरा करता है और पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में उल्लिखित परिभाषा के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनता है।

24. यहां तक कि अगर ऐसे अनुमान, जिसे प्रतिपक्षों द्वारा दिया गया है, को आधार के रूप में लिया जाता है, तो भी आवेदक, भारत में सम्बद्ध वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक है और आवेदक की अकेले लगभग 47% हिस्सेदारी है। इस प्रकार ऑटोमोटिव एक्सल के उत्पादन के साथ-साथ याचिकाकर्ता का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन के 50% से अधिक है। इसके अलावा, प्राधिकारी को इस तरह के अन्य ज्ञात निर्माताओं से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इसलिए ये कंपनियाँ आवेदन का न तो समर्थन करती हैं और न ही विरोध करती हैं। इस प्रकार वर्तमान मामले में आवेदन के पक्ष में समर्थन घरेलू उद्योग के ऐसे भाग द्वारा उत्पादित समान सामग्री के कुल उत्पादन के बड़े हिस्से को स्थापित करता है जिसका वे या तो समर्थन करते हैं अथवा विरोध व्यक्त करते हैं। इस परिदृश्य में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के आवेदन के साथ साथ कुल भारतीय उत्पादन में उनकी हिस्सेदारी को अस्वीकार करने का कोई सबूत रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।

25. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि उत्पाद के लिए नए वाहन के क्षेत्र से अधिक होने पर भी पर्याप्त प्रतिस्थापन बाजार है और लुधियाना जैसे स्थानों से प्रचालन कर रहे छोटे पैमाने के उत्पादक हैं और ऐसे बाजार के लिए उत्पादन तथा उत्पादकों पर विचार नहीं किया गया है, यह नोट किया गया है कि दावा निराधार है साथ ही इस तरह के दावों को पुष्ट करने के लिए कोई सबूत उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदकों ने कहा कि सम्बद्ध वस्तु के लिए कोई भी महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन बाजार नहीं है। ट्रेलर की तुलना में एक्सल की मियाद को अधिक बताते हुए कुछ ट्रेलर विनिर्माताओं द्वारा ट्रेलर विनिर्माण में पुराने एक्सल को तरजीह देने तथा उपयोग करने के सबूत हैं और इसलिए प्रतिवादी इच्छुक पक्षों की दलील को खारिज किया जाता है।

26. जहाँ तक इस विवाद का संबंध है, टाटा समूह ने आयात किया है और देश में ही कच्चे माल की खरीद भी की है जो कि और कुछ नहीं मात्र टाटा ब्रांड के तहत तीसरे पक्ष का आयात है और प्राधिकारी यह जाँच कर सकते हैं कि क्या इस तरह की स्वदेशी खरीद वास्तव में भारत में किया गया है अथवा नहीं, इस तरह की कोई भी दलील किसी भी मान्य सबूतों से समर्थित नहीं है।

27. जहाँ तक इस विवाद का संबंध है कि आवेदक के समूह की कंपनी अर्थात् टाटा मोटर्स ने आवेदन में भागीदारी की है, यह नोट किया गया है कि समर्थक के साथ मेसर्स यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को नियम 2(ख) के अनुसार वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के रूप में पाया गया है और अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा नियम 2(ख) की आवश्यकताओं के अलावा यथा प्रस्तुत कुछ भी नियम को अनिवार्य नहीं बनाता है। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदक ने कहा है कि टाटा मोटर्स लिमिटेड एक अलग कानूनी इकाई है और किसी भी मामले में नियमों में यथा अभिकल्पित एक संबंधित पक्ष नहीं है तथा आवेदक वर्तमान आवश्यकता को पूरा करता है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की परीक्षा करने पर यह देखा और पाया गया है कि यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (एशिया) प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर द्वारा धारित है। टीआरएफ लिमिटेड, भारत टीआरएफ सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर द्वारा धारित कंपनी है। टीआरएफ लिमिटेड, भारत के शेयर मुख्य रूप से निम्नानुसार द्वारा धारित हैं : टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा 34.29% और टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानि प्रमोटर और प्रमोटर समूह द्वारा 0.02% और बाकी सार्वजनिक शेयरधारिता है। टाटा मोटर्स लिमिटेड और टीआरएफ लिमिटेड, भारत के बीच साझा शेयरधारिता टाटा स्टील लिमिटेड और टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैं और वे टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयरों में क्रमशः 2.90% और 2.50% के धारक हैं। इसलिए यह अनुमान लगाना गलत है कि टाटा मोटर्स लिमिटेड और यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पाटन रोधी नियमों के नियम 2 (ख) के अनुसार संबंधित कंपनियाँ हैं।

28. हालांकि, यह पाया गया है कि टाटा इंटरनेशनल डीएलटी प्राइवेट लिमिटेड और यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड संबंधित कंपनियाँ हैं और उनके कुछ साझा निदेशक हैं। यह भी नोट किया जाता है कि टाटा इंटरनेशनल डीएलटी प्राइवेट लिमिटेड ने घोषणा की है कि उन्होंने सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। इसके अलावा टाटा इंटरनेशनल डीएलटी प्राइवेट लिमिटेड सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादन में शामिल नहीं है। इसलिए समर्थक के साथ-साथ मेसर्स यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग के रूप में पाया गया है और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई एक घोषणा यह है कि उन्होंने पाटन रोधी नियमों के नियम 2 (ख) के अनुसार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी सम्बद्ध पक्ष से सम्बद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।

29. जहाँ तक इस विवाद का संबंध है कि भारतीय उत्पादन के अनुमानित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, प्राधिकारी नोट करता है कि कुल भारतीय उत्पादन के बारे में सूचना का अनुमान अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री के 5% इन्वेंटरी को जोड़कर लगाया गया है। अन्य भारतीय उत्पादकों के बिक्री आंकड़े को कुल भारतीय मांग की तुलना में संबद्ध वस्तुओं के न्यूनतम हैं और घरेलू उद्योग के घरेलू बाजार में बिक्री के बीच के अंतर को घटा कर लिया जाता है।

30. जहाँ तक इस विवाद का संबंध है कि याचिकाकर्ता ने यह नहीं समझाया है कि याचिकाकर्ता अनुमान पर कैसे पहुँचा है, प्राधिकारी नोट करता है कि याचिका और घरेलू उद्योग द्वारा तदनुसार प्रस्तुत आवेदन इस पहलु के संबंध में स्वयं-पुष्ट है।

31. जहाँ तक इस विवाद का संबंध है कि यदि केवल प्राइम मूवर्स के उत्पादन को ही सम्बद्ध वस्तुओं को मापने का आधार बनाया जाता है तो भी आवेदक की हिस्सेदारी लगभग मात्र 47% है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य इच्छुक पक्षों के आवेदन यह दर्शाते हैं कि

ऑटोमोटिव एक्सेल के समर्थन सहित घरेलू उद्योग के दावे घरेलू उत्पादन के 50% से अधिक हैं और घरेलू उद्योग के दावों का विवरण पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है तथा इस पर ऊपर चर्चा की जा चुकी है।

32. जहाँ तक इस विवाद का संबंध है कि ऑटोमोटिव एक्सेल लिमिटेड द्वारा याचिका का समर्थन किया गया है और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि समर्थक कंपनी एक्सेल का नियमित उत्पादक नहीं है तथा केवल जब मांग होती है तभी एक्सेल का उत्पादन करती है, प्राधिकारी यह नोट करता है कि समर्थक के साथ मैसर्स यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को नियम 2(ख) के अनुसार वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के रूप में पाया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्यतः पीयूसी का उत्पादन ऑर्डर के अनुसार किया जाता है और इच्छुक पक्षों ने इस संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किया है कि क्यों मैसर्स ऑटोमोटिव एक्सेल लिमिटेड को सम्बद्ध वस्तुओं के नियमित उत्पादक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

33. जहाँ तक इस विवाद का संबंध है कि ऑटोमोटिव एक्सेल लिमिटेड द्वारा समर्थन संदेहजनक है, यह नोट किया गया है कि इस तरह की दलीलें निराधार हैं, चूंकि समर्थक कंपनी से एक समर्थन पत्र प्राधिकारी के रिकार्ड में उपलब्ध है।

34. जहाँ तक इस विवाद का संबंध है कि यह संदेहजनक है कि याचिकाकर्ता का आऊटपुट कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात नहीं है, यह नोट किया जाता है कि एडी जांच में इस तरह के अनुमान कोई ठोस सबूत नहीं होते हैं और ऊपर बताए गए तथ्य से पता चलता है कि आवेदन वर्तमान आवश्यकता को पूरा करता है।

## ब. गोपनीयता

### ब.1 निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध

35. प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक मानी गई सूचना की गोपनीयता और प्रकटीकरण के संबंध में निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

- i. याचिकाकर्ता ने याचिका में अत्यधिक गोपनीयता बरती है, जो विश्व व्यापार संगठन एडीए के अनुच्छेद 6.5 और एडी नियमों के नियम 7 (2) का उल्लंघन है।
- ii. प्रोफार्मा IVA में निर्धारित मापदंडों को या तो गोपनीय, सरसरे तौर पर (स्केची) रखा गया है या उन्हें उपलब्ध नहीं करवाया गया है, यहां तक कि उन्हें सूचीबद्ध भी नहीं किया गया है और आकस्मिक लिंक के विक्षेपण के साथ ही यह पता लगाने में इस तरह की जानकारी महत्वपूर्ण होती है कि क्या घरेलू उद्योग को कोई क्षति का सामना करना पड़ा है।
- iii. नाममात्र की कीमत के भुगतान पर कारपोरेट मामला मंत्रालय ("एमसीए") की वेबसाइट पर याचिका दायर करने वाली कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इसे भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस तरह के आंकड़ों के अभाव में, प्रतिवादी, याचिका दायर करने वाली कंपनियों के क्षति के आरोपों को प्रभावी ढंग से गलत साबित नहीं कर सकता है।
- iv. ऑटोमोटिव एक्सेल लिमिटेड द्वारा समर्थन पत्र में विवरण को संपादित कर लिया गया है और विवरण को भी सूचीबद्ध रूप में भी उपलब्ध नहीं करवाया गया है जबकि इसी तरह का विवरण, याचिका दायर करने वाली कंपनियों को उपलब्ध करवाया गया है।

### ब.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

36. प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक मानी गई सूचना की गोपनीयता और प्रकटीकरण के संबंध में घरेलू उद्योगों द्वारा की गई कुछ प्रस्तुतियाँ इस प्रकार हैं:

- i. विरोधी पक्षों द्वारा अनुरोध में अत्यधिक गोपनीयता अपनायी गयी थी। हालांकि हमें यकीन नहीं है कि केकेटीसी का कौन सा आईक्यूआर सही है, रिकॉर्ड में दोनों आईक्यूआर के साथ ही कंपनी द्वारा दायर प्रारंभिक क्षति के लिए बिना किसी औचित्य के अत्यधिक गोपनीयता का उपयोग किया गया है।
- ii. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में सभी तरह की सूचना का खुलासा किया है और एक सार्थक सारांश, जहां लागू हो, उपलब्ध कराया है। लेकिन केकेटीसी ने आयात की मात्रा का वास्तविक विवरण उपलब्ध नहीं कराया है और यहाँ तक कि उनके आयात कीमतों के संबंध में भी सार उपलब्ध नहीं कराया है। इस प्रकार, केकेटीसी ने याचिकाकर्ता पर निराधार अत्यधिक गोपनीयता के आरोप का सहारा लिया है जबकि इस मामले के तथ्य यह हैं कि केकेटीसी ने याचिकाकर्ता को मौलिक सूचना भी उपलब्ध नहीं कराई है।
- iii. केकेटीसी ने आईक्यूआर की अपने पहले सेट में कुछ सूचना का खुलासा किया था और इसी को आईक्यूआर की अपने दूसरी सेट में गोपनीय माना था। यह केकेटीसी द्वारा गोपनीयता के तर्क के खोखलेपन को दर्शाता है। केकेटीसी को उनके आयात के बारे में वास्तविक सूचना का खुलासा करना चाहिए ताकि हमारे द्वारा सार्थक खंडन उपलब्ध कराया जा सके। इस प्रकार, यह कहा किया जाता है कि केकेटीसी ने सार्थक टिप्पणी देने से याचिकाकर्ता को वंचित करते हुए अत्यधिक गोपनीयता का सहारा लिया है जो एडी नियमावली में उपलब्ध गोपनीयता प्रावधानों के पूरी तरह से खिलाफ है।

- iv. केकेटीसी ने कोई भी न्यायोचित कारण दिए बिना काफी जानकारी गोपनीय रखी है। यह नियमों के तहत अनुमत्य नहीं है, जैसा कि उपरोक्त प्रावधानों से देखा जा सकता है। ऐसी कुछ सूचनाएँ, जिन्हें गोपनीयता की आड़ में रोका गया है, के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:
- क. सम्बद्ध देश से आयात की कुल मात्रा के बारे में सूचना
- ख. सम्बद्ध देश से आयात की औसत कीमत
- ग. धारक कंपनी का विवरण
- घ. आयातित उत्पाद के उपयोग संबंधी मात्रात्मक सूचना
- ड. हानि-लाभ खाता उपलब्ध नहीं कराया गया, ना ही हानि-लाभ के कंपनी रजिस्ट्रार का संस्करण उपलब्ध कराया गया है, आदि
- च. प्राथमिक क्षति प्रस्तुति के अनुबंध 1 के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा एक्सेल/सेंट्रल बीम के कथित आयात संबंधी सूचना हमें ऐसे निराधार आरोपों के लिए कोई सार्थक टिप्पणी करने से रोकती है।
- छ. अनुबंध 3 और 3 ए भी कुछ नहीं है बल्कि कुछ कीमत की तुलना है इसे भी हमारे सार्थक खंडन पेश करने के अधिकार को रोकते हुए गोपनीय रखा गया है।
- v. हम यह कहते हैं कि सूचना की उपर्युक्त सूची, यद्यपि पूरी नहीं है, फिर भी कुछ जानकारी देती है जिसे केकेटीसी द्वारा गोपनीय नहीं रखा जाना था। जबकि गैर-गोपनीय सार प्रस्तुत करने के लिए गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु पक्षों को नियमों की आवश्यकता होती है, केकेटीसी ने उनके लिए सुविधाजनक पद्धति का सहारा लिया और वास्तव में उनके द्वारा किए गए पाटित आयात के संबंध में वास्तविक स्थिति का आकलन करने से याचिकाकर्ता को रोका गया है। केकेटीसी द्वारा अपनाई गई अत्यधिक गोपनीयता भी चीन से कुछ लोहा या स्टील फास्टनर्स के संबंध में यूरोपीय कम्युनिटिज-एंटी डंपिंग मीजर्स (डब्ल्यूटी/डीएस397/एबी/आर दिनांक 15 जुलाई, 2011) में अपीलीय निकाय के निष्कर्षों का उल्लंघन है, जिसमें अपीलीय निकाय ने गोपनीयता के विषय में पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद 6.5 और अनुच्छेद 6.5.1 की व्याख्या की है।
- vi. भागीदार निर्यातकों द्वारा अत्यधिक गोपनीयता को भी अपनाया गया था और ईक्यू रिस्पांस तथा एमईटी रिस्पांस में गोपनीयता वाली सूचना का कोई भी उपयुक्त सार आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है। बहुत ही बुनियादी जानकारी जैसे कंपनी का पूरा कानूनी फॉर्म, शेयरधारकों के नाम, पीयूसी में शामिल पक्षों से संबंधित नाम, संपर्क विवरण आदि सभी को तब भी गोपनीय रखा गया जबकि कंपनी एमईटी स्थिति का दावा कर रही है। यह अनुमत्य नहीं है।

### अ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

37. सूचना की गोपनीयता / प्रकटीकरण के संबंध में इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने जाने की जांच की जाती है तथा निम्नानुसार समाधान किया जाता है:

38. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है-

गोपनीय सूचना- (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियाँ या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

39. गोपनीयता दावे की पर्याप्ता के संबंध में गोपनीयता के आधार पर इच्छुक पक्षों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता दावा स्वीकार कर लिया है, जहां आवश्यकता है और इस तरह की सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य इच्छुक पक्षों के सामने खुलासा नहीं किया गया है। जहाँ भी संभव हो, गोपनीयता के आधार पर सूचना उपलब्ध कराने

वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना के लिए पर्याप्त गैर गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फ़ाइल के रूप में विभिन्न इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत सबूतों का गैर गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराया था।

40. जहाँ तक इस विवाद का संबंध है कि नाममात्र की कीमत के भुगतान पर कारपोरेट मामला मंत्रालय ("एमसीए") की वेबसाइट पर याचिका दायर करने वाली कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इसे भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस तरह के आंकड़ों के अभाव में, प्रतिवादी याचिका दायर करने वाली कंपनियों के क्षति के आरोपों को प्रभावी ढंग से गलत साबित नहीं कर सकता है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि आवेदक की वार्षिक रिपोर्टें सार्वजनिक फ़ाइल में उपलब्ध हैं और यह आवेदक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है जैसा कि आवेदन में कहा गया है। इस प्रकार, विवाद का कोई औचित्य नहीं है।

### **च. विविध मुद्दे**

#### **च.1 निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध**

41. प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक मानी गई सूचना के संबंध में निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए कुछ निवेदन इस प्रकार हैं:

- i. एडी नियमावली के नियम 5(3) (ख) के अनुसार सबूतों की पर्याप्तता के प्रति स्वयं संतुष्ट होने पर ही नामित प्राधिकारी पर कोई एडी जांच शुरू की जा सकती है। हालांकि, वर्तमान मामले में आवेदक ने जांच शुरू करने के लिए कोई भी आधार स्थापित नहीं किया था और याचिका में गंभीर कमियाँ हैं, जिसने विरोधी पक्षों को उनके कथन तैयार करने में पंगु बना दिया।
- ii. अद्यतन याचिका में केवल अनुबंध को अद्यतन किया गया है। आंकड़ों और क्षति मापदंडों के विश्लेषण में कोई बदलाव नहीं है।
- iii. इस संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए आईबीएस लेनदेन-वार कच्चे आयात के आकड़ों का कैसे उपयोग किया जा रहा है। याचिकाकर्ता द्वारा आईबीएस लेनदेन-वार कच्चे आयात के आकड़े उपलब्ध कराने के साथ साथ एमएस-एक्सेल प्रारूप में प्रतिवादी को आयात आकड़े छाँट कर देने चाहिए। प्राधिकारी को यह भी अनुरोध किया गया था कि याचिकाकर्ता को व्याख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया जाए कि उसने कैसे कच्चे आयात आंकड़ों को छाँटा, चूँकि यह जाँच अवधि और क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान भारत में सम्बद्ध वस्तु के आयात के ट्रेड के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है।
- iv. याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि जब भी आयात आंकड़ों में किलोग्राम के मामले में इकाई (केजी) उपलब्ध नहीं होती है, याचिकाकर्ता ने पीयूसी के मानक वजन का उपयोग कर वजन के समान में इसे बदल दिया। हालांकि, मानक वजन क्या है और कैसे वे इस पर पहुंचे इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- v. याचिका में सकल भूल घोषणाएं/गोपनीयता है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि केंद्रीय या एक्सेल बीम सम्बद्ध वस्तु का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उत्पाद लाइन के पूरक के रूप में इस तरह का कोई उत्पाद न तो खरीदा गया है या न ही आयात किया गया है। हालांकि, यह सूचना सही नहीं है। अनेक अवसरों पर याचिकाकर्ता ने चीन पीआर से केंद्रीय/एक्सेल बीम आयात किया है। इसे विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त आयात अभिलेखों से स्पष्ट रूप से देखा गया है।
- vi. यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, एक टाटा उद्यम, की भारत में दो संबंधित कंपनियाँ अर्थात् टाटा मोटर्स लिमिटेड और टाटा इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड हैं, जो संबंधित उत्पाद से जुड़े कार्य कर रहीं हैं। इन पक्षकारों ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया था या आवेदन में शामिल भी नहीं किए थे। यह घरेलू उद्योग श्रृंखला का उल्लंघन है जैसा कि निर्यातकों के मामले में लागू होता है।
- vii. ऐसे मामले में जहाँ निर्यातक संबद्ध देश में अपने संबंधित उत्पादक की प्रश्रावली का जवाब दाखिल नहीं करता, भले ही उसने संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है, वहाँ डीजीएडी ने पिछले कई मामलों में भागीदार निर्यातक के उत्तर को नकार दिया है। वर्तमान जांच के मामले में भी यही नियम लागू किया जाना चाहिए।
- viii. यह कहा गया है कि यॉर्क का चीन पीआर में संबद्ध वस्तु के संबंध में दो संबंधित उत्पादक हैं। यॉर्क द्वारा मात्र दिया गया बयान कि चीन में संबंधित कंपनियाँ अर्थात् क्वांगडो वाईटीई स्पेशल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड और यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (शंघाई) कम्पनी लिमिटेड, चीन ने संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है, पर्याप्त नहीं है। इन संबंधित कंपनियों को खुद प्रश्रावली का जवाब दायर करना चाहिए या यह स्थापित करने के लिए है कि इन कंपनियों ने भारत में संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है, अपनी बिक्री का ब्यौरा देना चाहिए।

#### **च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया निवेदन**

42. विविध मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माने गए कुछ आवेदन इस प्रकार हैं:

- i. कुछ इच्छुक पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया और बयान दिए, हालांकि, लिखित में अपने मौखिक बयान पुनः प्रस्तुत नहीं किए। हम प्राधिकारी से ऐसे मौखिक बयानों, जिसे नियम 6 (6) के मद्देनजर, जो यह कहता है कि इस तरह की मौखिक सूचना को



नामित प्राधिकारी द्वारा तभी ध्यान में रखा जाएगा जब इसे तत्पश्चात् लिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किया जाता है, को वर्तमान जांच के लिए लिखित रूप में पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए इस पर विचार नहीं करने का अनुरोध करते हैं।

- ii. किंग कावेरी ट्रेडिंग कंपनी (कई जगह किंग कावेरी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में लिखा गया है) ने विभिन्न कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से कई आईक्यूआर दायर किए हैं और कोई पुष्टि नहीं है कि कौनसा सही आईक्यूआर है, जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए।
- iii. यहाँ तर्क करने का आधार नहीं है कि याचिकाकर्ता को कच्चे के साथ साथ एक्सेल प्रारूप में छाँटे गए लेनदेन-वार आकड़े उपलब्ध कराने चाहिए। आवश्यकता सिर्फ आयात की मात्रा और कीमत का सार देने की है और शेष तर्क का कोई कानूनी आधार नहीं है। इस तरह की कानूनी स्थिति होते हुए भी, जो प्राधिकारी के विभिन्न निष्कर्षों को परिलक्षित करता है, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से पीयूसी और गैर पीयूसी मद की स्पष्ट पहचान के द्वारा याचिका के अनुबंध 1.4 में लेनदेन-वार आयात आकड़ा उपलब्ध कराया है। इसके अलावा भी तर्क का कोई आधार नहीं है कि रूपांतरण का मानक वजन उपलब्ध नहीं कराया है। वास्तव में, लेनदेन-वार आकड़ों में दोनों खंडों की संख्या और लिया गया वजन, जहाँ अर्थ लागू होता है, शामिल है जिससे मानक वजन का भी खुलासा होता है।
- iv. हम अपने निवेदन को पुनः दोहराते हैं कि माइनर घटकों की कुछ खरीद कंपनी द्वारा की गई थी और उस खरीद को हमारी कच्चे सामग्री की खरीद के रिकॉर्ड में दिखाया गया है। यह भी उल्लेख है कि Zaubacom के अनुसार केकेटीसी द्वारा आपूर्ति किया गया आयात आकड़ा यह नहीं दर्शाता है कि यॉर्क ने चीन पीआर से सेंट्रल एक्सेल/बीम का आयात किया था। किसी भी मामले में केकेटीसी इस संलग्न अनुलग्नक 1 में दिखाया गया आयात, स्पष्टतः माइनर घटक हैं।

### **च.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच**

43. विविध मुद्दों के संबंध में इच्छुक पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माने गए विभिन्न आवेदनों की जांच और समाधान इस प्रकार हैं:

- i. जहाँ तक इस विवाद का संबंध है कि वर्तमान मामले में आवेदक ने जांच शुरू करने संबंधी कोई आधार स्थापित नहीं किया है और याचिका में गंभीर कमियाँ हैं जिन्होंने प्रतिवादी पक्ष को अपने बयान प्रस्तुत करने में पंगु बनाया है, प्राधिकारी यह नोट करता है कि अच्छी तरह से प्रलेखित आवेदन के आधार पर और प्रथम दृष्टया कथित पाटन और क्षति के बीच घरेलू उद्योग और आकस्मिक लिक के संबंध में कथित पाटन और क्षति से संबंधित सूचना की पर्याप्तता और सटीकता के प्रति संतुष्ट होने के बाद ही जांच शुरू की गई थी।
- ii. जहाँ तक इस विवाद का संबंध है कि अद्यतन याचिका में केवल अनुबंध को अद्यतन किया गया है और क्षति मापदंडों के संबंध में आंकड़ों तथा विश्लेषण में कोई बदलाव नहीं है, यह बताया गया है कि प्राधिकारी द्वारा इसे और अधिक हाल ही का बनाने के लिए जाँच अवधि को बढ़ा दिया गया था तथा विस्तारित जाँच अवधि से संबंधित पाटन और क्षति सूचना सभी इच्छुक पक्ष को उपलब्ध करवाई गई है।
- iii. विवाद के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए आईबीएस लेनदेन-वार कच्चे आयात आकड़ों का कैसे उपयोग किया जा रहा है। याचिकाकर्ता द्वारा आईबीएस लेनदेन-वार कच्चा आयात आकड़ा उपलब्ध कराने के साथ साथ एमएस-एक्सेल प्रारूप में प्रतिवादी को आयात आकड़ा छाँट कर देना चाहिए। यह नोट किया जाता है कि एमएस-एक्सेल प्रारूप सहित खास प्रारूप में आयात आकड़ा उपलब्ध कराने हेतु नियमों के तहत कोई आवश्यकता नहीं है। कार्यप्रणाली के संबंध में, यह देखा गया है कि आवेदन का भाग-1 इस संबंध में स्वतः स्पष्ट है कि कैसे आयात सूचना उपलब्ध कराई गई है।
- iv. जहाँ तक इस विवाद का संबंध है कि याचिकाकर्ता ने मानक वजन का उल्लेख नहीं किया है। यह उल्लेखनीय है कि आयात लेनदेन दिया गया है। यह नोट किया जाता है कि जाँच अवधि में 23075 एक्सेलों के कुल आयात में से 22040 को पहले ही किलोग्राम में सूचित किया गया है और केवल 1,035 किलोग्राम को संख्या से बदला गया था। उन्हें प्रति एक्सेल 353 किलोग्राम के मानक वजन में परिवर्तित किया गया था।
- v. जहाँ तक इस विवाद का संबंध है कि याचिका में सकल गलत घोषणाएं/सूचना छिपाई गई है। अनेक अवसरों पर याचिकाकर्ता ने चीन पीआर से केंद्रीय/एक्सेल बीम आयात किया है। इसे विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त आयात अभिलेखों से स्पष्ट रूप से देखा गया है। प्राधिकारी नोट करता है कि आवेदक द्वारा दलीलों का इनकार किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि विरोधी पक्ष द्वारा उपलब्ध कराए गए आयात सबूत यह नहीं दिखाते हैं कि इस तरह के आयात आवेदक द्वारा किए जाते हैं या वे सेंट्रल/एक्सेल बीम का आयात करते हैं।
- vi. जहाँ तक इस विवाद का संबंध है कि यॉर्क ट्रांसपोर्ट इन्फ्रिमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, एक टाटा उद्यम, की भारत में दो संबंधित कंपनियों अर्थात् टाटा मोटर्स लिमिटेड और टाटा इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड हैं, जो संबंधित उत्पाद से जुड़े कार्य कर रही हैं। इन पक्षकारों ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया था या आवेदन में शामिल भी नहीं किया था। यह घरेलू उद्योग श्रृंखला का उल्लंघन है जैसा कि निर्यातकों के मामले में लागू होता है। यह नोट किया जाता है कि संबंधित नियमों के अनुसार आवेदन आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करता है।

- vii. जहाँ तक इस विवाद का संबंध है कि ऐसे मामले में जहाँ निर्यातक संबद्ध देश में अपने संबंधित उत्पादक की प्रश्रावली जवाब दाखिल नहीं करता, भले ही उसने संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है, डीजीएडी ने पिछले कई मामलों में भागीदार निर्यातक के उत्तर को नकार दिया है। वर्तमान जांच के मामले में भी यही नियम लागू किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करता है कि ऐसी तुलना का कोई तथ्यात्मक या कानूनी आधार नहीं है। पाटनरोधी जाँच में आवश्यकता को स्थापित करने तथा निर्यात कीमत की विश्वसनीयता स्थापित करने की आवश्यकता को समान नहीं बनाया जा सकता है और नियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार मानदंड को अलग करना चाहिए।
- viii. जहाँ तक इस विवाद का संबंध है कियॉर्क के चीन पीआर में संबद्ध वस्तु के दो संबंधित उत्पादक हैं। यॉर्क द्वारा मात्र दिया गया बयान कि चीन में संबंधित कंपनियाँ अर्थात् क्वांगडो वाईटीई स्पेशल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड और यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (शंघाई) कम्पनी लिमिटेड, चीन ने संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है, पर्याप्त नहीं है। इन संबंधित कंपनियों को खुद प्रश्रावली का जवाब दायर करना चाहिए या यह स्थापित करने के लिए है कि इन कंपनियों ने भारत में संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है, अपनी बिक्री का ब्यौरा देना चाहिए। प्राधिकारी नोट करता है कि इस तरह की दलीलों का कोई कानूनी आधार नहीं है और प्रतिवादी इच्छुक पक्षकार ने ऊपर उल्लिखित संबंधित उत्पादकों से भारत के लिए संबद्ध वस्तु के निर्यात को दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है।
- ix. जहाँ तक तर्क का संबंध है, कुछ इच्छुक पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया और बयान दिए, हालांकि, लिखित में अपने मौखिक बयान पुनः प्रस्तुत नहीं किए। यह नोट किया जाता है कि नियम 6 (6) बहुत ही स्पष्ट है, जो यह कहता है कि इस तरह की मौखिक सूचना को नामित प्राधिकारी द्वारा तभी ध्यान में रखा जाएगा जब इसे तत्पश्चात लिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किया जाता है।
- x. जहाँ तक इस विवाद का संबंध है किकेकेटीसी ने विभिन्न कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से कई आईक्यूआर दायर किया है और कोई पुष्टि नहीं है कि कौनसा सही आईक्यूआर है, जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करता है कि कंपनी ने इस संबंध में एक नए प्राधिकार पत्र के साथ एक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया है।

#### **छ. बाजार अर्थव्यवस्था सुधार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और डंपिंग मार्जिन**

44. चीन पीआर से तीन प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों, गुआंगडोंग फुवा इंजीनियरिंग मेनुफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड और गुआंगडोंग फुवा हेवी इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ने पाटन रोधी नियमों के अनुसार चीन पीआर की गैर-बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति के अनुमान को गलत साबित करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था सुधार (एमईटी) प्रश्रावली दायर की थी। तथापि सत्यापन दौर से पहले दोनों उत्पादकों/निर्यातकों ने बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति के लिए अपने दावे को वापस ले लिया। इस प्रकार, चीन पीआर से कोई उत्पादक/निर्यातक ने प्रभावी ढंग से एमईटी का दावा नहीं किया है।

#### **छ.1 निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन**

45. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/ अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और डंपिंग मार्जिन के विषय में किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माने गए आवेदन इस प्रकार हैं;

- आवेदक द्वारा सामान्य मूल्य प्रति किलोग्राम अमेरिकी डॉलर 2- 4 दिया गया है। यह सही नहीं लगता है और सामान्य मूल्य को एक निश्चित संख्या होना चाहिए, एक सीमा नहीं होना चाहिए। सामान्य मूल्य सीमाबद्ध भी नहीं होता है तथा इसकी भिन्नता 100 % है।
- आवेदक ने सामान्य मूल्य में लाभ और व्याज को गोपनीय रखा था। प्राधिकारी को उन आंखड़ों का खुलासा करना चाहिए और आवेदन में प्राधिकारी के पास इस आकड़े के संबंध में गोपनीयता की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
- सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना का स्तर अनुचित है।
- आवेदक द्वारा डंपिंग मार्जिन की गणना गलत है।
- कृपया गुआंगडोंग फुवा इंजीनियरिंग मेन्यूफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, और गुआंगडोंग फुवा हेवी इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर के लिए शुल्क की अलग दर लगायी जाए, चूंकि यह भारत में संबद्ध वस्तुओं का पूरी तरह से सहयोगी उत्पादक/निर्यातक है।
- याचिका में सामान्य मूल्य प्राप्त करने की कोई पद्धति उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके अलावा, सामान्य मूल्य की गणना करने हेतु प्रयुक्त कच्चे माल की लागत, खपत मानदंड जिन्हें आसानी से बताया जा सकता है, जैसे कुछ तथ्य याचिका में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
- निर्यात मूल्य में किए गए समायोजन का कोई सबूत जैसे समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बंदरगाह व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा व्यय, बैंक शुल्क का उल्लेख याचिका नहीं किया गया है।
- सामान्य मूल्य की गणना के उद्देश्य से तीसरे देश में घरेलू कीमतों का पता लगाने हेतु याचिकाकर्ता द्वारा किए गए प्रयासों का जिक्र नहीं है।

- ix. चीन पीआर के लिए सामान्य मूल्य निर्धारण एडी नियमावली के अनुलग्नक-1 के पैरा 7 के तहत अपेक्षाओं का उल्लंघन है चूंकि सामान्य मूल्य की गणना भारत में किए गए भुगतान या देय कीमतों के आधार पर की गई है, जिसे प्राथमिक विधि के बजाय अंतिम उपाय के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।
- x. उपलब्ध विभिन्न निर्णय और फैसलों से यह स्पष्ट है कि गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से निर्यात के मामले में, सामान्य मूल्य पर पहुंचने की एकमात्र सही पद्धति है- सामान्य नियम अर्थात् तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत या निर्मित मूल्य अथवा जांच करने वाले देश सहित अन्य देश के लिए इस तरह के किसी तीसरे देश की कीमत लागू करना। केवल उन मामलों में, जहां प्राधिकारी सामान्य नियम लागू करने में असमर्थ है, कुछ अन्य उचित आधार का उपयोग करने के विकल्प का भी सहारा लिया जा सकता है।
- xi. "चूंकि यह आवेदक के लिए यथोचित उपलब्ध है" का मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता को कोई सबूत नहीं देने की स्वतंत्रता है। प्राधिकारी ने याचिका के साथ प्रस्तुत साक्ष्य की पर्याप्तता की जांच नहीं कर विश्व व्यापार संगठन एडीए के अनुच्छेद 5.3 का उल्लंघन किया है।

## **छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन**

46. घरेलू उद्योगों द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और डंपिंग मार्जिन के विषय में किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माने गए निवेदन इस प्रकार हैं;

क. चीन पीआर को वर्तमान जांच और सामान्य मूल्य के उद्देश्य से गैर बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में माना जाना चाहिए, ऐसे मामले में अनुबंध-1 पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार चीनी उत्पादकों का निर्धारण किया जाना चाहिए।

ख. चीन पीआर को एक एनएमई देश के रूप में मानकर विभिन्न पाटनरोधी जांच के हिस्से के रूप में दोनों भारतीय प्राधिकारी और अन्य देशों जैसे यूरोपीय संघ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि द्वारा हाल ही में संपन्न जांच सहित कई जांचों में चीनी उत्पादकों ने एमईटी स्थिति से इनकार कर दिया है।

ग. इसके अलावा, हम प्रतिवादी निर्यातकों के दावे पर यह आपत्ति करते हैं कि उन्हें अलग-अलग मार्जिन देना चाहिए। उपर्युक्त के स्थान पर उत्पादकों को एक इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए।

घ. प्रतिवादी निर्यातक ने ईक्यूआर के पृष्ठ संख्या 2 पर प्रस्तुत किया है कि जाँच अवधि के दौरान इनपुट संबंधी वैट वापसी दर 15% थी। प्राधिकारी के नियमित कार्याभ्यास के अनुसार निर्यात पर दावा नहीं किए गए वैट का समायोजन, निर्यातक के निर्यात मूल्य से किया जाना चाहिए। इसके अलावा, वास्तविक सबूतों के अनुसार वैट वापसी की दर को लिया जा सकता है।

ङ. प्राधिकारी के लिए उपलब्ध कराई गई सूचना निर्यातक के द्वारा वहन की गई वारंटी लागतों को दर्शाती है। निवल निर्यात मूल्य निकालते समय यह वारंटी लागत को समायोजित करने के लिए तुरंत आवश्यक हो जाता है।

च. सामान्य कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के दावों के संबंध में यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक ने पाटनरोधी नियमावली के विनिर्दिष्ट उपलब्ध सूचना एवं अनुज्ञेय तरीकों के अनुसार तथा नियम के प्रासंगिक अनुबंध के अनुसार सामान्य कीमत और पाटन मार्जिन प्रस्तुत किया। ऐसी गणनाओं के ब्यौरे तथा एन.सी.वी. आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए जाते हैं जो स्पष्ट हैं और उसमें सभी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित हैं। अतः हितवद्ध पक्षकारों की गलतफहमियों और दावों का कोई आधार नहीं है।

## **छ.3 प्राधिकारी के द्वारा जांच**

47. इस दावे के बारे में कि चीन गणराज्य के लिए निर्धारित सामान्य कीमत ए.डी. नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के तहत अपेक्षाओं का उल्लंघन है क्योंकि सामान्य कीमत की गणना भारत में भुगतान अथवा भारत में देय कीमतों के आधार पर की गई है, जिसका प्रमुख तरीके की अपेक्षा एक अंतिम सहारे के रूप में उपयोग करना होगा। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने सामान्य कीमत और निर्यात एवं पाटन मार्जिन की गणना करने की कार्रवाई ए.डी.डी. नियमावली के अधीन शुरू की है और न कि अन्यथा, तथा अपनाई गई पद्धति और तर्क स्वतः स्पष्ट है।

### **क) सामान्य कीमत का निर्धारण**

48. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन गणराज्य के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 6 के अनुसार चीन गणराज्य के मामले में सामान्य कीमत का निर्धारण करने हेतु बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति के तहत प्रचालन करने का दावा नहीं किया है। इस परिस्थिति में, प्राधिकारी चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए नियमावली के अनुबंध-1 का पैरा 8 लागू करने की स्थिति में नहीं है तथा प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।

49. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ-7 में निम्नानुसार प्रावधान है:

“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिसमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्रुत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी अनुचित विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।”

50. इन नियमों के अनुसार, चीन में सामान्य कीमत का निम्नलिखित में से किसी एक के आधार पर निर्धारण किया जा सकता है:

क) किसी तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत के आधार पर; अथवा

ख) किसी तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में निर्मित कीमत; अथवा

ग) ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत।

घ) यदि सामान्य कीमत के बारे में ऊपर बताए गए विकल्पों के आधार पर निर्धारण नहीं किया जा सकता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान किए अथवा देय मूल्य सहित किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य कीमत का निर्धारण कर सकता है।

51. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि तीसरे देश की लागत और कीमतों के आधार पर सामान्य कीमत का निर्धारण करने के लिए घरेलू बिक्री अथवा तीसरे देश की निर्यात बिक्री के पूर्ण और विस्तृत आंकड़े, तथा तीसरे देश में ऐसे उत्पादकों के उत्पादन और सहयोग करने की लागत संबंधी आंकड़ों की आवश्यकता होती है। इन बाजारों में प्रचलित मूल्यों और लागतों के संबंध में ऐसी कोई सूचना न तो आवेदक के द्वारा अथवा प्रतिवादी निर्यातकों के द्वारा उपलब्ध कराई गई है और न ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के मूल्यांकन किया जा सका है और न ही प्रतिवादी चीनी कंपनियों ने इस अवस्था में तीसरे देश की किसी उचित बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में कोई दावा किया है। प्राधिकारी किसी अन्य उचित आधार पर आधारित सामान्य कीमत के बारे में कार्यवाई करते हैं।

52. प्राधिकारी ने ए.डी. नियम के अनुबंध-1 के पैरा 7 के द्वितीय परन्तुक के अनुसार, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर चीन गणराज्य के लिए सामान्य कीमत का निर्धारण किया है। तदनुसार, कारखाने से बाहर विचाराधीन उत्पाद की सामान्य कीमत की बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागतों एवं उचित लाभों के साथ-साथ घरेलू उद्योग की अधिकतम उत्पादन लागत के आधार पर उत्पादन की निर्मित लागतों के अनुसार निर्धारण किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य अमरीकी डालर \*\*\*/कि.ग्रा. हैं।

#### ख) निर्यात मूल्य का निर्धारण

##### i. मै. गोंगडोंग एफयूडब्ल्यू इंजीनियरिंग मैनुफैक्चरिंग कं. लि.

53. चीन गणराज्य के उत्पादक सह निर्यातक ई.क्यू. के प्रत्युत्तर में, मै. गोंगडोंग एफयूडब्ल्यू इंजीनियरिंग मैनुफैक्चरिंग कं. लि. ने भारत के लिए \*\*\*\* अमेरिकी डॉलर के कुल सीआईएफ कीमत के पी.यू.सी. के (\*\*\*) एम.टी.) \*\*\*\* नगरों का निर्यात करने का दावा किया है। प्राधिकारी ने फैक्ट्री से बाहर स्तर पर निवल निर्यात मूल्य प्राप्त करने के लिए वैट रिफंड के प्रभाव के अलावा अपने ई.क्यू. प्रत्युत्तर ने निर्यातक के द्वारा दावा किए गए समुद्री माल-भाड़ा, समुद्री बीमा, रख-रखाव प्रभार, अन्तर्देशीय भाड़ा, क्रेडिट लागत, बैंक प्रभारों के बारे में समायोजन किया है। तदनुसार, मै. गोंगडोंग एफयूडब्ल्यू इंजीनियरिंग मैनुफैक्चरिंग कं. लि., चीन गणराज्य के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात मूल्य के बारे में प्रति कि.ग्रा. \*\*\* अमेरिकी डॉलर के रूप में निर्धारण किया गया है।

##### ii. गोंगडोंग एफयूडब्ल्यू हैवी इंडस्ट्रीज कं. लि., चीन गणराज्य

54. चीन गणराज्य के उत्पादक सह निर्यातक ई.क्यू. के प्रत्युत्तर में, गोंगडोंग एफयूडब्ल्यू हैवी इंडस्ट्रीज कं. लि. ने भारत के लिए \*\*\*\* अमेरिकी डॉलर के कुल सीआईएफ कीमत के पी.यू.सी. के (\*\*\*) एम.टी.) \*\*\*\* नगरों का निर्यात करने का दावा किया है। प्राधिकारी ने फैक्ट्री से बाहर स्तर पर निवल निर्यात मूल्य प्राप्त करने के लिए वैट रिफंड के प्रभाव के अलावा अपने ई.क्यू. प्रत्युत्तर ने निर्यातक के द्वारा दावा किए गए समुद्री माल-भाड़ा, समुद्री बीमा, रख-रखाव प्रभार, अन्तर्देशीय भाड़ा, क्रेडिट लागत,

बैंक प्रभारों के बारे में समायोजन किया है। तदनुसार, गोंगडोंग एफयूडब्ल्यूए हैवी इंडस्ट्रीज कं. लि., चीन गणराज्य के लिए फैक्ट्री के बाहर स्तर पर निवल निर्यात मूल्य के बारे में प्रति कि.ग्रा. \*\*\* अमेरिकी डॉलर के रूप में निर्धारण किया गया है।

### iii. सानडोंग जिनसेंग एक्सल मैनुफैक्चरिंग कं. लि.

55. ई.क्यू.आर. में चीन गणराज्य के उत्पादक सह निर्यातक सानडोंग जिनसेंग एक्सल मैनुफैक्चरिंग कं. लि. ने भारत के लिए \*\*\* अमेरिकी डॉलर के कुल एफओबी कीमत के पीयूसी के \*\*\* नगों (\*\*\* एमटी) का निर्यात करने का दावा किया है। प्राधिकारी ने फैक्ट्री से बाहर स्तर पर निवल निर्यात मूल्य प्राप्त करने के लिए वैट रिफंड के प्रभाव के अलावा अपने ई.क्यू. प्रत्युत्तर ने निर्यातक के द्वारा दावा किए गए अन्तर्देशीय भाड़ा, क्रेडिट लागत, बैंक प्रभारों के बारे में समायोजन किया है। तदनुसार, मै. शांगडोंग जिनशेंक एक्सल मैनुफैक्चरिंग कं. लि., चीन गणराज्य के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात मूल्य का निर्धारण, प्रति कि.ग्रा. \*\*\* अमेरिकी डॉलर/कि.ग्रा. के रूप में किया गया है।

### iv. चीन गणराज्य के सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक

56. चीन गणराज्य के नान को-ऑपरेटिव उत्पादक/निर्यातक के बारे में, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उनकी निवल निर्यात मूल्य निर्धारित किया है। तदनुसार, चीन गणराज्य के नान को-ऑपरेटिव निर्यातकों के बारे में निवल निर्यात \*\*\* अमेरिकी डॉलर/कि.ग्रा. निर्धारित किया है।

### ग. पाटन मार्जिन का निर्धारण

57. यथा उपरोक्त निर्धारित सामान्य कीमत और निर्यात मूल्य के आधार पर चीन गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन प्राधिकारी के द्वारा निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

विवरण	सामान कीमत अमेरिकी डॉलर/कि.ग्रा.	निर्यात मूल्य अमेरिकी डॉलर/कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन अमेरिकी डॉलर/कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन रेंज %
मैसर्स गोंगडोंग एफयूडब्ल्यूए इंजीनियरिंग मैनुफैक्चरिंग कं. लि. (उत्पादक एवं निर्यातक)	***	***	***	30-35
मैसर्स गोंगडोंग एफयूडब्ल्यूए हैवी इंडस्ट्रीज कं. लि. (उत्पादक एवं निर्यातक)	***	***	***	
सानडोंग जिनसेंग एक्सल मैनुफैक्चरिंग कं. लि.	***	***	***	35-40
सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	55-60

### छ. क्षति निर्धारण के लिए पद्धति तथा क्षति और कारणात्मक संबंध होने की जांच

#### i. क्षति जांच

#### छ.1 निर्यातकों, आयातकर्ताओं, प्रयोक्ताओं एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए निवेदन

58. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकर्ताओं/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए क्षति निवेदन निम्नलिखित हैं:

- आवेदक ने आईबीआईएस आंकड़ों पर विश्वास किया है जिसमें सभी पक्षों के शामिल न होने का दावा है तथा जिसमें प्राधिकारी पर डीजीसीआईएंडएस के अनुसार आयातों के सही एवं पूर्ण आंकड़े प्राप्त करने की जिम्मेदारी दी जाती है। आवेदक के द्वारा प्रदान किए गए आयात संबंधी आंकड़े विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं।
- घरेलू उद्योग को कोई भारी क्षति नहीं हुई है। वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के दृष्टिगत जो लाभ दर्शाती है, क्षति दर्शाने वाले कुछ मूल्य पैरामीटरों की निराशाजनक तस्वीर सही नहीं है। अतः कोई क्षति नहीं हुई है।

- iii. इस मामले में क्षमता उपयोग शब्द की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि कोई भी वास्तविक विनिर्माण कार्यकलाप नहीं है।
- iv. वर्तमान मामले में कीमत में कोई कटौती नहीं हुई है और आवेदक के द्वारा कीमत में कटौती होने का दावा सही नहीं है। साथ ही, पाटन आयातों से किसी प्रकार के मूल्य प्रतिबंध/दबाव संबंधी कोई प्रभाव नहीं हुआ है।
- v. कंपनी को हुई क्षति की वास्तविक स्थिति कंपनी के तुलन-पत्र में उपलब्ध है जो जनता के अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध कराई है। उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियों के संदर्भ में अपार वृद्धि हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि पाटन की वजह से कोई क्षति नहीं हुई है, लेकिन अन्य कारक उद्योग के पूर्णतः प्रभावित कर रहे हैं।
- vi. आवेदन के अनुसार, लाभप्रदता के एनसीवी प्रवृत्ति, आरओसीई आदि तथा आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए वास्तविक लाभों के बीच अंतर है। प्राधिकारी के द्वारा इसकी जांच करने की जरूरत है और इस अंतर को बताने के बारे में आवेदक से अनुरोध किया जाना चाहिए।
- vii. आवेदन में उपलब्ध कराया गया बाजार हिस्सा सही नहीं है क्योंकि मांग, बड़े प्रतिस्थापन बाजार को ध्यान में रखे बिना होती है। यहां तक आयात संबंधी विश्वस्त आंकड़े भी आयात की पूरी तस्वीर नहीं दर्शाते हैं।
- viii. सर्वसम्मति से, रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता की वजह से कोई क्षति नहीं हुई है।
- ix. संबद्ध वस्तुओं के बहुत से जाने माने आयातकर्ता और प्रयोक्ता हैं जो आयात कर रहे हैं और स्वदेश में प्राप्त कर रहे हैं। प्राधिकारी के द्वारा ऐसे पक्षकारों से सूचना हेतु अनुरोध करना चाहिए।
- x. माल-सूचियों में बढ़ोत्तरी की वजह निर्यातों के लिए सामग्री स्टोर करने हेतु आवेदक की रणनीति हो सकती है और इसकी कोई अन्य प्रासंगिकता नहीं है।
- xi. इस जांच में यार्क्स ने जिस मूल्य पर भारत में उसकी संबंधित कंपनी को संबद्ध वस्तुएं बेची हैं, वह महत्व रखती है। क्या उन्होंने संबंधित कंपनी से कम मूल्य लिया है? क्या यह मूल्य अंतरण प्रार्थी घरेलू उद्योग की क्षति होने का मुख्य कारण है?
- xii. टाटा मोटर्स ने इस वजह से प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है कि वह भारी लाभ कमा रही है और उसकी लागत यार्क्स की लागत से काफी कम है। यदि टाटा मोटर्स प्रत्युत्तर दायर करती है तो इस बात की संशय संभावना है कि वह क्षतिरहित मूल्य को कम कर देगी तथा डीजीएडी की प्रक्रिया के अनुसार निर्मित सामान्य मूल्य भारत में सबसे कुशल उत्पादक की लागत पर आधारित होगा। घरेलू उद्योग के भाग के रूप में टाटा उद्योग को शामिल करने से निश्चित तौर पर उस नकारात्मक पाटन और क्षति मार्जिन को दर्शाएगा।
- xiii. किसी स्थिर लागत जैसे ब्याज लागत और मूल्यहास के बारे में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे उन कारणों की जांच की जा सके जिनकी वजह से कथित हानियां हुई हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि याचिकाकर्ता कंपनी की हाल में स्थापना की गई थी और वह इन लागतों को एकत्र नहीं कर सकेगी।
- xiv. सामान्य कीमत की गणना करने के प्रयोजनों के लिए याचिकाकर्ता के द्वारा चीन गणराज्य अथवा किसी तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में घरेलू मूल्यों का पता लगाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है।
- xv. पुणे में विनिर्माण सुविधा की वर्ष 2011 के मध्य में स्थापना की गई थी और उससे पूर्व याचिकाकर्ता का जमशेदपुर संयंत्र ही प्रचालन में था। इस तथ्य के बारे में याचिका में नहीं बताया गया है। यह नोट करना चाहिए कि लाभ/हानि का विश्लेषण करने इस तथ्य का वास्तव में महत्व है क्योंकि किसी नई इकाई के लिए अपने स्थापना के पहले कुछ वर्षों में समस्त लागतों की वसूली करने की संभावना नहीं होती है।
- xvi. बाजार के जानकारों का सुझाव है कि याचिकाकर्ता के द्वारा निर्मित ऐसे एक्सलों की व्यापक संख्या में बिक्री टाटा इंटरनेशनल प्रा. लि. को की गई है। घरेलू उद्योग को हुई कथित हानियों के कारण का आकलन करने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।
- xvii. केकेटीसी घरेलू उद्योग के मूल्यों से अधिक मूल्यों पर अपने उत्पादों को निरन्तर बेच रही है और यह बात याचिका में दर्शाए गए मूल्य में कटौती करने के आरोप के बारे में शंका पैदा करता है तथा याचिकाकर्ता का नेकनीयती पर भी शंका पैदा करती है।
- xviii. याचिका में भारत के भाग को सही-सही नहीं दर्शाया गया है। "एसआईएम" के द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में अपेक्षित एक्सलों की संख्या और उनकी मात्रा (एमटी में) के बारे में वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए गणना की गई है जो निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	पीओआई वार्षिकीकृत
याचिका में बताए अनुसार मांग	एमटी	13,892	8,762	16,639
एसआईएम आंकड़ों के अनुसार गणना की गई मांग	एमटी	18,593	13,109	27,644

- xix. मांग में भारी विसंगति है और याचिकाकर्ता के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े सही नहीं हैं और इनके बारे में कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। यह भी नोट किया जाए कि ट्रकों के निर्माता भी हैं जो एसआईएम का भाग नहीं है और उनके आंकड़ों को शामिल नहीं किया गया है। यह सुझाव है कि जो भाग दर्शाया गया है, मांग इससे काफी अधिक है।
- xx. याचिका में दिए आंकड़ों में भी क्षति, विशेषकर कारक लिंक को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।
- xxi. आयात और मांग संबंधी आंकड़े यह दर्शाते हैं कि आयातों की मात्रा मांग के हिसाब से कम-ज्यादा है अर्थात् जब मांग अधिक होती है तो आयातों की मात्रा अधिक होती है और जब मांग कम होती है तब आयातों की मात्रा कम होती है। इस सुझाव से सुझाव यह है कि आयातों की मात्रा का घरेलू उद्योग पर वास्तव में कोई प्रभाव नहीं होता है।
- xxii. उत्पादन, प्रतिदिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता और क्षमता उपयोग में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। भारत में उत्पादन के संदर्भ में धीरे-धीरे कमी आई है। इससे सुझाव यह है कि चीन गणराज्य से आयातों के बावजूद घरेलू उद्योग वृद्धि के संकेत दे रहा है। आयातों का घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- xxiii. 49% उपयोग एक बहुत ही छोटी-सी राशि है जब इसे भारतीय बाजार में मांग के संदर्भ में देखा गया है। भारत में मांग लगभग 16,639 एमटी के आस-पास है और याचिकाकर्ता उक्त क्षमता उपयोग से 7,967 उत्पादन करता है। उक्त क्षमता से याचिकाकर्ता भारतीय बाजार में अपेक्षित वस्तुओं की लगभग 48% का उत्पादन कर रहा है। भारत में मांग को पूरा करने के लिए वृद्धि और पर्याप्त क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
- xxiv. संबद्ध देश से आयातों की वजह से एक सीमित बाजार शेयर से क्षति नहीं हो सकती है तथा घरेलू उद्योग को हानियां क्षति की अवधि में कम हो रही हैं।
- xxv. चीन गणराज्य से आयातों के बावजूद घरेलू उद्योग में वृद्धि के संकेत हैं।
- xxvi. घरेलू उत्पादक अच्छी गणवत्ता वाले एक्सल उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं और वे भारतीय प्रयोक्ताओं की मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं। केकेटीसी के द्वारा आयात किए गए एक्सल एफयूडब्ल्यूए इंजीनियरिंग ग्रुप लि. के द्वारा निर्मित एक अनूठा नग है (जिसमें बाजार के जानकारों के अनुसार चीन गणराज्य में 80% बाजार शेयर है)। इसमें भारतीय उद्योग के द्वारा चार (4) अलग-अलग पुर्जों की वैलडिंग करने के बजाए हॉट फार्मिंग स्पिन्दल टेक्नोलॉजी से युक्त एक पीस बीम है। उत्तरवर्ती कमजोर/अस्थिर है तथा बाजार के जानकारों का सुझाव है कि रोजाना उपयोग करने पर यह दब जाता है। एक्सल के अधिक राशि देने के लिए इच्छुक होते हैं जो यह भी सुझाव देते हैं कि भारत में निर्मित एक्सलों की तुलना में उपभोक्ता उक्त एक्सलों के लिए तरजीह देते हैं।
- xxvii. स्थिर लागतों के संदर्भ में घरेलू उत्पादक हानियों की वसूली करने में असमर्थ हैं। कथित हानियां नए संयंत्र की स्थापना करने की वजह से हुई हैं।
- xxviii. यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो एक्सलों का केवल बड़ा और नियमित निर्माता होने की वजह से याचिकाकर्ता का बाजार पर एकाधिकार होगा और अपना (प्रधान) प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग कर सकता है। भारत में एक्सलों के सबसे बड़े निर्माता और अधिक सुरक्षा देने से प्रतिकूल प्रतिस्पर्द्धारोधी प्रभावों को संभवतः बढ़ावा दिया जाएगा।
- xxix. चल पूंजी और निवल स्थिर परिसंपत्तियां प्रथम-IVक में एक बहुत ही संदिग्ध घट-बढ़ को दर्शाती है।
- xxx. याचिकाकर्ता वर्तमान जांच में पाटन, क्षति और कारक लिंक स्थापित करने में असमर्थ रहा है। याचिका में दिए आंकड़े संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बारे में समर्थन नहीं करते हैं।

## छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

59. घरेलू उद्योग के द्वारा क्षति से संबंधित किए गए निवेदन संक्षेप में निम्नलिखित हैं:

- क) प्रथम-IV और VI में घरेलू उद्योग के लिए मात्रा एवं मूल्य प्रभाव तथा आर्थिक मापदण्डों के बारे में सूचना यह दर्शाती है कि उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री जैसे मात्रा संबंधी कुछ मानदंडों की यद्यपि सकारात्मक प्रवृत्ति रही, फिर भी घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति से संबंधित कुछ अन्य सूचकों, नामतः लाभप्रदता, निवेश पर लाभ, नकद लाभ आदि, पीओआई के दौरान काफी नकारात्मक थे तथा पीओआई में मात्रा संबंधी स्पष्ट कुछ सुधार की तुलना में उसी अवधि के दौरान किसी प्रकार का संतोषप्रद अथवा यहां तक औचित्यपूर्ण प्रवृत्ति नहीं दर्शायी थी।
- ख) वास्तव में घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष को छोड़कर क्षति अवधि के दौरान चीन गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अपनाई गई आक्रामक पाटन प्रक्रिया की वजह से भारी मात्रा में वित्तीय हानियों का सामना किया है और थोड़ी-सी वृद्धि होने से किसी प्रकार का उचित लाभ प्राप्त करने के लिए घरेलू उद्योग को मदद नहीं मिली थी क्योंकि मूल्य में बढोत्तरियों को पाटित आयातों के द्वारा रोका गया था।
- ग) विभिन्न आर्थिक मापदंडों के वस्तुपरक और समग्र मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगा कि संबद्ध देश से पाटित आयातों की वजह से घरेलू उद्योग को वस्तुतः क्षति हुई है।
- घ) मूल्य में कटौती, मूल्य प्रतिबंध और मूल्य नियंत्रणों के आधार पर पाटित आयातों का मूल्य प्रभाव काफी हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता विकृत हो गई है और घरेलू स्थिति आधार वर्ष के बाद हानि होने की बनी रही, अतः घरेलू उद्योग को वस्तुगत क्षति हुई है।
- ङ) पाटन की वजह से समतुल्य कीमत से कम कीमत लेने के कारण मात्रा संबंधी मापदंडों में सुधार पूर्णतः विकृत हो गए थे और वास्तव में कुछ अकेले (स्टैंडअलोन) मात्रा मापदंडों में सुधारों से घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं हुआ था क्योंकि घरेलू उद्योग के द्वारा उस मूल्य पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जो मूल्य लाभकारी नहीं था और वस्तुतः अपनी उत्पादन लागत से कम था। घरेलू उद्योग को वस्तुतः क्षति हुई है।
- च) जिस मूल्य पर विचाराधीन उत्पाद का भारत में आयात किया जाता है, वह मूल्य उसकी सामान्य कीमत से कम है, परिणामस्वरूप काफी पाटन मार्जिन है।
- छ) घरेलू उद्योग एक नकारात्मक स्तर तक लाभप्रदता को कम करते हुए और उस स्तर तक सब-ऑप्टिमल (कम अधिकतम) मूल्य पर देने के लिए बाध्य हुआ है जो अव्यावहारिक है और इसके जारी रहने से अत्यधिक प्रभाव पड़ा है।
- ज) बहुत ही कम और पाटित मूल्य पर आयात होने से घरेलू उद्योग को अपना मूल्य निवेश लागत में बढोत्तरी करने की सीमा तक बढ़ाने से रोकने की वजह से घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्यों को आयात नियंत्रित कर रहे हैं और दबाव भी पड़ रहा है।
- झ) लाभों में कमी होने से नियोजित पूंजी पर लाभ और नकद लाभों की स्थिति भी प्रत्यक्षतः खराब हुई है। घरेलू उद्योग पूंजी की लागत की वसूली करने में समर्थ नहीं रहा है। अतः हानियां, नियोजित पूंजी पर लाभ और नकद लाभ भी प्रत्यक्ष रूप से पाटित आयातों के कारण है।
- ञ) घरेलू उद्योग को हुई क्षति केवल संबद्ध देश से पाटित आयातों की वजह से हुई है।
- ट) यह भी निवेदन है कि भारतीय बाजार में उत्पाद की पर्याप्त मांग रहने के बावजूद घरेलू उद्योग को संबद्ध देश पर क्षतिपूर्ण पाटन के एक प्रभाव के रूप में भारी मात्रा में वित्तीय हानियां हुई थीं। वास्तव में, चीन गणराज्य से पाटन की वजह से संबद्ध वस्तुओं के बारे में निरन्तर प्रतिकूल बाजार की स्थितियों ने घरेलू बाजार को किसी प्रकार का उचित एवं न्यायसंगत लाभ पराप्त करने और क्षमताओं में और बढोत्तरी करने से भी रोका था।

## छ. 3 प्राधिकारी के द्वारा जांच

60. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.1 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में इन दोनों की वस्तुपरक जांच करने का प्रावधान है: (क) समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में पाटित आयातों की मात्रा और मूल्यों पर पाटित आयातों का प्रभाव और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव/पाटित आयातों के मात्रा संबंधी प्रभाव के बारे में प्राधिकारी के द्वारा यह जांच करनी होती है कि क्या पाटित आयातों में पर्याप्त बढोत्तरी हुई है अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के संदर्भ में हुई है। पाटित आयातों के मूल्य प्रभाव के बारे में प्राधिकारी के द्वारा यह जांच करनी होती है कि क्या भारत में समान उत्पाद के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों से मूल्यों में काफी कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा काफी हद तक मूल्यों को नियंत्रित करना अथवा मूल्यों को बढ़ने से रोकना है जो पर्याप्त सीमा तक अन्यथा होंगे।



61. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का जहां तक संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (IV) में निम्नानुसार सूचित किया जाता है:
- "संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट, सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"*
62. इसमें प्राधिकारी द्वारा किया गया विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का स्वतः समाधान करता है। तथापि, प्राधिकारी समाधान किए गए, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विशिष्ट अनुरोध निम्नलिखित हैं;
63. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक ने आईबीआईएस आंकड़ों पर विश्वास किया है जोकि सभी पक्षों को शामिल नहीं किए जाने का दावा करते हैं और प्राधिकारी को डीजीसीआईएण्डएस के अनुसार आयात के सही और पूर्ण आंकड़े प्राप्त करने के उत्तरदायित्व की भूमिका देता है और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए आयात आंकड़े विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते, यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी द्वारा विगत कई मामलों में विश्वास किया गया है। इसके अतिरिक्त, आईबीआईएस के आयात आंकड़ों का डीजीसीआईएस के आंकड़ों से प्रति परीक्षण किया गया है। मात्रा और कीमतों में इसी प्रकार का रुख है।
64. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने कोई भी मात्रा क्षति वहन नहीं की है तथा कुछ कीमत प्राचलों की स्पष्ट स्थिति 2014-15 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सही नहीं हैं, जो लाभ दर्शाते हैं इस प्रकार कोई क्षति नहीं है, यह नोट किया गया है कि वार्षिक रिपोर्ट में सूचना संपूर्ण कंपनी के लिए है और अकेले पीयूसी से संबंधित नहीं है। पाटन और क्षति के तथ्य तथा उसके बीच कारणात्मक संबंध का इस अंतिम जांच परिणाम में उचित स्थानों पर उल्लिखित किया गया है।
65. इस तर्क के संबंध में कि क्षमता उपयोगिता शब्द का इस मामले में कोई संबंध नहीं है क्योंकि कोई वास्तविक विनिर्माण कार्यकलाप में शामिल नहीं हैं, इसलिए यह नोट किया गया है कि तर्क सिद्ध नहीं हुआ है।
66. इस तर्क के संबंध में कि वर्तमान मामले में कोई कीमत अंडरकटिंग नहीं है और आवेदक द्वारा कीमत अंडरकटिंग के दावे सही नहीं हैं और पाटित आयातों द्वारा कोई कीमत वृद्धि/कमी प्रभाव सृजित नहीं हुआ है, यह नोट किया गया है कि नीचे यहाँ दिया गया वर्तमान अंतिम जांच परिणाम इस प्रकार के दावों के संबंध में स्वतः स्पष्ट है।
67. इस तर्क के संबंध में कि कंपनी की क्षति की वास्तविक स्थिति कंपनी के तुलन पत्र में उपलब्ध है जो सरकारी डोमेन में उपलब्ध कराई गई है, यह नोट किया गया है कि संदर्भित तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि खाता संपूर्ण कंपनी के लिए है जबकि प्राधिकारी ने केवल पीयूसी से संबंधित निष्पादन प्राचलों का विश्लेषण किया है।
68. इस तर्क के संबंध में कि आवेदन में उल्लिखित बाजार हिस्सा सही नहीं है क्योंकि मांग बड़े प्रतिस्थापन बाजार को ध्यान में रखे बगैर है, यह नोट किया गया है कि दावे का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।
69. इस तर्क के संबंध में कि वह कीमत जिस पर यॉर्क ट्रांसपोर्ट इन्क़िपमेंट्स (इण्डिया) प्रा. लि. ने अपनी संबंधित कंपनी को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है, बहुत महत्वपूर्ण है और क्या यह अंतरण कीमत आवेदक घरेलू उद्योग को क्षति का मुख्य कारण है, के मामले की जाँच की गई है और यह पता लगा है कि घरेलू बाजार में संबद्ध पक्षकार बिक्री पीओआई के दौरान 20% से कम थी। इसके अतिरिक्त, संबद्ध कंपनी के लिए औसत विक्रय कीमत घरेलू बाजार में औसत विक्रय कीमत की तुलना में मामूली कम थी। यह कतिपय व्यय जैसे यूनिट की समीपता के कारण भाड़ा तथा बिक्री करने के लिए किसी मध्यवर्ती को कमीशन का भुगतान नहीं करने के कारण व्यय नहीं होने जैसे विभिन्न कारणों की वजह से है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध पक्षकारों को बिक्री को शामिल नहीं करने के बावजूद कीमत अंडरकटिंग धनात्मक थी। इस प्रकार आवेदक घरेलू उद्योग को क्षति का मुख्य कारण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किए गए अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार लेन-देन नहीं है।
70. इस तर्क के संबंध में कि टाटा मोटर्स ने इस तथ्य के कारण कोई उत्तर दायर नहीं किया है कि यह भारी लाभ कमा रहा है, यह नोट किया गया है कि समर्थकों सहित मैसर्स यॉर्क ट्रांसपोर्ट इन्क़िपमेंट्स (इण्डिया) प्रा. लि. नियम 2 (ख) के अनुसार वर्तमान जाँच में घरेलू उद्योग पाया गया है और नियम 2 (ख) की अपेक्षाओं के अलावा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए किसी अनुरोध में अधिदेशित नहीं हैं। यह भी नोट किया गया है कि आवेदक ने अनुरोध किया है कि टाटा मोटर्स लिमिटेड एक पृथक कानूनी निकाय है एक हितबद्ध पक्षकार नहीं है जैसा कि किसी मामले में नियमों में परिकल्पित है और आवेदक स्थायी अपेक्षाओं को पूरा करता है।
71. इस तर्क के संबंध में कि विनिर्माण सुविधा 2011 के मध्य में पुणे में स्थापित की गई थी और याचिकाकर्ता का जमशेदपुर संयंत्र उससे पूर्व प्रचालन में एकमात्र इकाई थी, यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी ने नियमों में, उल्लिखित अनुसार और अन्यथा नहीं, क्षति के दावे की जाँच की है।

72. इस तर्क के संबंध में कि केकेटीसी घरेलू उद्योग की कीमतों की तुलना में अधिक कीमतों पर लगातार अपने उत्पादों की बिक्री कर रहा है और यह याचिका में उल्लिखित कीमत अंडरकटिंग रेंज के आरोप पर संदेह उत्पन्न करता है और याचिकाकर्ता की *प्रामाणिकता* पर संदेह उत्पन्न करते हैं। यह नोट किया गया है कि कीमत अंडरकटिंग की गणना औसत एनएसआर और आयातों की उतराई कीमत के आधार पर की गई है और किसी वैयक्तिक खरीददार के लिए आपूर्तियों पर आधारित नहीं हैं।

73. इस तर्क के संबंध में कि आयात और मांग से संबंधित आंकड़े दर्शाते हैं कि आयात की मात्रा मांग के अनुरूप है अर्थात् – जिस समय मांग अधिक है उस समय आयात मात्रा अधिक है और जिस समय मांग कम है उस समय आयात मात्रा कम है, यह नोट किया गया है कि आयात पर्याप्त हैं और पाटित और क्षति कीमत पर हो रहा है।

74. इस तर्क के संबंध में कि उत्पादन, प्रतिदिन उत्पादकता, प्रति कर्मचारी उत्पादकता और क्षमता उपयोग में काफी वृद्धि हुई है और भारत में उत्पादन की दृष्टि से आयात में क्रमिक रूप से कमी होगी और यह सुझाव देता है कि घरेलू उद्योग चीन पीआर से आयात के बावजूद वृद्धि के संकेत दर्शाता है। घरेलू उद्योग पर आयातों का कोई प्रभाव नहीं है, यह नोट किया गया है कि वर्तमान अंतिम जांच परिणाम से उत्पन्न तथ्य इस प्रकार के तर्कों के संबंध में स्वतः स्पष्ट है।

75. इस तर्क के संबंध में कि संबद्ध देश से आयात सीमित बाजार हिस्से के साथ क्षति का कारण नहीं हो सकता और घरेलू उद्योग को क्षति, क्षति अवधि के दौरान कम हो रही है, यह नोट किया गया है कि वर्तमान विवरण प्रकटन से उत्पन्न तथ्य इस तर्क के संबंध में स्वतः स्पष्ट हैं।

76. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग चीन पीआर से आयात के बावजूद वृद्धि के संकेत दर्शाता है, यह नोट किया गया है कि वर्तमान अंतिम जांच परिणाम से उत्पन्न तथ्य इस तर्क के संबंध में स्वतः स्पष्ट है।

77. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उत्पादक अच्छी क्वालिटी के एक्सेल उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है और भारतीय प्रयोक्ताओं की मांग को पूरा नहीं कर सकते, यह नोट किया गया है कि आवेदक ने अनुरोध किया कि उनके उत्पाद अपेक्षित गुणवत्ता मानदंड को पूरा करते हैं और विरोधी पक्षकार के तर्क सच नहीं हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि आयातित पीयूसी और घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पाद में कोई विशेष अंतर है।

78. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उत्पादक स्थिर लागतों को ध्यान में रखते हुए हानि को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं और निर्दिष्ट हानि एक नया संयंत्र स्थापित करने की लागतों के कारण हैं, यह नोट किया गया है कि यह तर्क प्रमाणित नहीं हुआ है।

79. इस तर्क के संबंध में कि यदि एडी शुल्क लगाया जाता है तो याचिकाकर्ता के एक्सेलों का एकमात्र बड़ा और नियमित विनिर्माता होने के कारण बाजार में एकाधिकार करेगा और अपनी प्रभुत्वपूर्ण स्थिति का दुरुपयोग कर सकता है और भारत में एक्सेलों के बड़े उत्पादक को संरक्षण देते हुए प्रतिकूल प्रतिस्पर्द्धारोधी प्रभाव देने की संभावना होगी, यह नोट किया जाए कि यदि एडी शुल्क लगाया जाता है तो वह केवल पाटन के क्षति प्रभाव को ही समाप्त करेगा और क्षति को कम करने अथवा पाटन मार्जिन के बाहर किसी संरक्षण की परिकल्पना नहीं करेगा।

80. इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता पाटन क्षति और वर्तमान जाँच में आकस्मिक लिंक प्रमाणित करने में विफल रहा है और याचिका में आंकड़े संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का समर्थन नहीं करते, यह नोट किया गया है कि वर्तमान वर्तमान अंतिम जांच परिणाम से उत्पन्न तथ्य इस प्रकार के तर्कों के संबंध में स्वतः स्पष्ट है।

81. भारत में घरेलू उद्योग पर आयात के प्रभाव की जाँच करने के लिए प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के **अनुबंध-II(iv)** के अनुसार आगे इस प्रकार के सूचकों पर विचार किया है जिनका उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, मात्रा तथा पाटन मार्जिन आदि के रूप में उद्योग की स्थिति को दर्शाते हैं।

## **ii. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों पर मात्रा प्रभाव**

82. क्षति का निर्धारण करने के प्रयोजन से प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात की मात्रा और कीमत प्रभावों तथा क्षति के अस्तित्व एवं पाटन एवं क्षति के बीच आकस्मिक लिंक, यदि कोई हो, की जाँच करने के लिए कीमत और लाभप्रदता पर इसके प्रभाव की जाँच की है। तदनुसार, नीचे दिए अनुसार पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभावों की जाँच की गई है:

### **क. मांग और बाजार हिस्सा**

83. प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादों की कुल बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में भारत में उत्पाद की प्रत्यक्ष खपत के लिए वर्तमान जाँच के उद्देश्य हेतु परिभाषित किए हैं। इस प्रकार निर्धारित मांग नीचे तालिका में दी गई है:

## i) मांग

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई	पीओआई वार्षिकी
मांग	एमटी	16902	13923	8785	20855	16684
इंडेक्स	रुख	100	82	52	99	99
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	4,917	4,433	3,066	8,250	6,600
अन्य देशों से आयात	एमटी	526	8	-	-	-
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	4542	3517	2605	6501	5201
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	एमटी	6,916	5,965	3,114	6,104	4,883

## ii) मांग में बाजार हिस्सा

84. विभिन्न स्रोतों से संबद्ध वस्तुओं के आयात, भारतीय उत्पादकों की संबद्ध वस्तुओं की बिक्री, भारत में मांग में संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से को ध्यान में रखते हुए जाँच की गई थी, के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति नीचे दी गई है;

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई	पीओआई वार्षिकी
संबद्ध देशों से आयात	%	29.09	31.84	34.90	39.56	39.56
अन्य देशों से आयात	%	3.11	0.06	-	-	-
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	26.88	25.26	29.65	31.17	31.17
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	%	40.92	42.84	35.44	29.27	29.27

85. उपरोक्त तालिका से यह देखा गया है कि देश में उत्पाद की मांग आधार वर्ष की तुलना में 2012-13 और 2013-14 के दौरान घट गई है तथा पीओआई के दौरान बढ़ गई है। आवेदक ने दावा किया है कि आधार वर्ष और वर्ष 2013-14 के बीच मांग में गिरावट देश में प्रतिकूल आर्थिक स्थिति में का परिणाम था जिसने ट्रेलर उत्पादन को प्रभावित किया है तथापि, उसे पीओआई द्वारा काफी सीमा तक सही कर दिया गया था। यह नोट किया गया है कि संबद्ध आयात का हिस्सा जो आधार वर्ष में 29.09% था, पीओआई में बढ़कर 39.56% हो गया जबकि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जो आधार वर्ष में 26.88% था, पीओआई के दौरान बढ़कर 31.17% हो गया। इस प्रकार मांग में वृद्धि संबद्ध देशों से पाटित आयात द्वारा प्रमुख रूप से खपा दी गई थी। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर संबद्ध देशों से पाटित आयात का प्रभाव सिद्ध होता है।

## क. आयात मात्रा और बाजार हिस्सा

86. प्राधिकारी ने आईबीआईएस के लेन-देनवार आयात आंकड़ों के अनुसार और डीजीसीआईएण्डएस के अनुसार संबद्ध देशों के आयातों की मात्रा की जाँच की है। प्राधिकारी ने इस वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए उस पर विश्वास किया है। रिकॉर्ड पर आयात आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देश से आयात मात्रा डी-मिनिमिस के स्तर से अधिक पाई गई है। संबद्ध देश और अन्य देशों से आयात मात्रा नीचे दी गई है:-

विवरण		इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई	पीओआई वार्षिकी
मात्रा	संबद्ध देश	एमटी	4,917	4,433	3,066	8,250	6,600
	अन्य देश	एमटी	526	8	-	-	-
	कुल आयात	एमटी	5,444	4,441	3,066	8,250	6,600
आयात में बाजार हिस्सा	संबद्ध देश	%	90.33	99.81	100.00	100.00	100.00
	अन्य देश	%	9.67	0.19	शून्य	शून्य	शून्य

87. यह अवलोकन किया गया है कि संबद्ध देश से आयात निरपेक्ष रूप से बढ़ा है और पीओआई सहित संपूर्ण क्षति अवधि में भारत में कुल आयात के 90% से अधिक रहा। वास्तव में, संबद्ध देश से आयात आधार वर्ष और उसके पश्चात् वर्ष को छोड़कर 100% बनता है। यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध देश से आयात भारत में उत्पाद की मांग के बहुत अधिक अनुपात में है। संबद्ध देश से आयात की मात्रा निरपेक्ष रूप से बढ़ी है और क्षति अवधि तथा पीओआई के दौरान भारत में मांग में तुलनात्मक रूप से भी वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से आयात जो आधार वर्ष में 4917 एमटी था, पीओआई के दौरान और मांग की दृष्टि से भी प्रत्यक्ष रूप से बढ़कर 6600 एमटी (वार्षिकी) हो गया है। घरेलू मांग में पाटित आयात का काफी हिस्सा और मांग में वृद्धि के लिए उसकी तुलनात्मक वृद्धि काफी सुस्पष्ट है।

#### ख. क्षमता और क्षमता उपयोगिता

88. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता और क्षमता उपयोगिता नीचे तालिका में दी गई है:-

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई	पीओआई वार्षिकी
क्षमता एमटी	एमटी	16560	16560	16560	20700	16560
क्षमता उपयोग	%	26.81	30.96	32.81	50.23	50.23

89. यह अवलोकन किया गया है कि आधार वर्ष के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोगिता में वृद्धि हुई है परंतु पीओआई के दौरान 50.23% पर बनी रही। यह भी नोट किया गया है कि क्षमता उपयोगिता संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान सम स्तर से नीचे रही। यदि हम एकमात्र प्राचल को देखें तो क्षमता उपयोगिता में वृद्धि घरेलू उद्योग को क्षति की वास्तविक स्थिति की गलत बयानी करेगी। क्षमता उपयोगिता में मामूली वृद्धि क्षति से संबंधित कीमत प्राचलों से देखी जानी चाहिए जिसने अत्यधिक गिरावट दर्शाई है।

#### ग. उत्पादन

90. घरेलू उद्योग का उत्पादन नीचे तालिका में दिया गया है:-

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई	पीओआई वार्षिकी
उत्पादन	एमटी	4439	5127	5433	10,397	8,318
मांग	एमटी	16902	13923	8785	20855	16684
मांग की तुलना में उत्पादन	%	26.26%	36.82%	61.84%	49.85%	49.85%

91. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान उत्पादन ने वृद्धि का रूख दर्शाया है। उपरोक्त मात्रा प्राचल भी वृद्धि का रूख दर्शाते हैं, संबद्ध कीमत प्राचलों में अत्यधिक गिरावट दर्शाई है और लाभों को प्रभावी रूप से ऋणात्मक करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा वित्तीय क्षति वहन की गई है जो मात्रा प्राचलों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किए गए हैं। यह भी नोट किया गया है कि भारत में मांग की तुलना में उत्पादन 2013-14 में 61.84% के स्तर पर बढ़ गया था और पीओआई में घटकर 49.85% के स्तर पर रह गया है।

**घ. बिक्री मात्रा**

92. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई	पीओआई वार्षिकी
घरेलू बिक्री	एमटी	4542	3517	2605	6501	5201
मांग	एमटी	16902	13923	8785	20855	16684
मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	26.87	25.26	29.65	31.17	31.17

93. तथापि, बिक्री मात्रा बिक्री में वृद्धि का रूख दर्शाती है फिर भी संबद्ध कीमत प्राचल अत्यधिक गिरावट दर्शाते हैं और घरेलू उद्योग द्वारा वित्तीय क्षति वहन की जा रही है। बिक्री मात्रा में यह वृद्धि आयातों की उतराई लागत के अनुरूप कीमत को समायोजित करने के लिए हासिल की गई है। सारांशतः, बिक्री मात्रा में वृद्धि में कोई बॉटम लाइन सुधार नहीं किया।

94. बिक्री प्राचलों में वृद्धि के इस संदर्भ में यदि वित्तीय प्राचलों को ध्यान में रखा जाता है तो घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन में प्रदर्शित नहीं हुआ। मात्रा प्राचलों में वृद्धि निष्पादन की अचल लागतों के कुछ प्रभाव को बेहतर ढंग से प्रभावहीन कर सकती है परंतु निष्पादन में समग्र रूप से सुधार करने के लिए यह पर्याप्त नहीं था।

95. इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य मात्रा प्राचलों में घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा क्षति अवधि के दौरान तथा पीओआई के दौरान बढ़ी है, तथापि जैसा कि यहाँ ऊपर नोट किया गया है कि चीन पीआर से आयात के बाजार हिस्से में वृद्धि पीओआई के दौरान भारतीय मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि से काफी अधिक रही है।

**ड. मालसूचियां**

96. घरेलू उद्योग की मालसूची निम्नानुसार है;

	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई	पीओआई वार्षिकी
औसत स्टॉक	एमटी	180	221	279	332	332
इंडेक्स		100	123	155	184	184

97. यह नोट किया गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की पास मालसूची में निरंतर वृद्धि हुई है। यह नोट किया गया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संबद्ध वस्तु मुख्य रूप से ऑर्डर के लिए उत्पादित की गई है, क्षति का प्रमुख सूचक नहीं हो सकता।

**iii. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव**

98. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस पर विचार करना अपेक्षित है कि भारत में उत्पाद की तरह कीमतों से तुलना के रूप में पाटित आयातों द्वारा काफी अंडरकटिंग कीमत रही है अथवा अन्यथा इस प्रकार के आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों को कम करने अथवा कीमत वृद्धियों को रोकने के लिए था जोकि अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए उत्पादन की भारित औसत लागत (सीओपी), भारित औसत निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और घरेलू उद्योग की गैर-क्षति कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से आयातों की उतराई लागत से की गई है।

**क) कीमत में कटौती**

99. निवल बिक्री प्राप्ति की गणना सभी छूटों और करों की कटौती करने के पश्चात् की गई है। आयातों के उतराई मूल्य की गणना 1% संभाल प्रभारित और संबद्ध आयातों के सीआईएफ मूल्य के लिए लागू मूल्य सीमा शुल्क को जोड़कर की गई है। आयातों के उतराई मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से की गई थी और यह पता लगा था कि पाटित आयात घरेलू उद्योग की अंडरकटिंग कीमतें हैं।

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई
उतराई मूल्य	रु./किग्रा	***	***	***	***
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./किग्रा	***	***	***	***
अंडरकटिंग कीमत	रु./किग्रा	***	***	***	***
अंडरकटिंग कीमत	%	***	***	***	***
अंडरकटिंग कीमत	% श्रेणी	15-20	5-10	1-5	5-10

100. यह अवलोकन किया गया है कि संबद्ध देश से आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना में काफी कम रही है जिसके फलस्वरूप क्षति अवधि और पीओआई के दौरान पर्याप्त अंडरकटिंग कीमत हुई। संबद्ध देश से आयात की उतराई कीमत में आधार वर्ष और उसके तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के बीच कुछ वृद्धियों के पश्चात् पीओआई के दौरान कुछ गिरावट दर्शाई है। कीमत अंडरकटिंग, जिसने वर्ष 2012-13 और 2013-14 में कुछ कमी दर्शाई है, पुनः पीओआई में बढ़ गई।

#### ख) कम कीमत पर बिक्री

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कम कीमत पर बिक्री क्षति के आलन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। क्षति रहित कीमत ज्ञात की गई है और कम कीमत पर बिक्री की सीमा ज्ञात करने के लिए उसकी तुलना संबद्ध वस्तु की पंहुच कीमत से की गई है। क्षति रहित कीमत घरेलू उत्पादक के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के अनुसार पीओआई के दौरान विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत पर विचार करते हुए उचित ढंग से मूल्यांकित की गई है। विश्लेषण से पता चला है कि संबद्ध आयातों का पंहुच मूल्य निम्नानुसार निर्धारित क्षतिरहित कीमतसे काफी कम है:

विवरण	इकाई	चीन जन. गण.
क्षतिरहित कीमत	रु./किग्रा.	***
पंहुच कीमत	रु./किग्रा.	109.73
कम कीमत पर बिक्री	रु./किग्रा.	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***
कम कीमत पर बिक्री	% रेंज	10-15

#### ग) कीमत न्यूनीकरण/ह्रास

102. प्राधिकारी ने इस बात की जाँच की कि क्या पाटित आयातों का प्रभाव भारत में समान वस्तु की कीमतों में ह्रास करना या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा बढ़ गई होती।

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई
उत्पादन लागत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	118	108
बिक्री कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	98	102
पंहुच मूल्य	रु./किग्रा.	95.35	105.80	110.09	109.73
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	115	115

103. उक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि उत्पादन लागत में आधार वर्ष में 100 से पीओआई में 108 तक की वृद्धि हुई है, बिक्री कीमत आधार वर्ष में सूचीबद्ध 100 से उसी अवधि के दौरान केवल 102 हुई है जिसका अर्थ है कि पाटित कीमतों के कारण कीमतों में ह्रास हुआ क्योंकि घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुपात में कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है। यह स्पष्ट है कि आयातों की पंहुच कीमत से काफी मात्रा में कीमत ह्रास हुआ है जिससे कम कीमत पर बिक्री के अलावा घरेलू उद्योग की बिक्री प्राप्ति पर गंभीर कीमत प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रास प्रभाव पड़ा है।

#### घ) लाभ/हानि

104. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई (वार्षिकीकृत)
लाभ	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(971)	(1266)	(315)
लाभ	लाख रू.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(750)	(725)	(360)

105. यह नोट किया जाता है क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भारी कमी आई है और लाभों में इन वर्षों में भारी गिरावट हुई है जबकि घरेलू उद्योग पहले लाभ कमा रहा था परंतु बाद में पूरी क्षति अवधि में उसे घाटा हुआ, यद्यपि पीओआई के दौरान उत्पादन और बिक्री में सुधार के कारण घाटों में कमी आई है। उक्त से यह नोट किया जाता है कि आयातों की पंहुच कीमत उसी अवधि में घरेलू कीमतों पर कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री प्रभाव डाल रही है। ऐसी पंहुच कीमत का प्रभाव घरेलू उद्योग के वित्तीय घाटों की स्थिति से स्पष्ट है।

#### ङ) नियोजित पूंजी पर आय

106. नियोजित पूंजी पर आय संबंधी सूचना नीचे तालिका में दी गई है:

	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(949)	(1061)	(293)

107. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय में क्षति अवधि के दौरान भारी कमी आई है और पीओआई में वह ऋणात्मक रही है और यह प्रवृत्ति लाभप्रदता की प्रवृत्ति से तुलनीय है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को उसी अवधि में वित्तीय घाटा उठाना पड़ रहा है।

#### च) नकद प्रवाह

108. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के नकद प्रवाह की स्थिति पर पाटन के प्रभाव की जाँच करने के लिए नकद लाभ की प्रवृत्ति की जाँच की है। घरेलू उद्योग के नकद प्रवाह के संबंध में सूचना नीचे तालिका में दी गई है:

	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई (वार्षिकीकृत)
नकद प्रवाह	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(325)	(325)	(135)

यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के नकद लाभ में क्षति अवधि के दौरान तेजी से गिरावट आई है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की नकद लाभ और नकद प्रवाह की स्थिति में प्रतिकूल दशा दर्ज हुई है।

**छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**

109. लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार और कीमतों का किसी प्रतिस्पर्धी स्थानापन्न की कीमतों से प्रतिस्पर्धा, यदि कोई हो, की जॉच पाटित आयातों के अलावा कारकों के विश्लेषण से की गई है जो घरेलू उद्योग को कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि परस्पर प्रतिस्पर्धा या लागत संरचना में कोई ऐसा अंतर हो जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट आई हो।

**ज) उत्पादकता**

110. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में उत्पादन के समान ही प्रवृत्ति रही है। उत्पादकता में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है और उससे माना जा सकता है कि उत्पादकता घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है:

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	114	176
उत्पादकता प्रतिदिन	एमटी/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	125	192

**झ) रोजगार और मजदूरी**

111. रोजगार के स्तर में पीओआई तक कुछ वृद्धि हुई है परंतु कुछ मामूल स्तर तक। तथापि प्रति किग्रा. समग्र मजदूरी में पीओआई में गिरावट आई है जिसे उन्नत प्रति कर्मचारी और प्रतिदिन उत्पादकता के साथ देखा जाना चाहिए।

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई
रोजगार	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	107	107
मजदूरी	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	74	88

**ञ) वृद्धि**

112. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की वृद्धि अनेक मापदंडों पर नकारात्मक रही है। घरेलू उद्योग की वृद्धि अनेक मापदंडों में हुई है जब उत्पाद की बाजार में भारी वृद्धि हुई थी।

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई
उत्पादन (एमटी)	%		15.49	5.97	53.09
घरेलू बिक्रियां (एमटी)	%		-22.58	-25.93	99.65
लाभ/ (घाटा) लाख रुपये	%		-850	3.35	50.35
नकद लाभ (लाख रुपये)	%		-425	0.21	58.42
निवेश पर आय	%		-1049	-11.81	72.42
मांग	%		-18	-37	90

**ट) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता**

113. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तेजी से भारी गिरावट आई है और घरेलू उद्योग वित्तीय घाटा उठा रहा है। जब मौजूदा निवेशों से निवेश पर आय में नुकसान है तो अतिरिक्त पूंजी निवेश जुटाने के लिए स्थिति व्यवहार्य नहीं है।



**ज. क्षति संबंधी निष्कर्ष**

114. क्षति संबंधी विभिन्न मापदंडों की जाँच करने पर प्राधिकारी इस निष्कर्ष का प्रस्ताव करते हैं कि संबद्ध देश से आयातों में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में भी वृद्धि हुई है। उत्पाद के आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं और कम कीमत पर बिक्री और कीमत ह्रास के प्रभाव डाल रहे हैं। इसके अलावा यद्यपि क्षति अवधि के दौरान उत्पादन की लागत बढ़ती रही है तथापि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में उत्पादन लागत के स्तर तक भी वृद्धि नहीं की जा सकी है जिससे घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हुआ है। इस प्रकार आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास हुआ है और उससे ऐसी कीमत वृद्धि नहीं हो पाई है जो अन्यथा पाटित आयातों की गैर मौजूदगी में बढ़ गई होती।

115. यह नोट किया जाता है कि उत्पाद की मांग और घरेलू उद्योग की बिक्री में भारी वृद्धि हुई है तथापि घरेलू उद्योग अनुपातिक रूप से लाभप्रदता को नहीं बढ़ा पाया है क्योंकि पाटित आयातों का बाजार में काफी अधिक हिस्सा बना हुआ है। ऐसे पाटित आयातों में कीमत कटौती के साथ निरंतर वृद्धि हुई है जिससे घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि को उपभोक्ताओं को हस्तांतरित करके लाभ नहीं कमा पाया है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा होना शुरू हो गया है। यद्यपि घरेलू उद्योग बिक्री मात्रा में वृद्धि नहीं कर सका है, तथापि उससे लाभप्रदता पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि ऐसी बड़ी हुई बिक्रियां संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की पाटित कीमतों से मुकाबला करके हासिल की गई थी।

116. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में निरंतर गिरावट आई है और घरेलू उद्योग वित्तीय घाटा उठा रहा है। नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ में भी लाभ के समान ही प्रवृत्ति रही है। नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ दोनों में पीओआई में काफी नकारात्मक आकड़े रहे हैं।

**झ. कारणात्मक संबंध और अन्य कारक**

117. वास्तविक क्षति की मौजूदगी घरेलू उद्योग की कीमतों पर कम कीमत पर बिक्री और कीमत ह्रास और न्यूनकारी प्रभावों, भारतीय नियमावली और पाटनरोधी करारों के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य संकेतात्मक मापदंडों के अनुसार पाटित आयातों के मात्रा और कीमत प्रभावों की जाँच करने के बाद प्राधिकारी ने इस बात की जाँच की है कि क्या एडी नियमावली में सूचीबद्ध कारकों से इतर कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। कारणात्मक संबंध की जाँच निम्नानुसार की गई है:

**(क) पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमत**

118. पीओआई के दौरान, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के कुल आयात संबद्ध देश से हुए हैं। अंतः अन्य देशों से आयातों को घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए विचारार्थ नहीं लिया जा सकता है।

**(ख) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा**

119. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु का एक बाजार है जिसमें संबद्ध देश से पाटित आयात घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तु से सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि आयातित संबद्ध वस्तु और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु समान वस्तु हैं और उनका समान अनुप्रयोगों/अंतिम प्रयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं और विदेशी उत्पादकों और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा के ऐसे कोई साक्ष्य नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

**(ग) मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन**

120. प्राधिकारी नोट करते हैं उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान और जाँच अवधि में भी भारी वृद्धि हुई है। इस प्रकार प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को क्षति मांग में संकुचन के कारण नहीं हुई है।

**(घ) प्रौद्योगिकी में विकास**

121. किसी भी हितबद्ध पक्ष ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई खास बदलाव दर्शाया गया हो जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

**(ङ) घरेलू उद्योग का निर्यात कार्यनिष्पादन**

122. घरेलू उद्योग के निर्यात कार्य निष्पादन का ब्योरा निम्नानुसार है:

अवधि	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई वार्षिकीकृत
मात्रा एमटी में	-	***	***	***
सूचीबद्ध	शून्य	100	204	212
मूल्य रुपये प्रति किग्रा.	शून्य	***	***	***
सूचीबद्ध	शून्य	100	113	123

123. घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन को घरेलू और निर्यात बाजार के लिए पृथक् किया गया है और घरेलू बाजार में लाभप्रदता पर ही इस वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है। अंतः निर्यात कार्य निष्पादन में कोई संभव गिरावट क्षति का कारण नहीं है। प्राधिकारी ने कीमत संबंधी मापदंडों के प्रभाव का पता लगाने के लिए केवल घरेलू प्रचालन पर विचार किया है।

#### (च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

124. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में निरंतर वृद्धि हुई है। तथापि उत्पादकता के स्तर में परिवर्तन पर विचार किए बिना घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में निरंतर गिरावट आई है।

125. पूर्वोक्त के अनुसार प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि अन्य कारकों की वजह से क्षति होने का कोई साक्ष्य नहीं है।

#### ज. कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक

126. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन के विश्लेषण से पता चलता है कि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में क्षति अवधि और जाँच अवधि के दौरान वास्तविक रूप से क्षति हुई है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित आधारों पर स्थापित किया गया है:

- क) संबद्ध वस्तु का भारत में पाटित कीमतों पर आयात हुआ है। संबद्ध देश से पाटित आयात में क्षति अवधि में भारी वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से आयातों भारी वृद्धि के साथ घरेलू बाजार में काफी हिस्सा प्रतिकूलतः प्रभावित होने से उसके बाजार हिस्से में घरेलू उद्योग की क्षमता संबद्ध वस्तु के लिए उचित और लाभप्रद कीमत प्राप्त करने में प्रभावित हुई है।
- ख) संबद्ध देश से पाटित आयात से घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास हो रहा है। चूंकि घरेलू उद्योग ने अपनी बिक्री कीमत को पंहुच कीमत के बराबर करने का प्रयास किया है, इसलिए बिक्री कीमत में वृद्धि उत्पादन लागत में वृद्धि से काफी कम रही है और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हुआ है।
- ग) संबद्ध देश से आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी स्तर तक कटौती हुई है। इससे घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुसार अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं कर पा रहा है और तर्कसंगत लाभ अर्जित करने में अक्षम है। वास्तव में, घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के दौरान उत्पादन लागत में वृद्धि हाने पर अपनी कीमतें घटाने पर बाध्य होना पड़ा है।
- घ) पाटित आयातों का कीमत ह्रास प्रभाव घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भारी गिरावट में दिखाई देता है।
- ङ) लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ में गिरावट पाटित आयातों का प्रत्यक्ष प्रभाव है।

127. प्राधिकारी का विचार है कि उक्त आधार स्पष्ट रूप से संबद्ध देश से पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी को सिद्ध करते हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी वर्तमान वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

#### ट. क्षति और क्षति मार्जिन की मात्रा

128. प्राधिकारी ने यथा संशोधित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। इस प्रकार निर्धारित क्षतिरहित कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पंहुच कीमत के साथ की गई है।

उत्पादक/निर्यातक का नाम	एनआईपी/किग्रा. (अमडा.)	पंहुच मूल्य/किग्रा. (अमडा.)	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन (%) रेंज
गुआंगडोंग फुवा इंजीनियरिंग मैनुफैक्चरिंग कंपनी लि.	***	***	***	***	5-15
गुआंगडोंग फुवा हैवी इंडस्ट्रीज कं. लि.	***	***	***	***	
शेनडोंग जिनशेंग एक्सल मैनुफैक्चरिंग कं. लि..	***	***	***	***	
कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	25-35

#### ठ प्रकटन पश्चात विवरण पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

129. वर्तमान अंतिम जांच परिणाम पर टिप्पणियों की जांच निम्नानुसार है-

**ड 1 घरेलू उद्योग की टिप्पणियां**

130 मै0 गुआंगडोंग एयूडब्ल्यूए इंजीनियरिंग मैनुफैक्चरिंग कं0 लि0 (उत्पादक और निर्यातक) तथा गुआंगडोंग एफयूडब्ल्यूए हैवी इंडस्ट्रीज कं0 लि0, (उत्पादक और निर्यातक) दोनों संबंधित प्रयोज्यताएं हैं और इन पक्षकारों के लिए समान शुल्कों की सिफारिश की जानी चाहिए। यह नोट किया जा सकता है कि मै0 गुआंगडोंग एयूडब्ल्यूए इंजीनियरिंग मैनुफैक्चरिंग कं0 लि0 (उत्पादक और निर्यातक) तथा गुआंगडोंग एफयूडब्ल्यूए हैवी इंडस्ट्रीज कं0 लि0, (उत्पादक और निर्यातक) संबंधित प्रयोज्यताएं हैं और इन पक्षकारों के लिए समान शुल्कों की सिफारिश करने की आवश्यकता है। डी जी ए डी में ऐसी प्रथा है कि संबंधित उत्पादक/निर्यातक के मामले में डीजीएडी में ऐसी प्रथा है और हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे मौजूदा मामले में भी अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ इसी प्रथा का अनुसरण करें।

**ड 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां****विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

- एकल अदद एक्सिल देश में अधिक प्राथमिकता वाले एक्सिल हैं और ये उत्पाद यार्क श्रृंखला में उपलब्ध नहीं हैं। घरेलू उद्योग द्वारा पेश किया जाने वाला उत्पाद निकृष्ट और घटिया हैं।
- प्रतिवादी का प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि प्रतिवादी द्वारा बेचे जाने वाले और घरेलू उत्पादकों द्वारा निर्मित किए जाने वाले एग्जिल की गुणवत्ता में वास्तविक अंतर है। वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के पैरा-77 में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन उत्पादों की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है, जैसा कि "आवेदक ने निवेदन किया है कि उनके उत्पाद अपेक्षित गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं और प्रतिवादी पक्षकार के तर्क सही नहीं हैं। इसके साथ ही हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे ऐसा पता चलता हो कि आयातित विचाराधीन उत्पाद और घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पाद के बीच कोई वास्तविक अंतर व्याप्त है।

**घरेलू उद्योग का अधिकार क्षेत्र और आधार**

- प्राधिकारी यह नोट मात्र करते हैं कि कुल भारतीय उत्पादन के बारे में सूचना का अनुमान अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियों की 5 प्रतिशत मालसूची को जोड़कर लगाया गया है तथा अन्य भारतीय उत्पादकों के बिक्री के आंकड़ों को कुल भारतीय मांग से घरेलू उद्योग के आयात और घरेलू बिक्रियों को घटाकर प्राप्त होने वाले अंतर के रूप में माना गया है (कृपया प्रकट विवरण के पैरा 30 को देखें)। प्राधिकारी ने इसका कोई आधार नहीं दिया है कि उत्पादन का परिकलन करने के लिए बिक्रियों में एकपक्षीय रूप से क्यों जोड़ा जाए। वास्तव में 5 प्रतिशत को जोड़े जाने का वर्णन करना इसलिए भी अधिक एकपक्षीय है क्योंकि याचिकादाता की निजी मालसूचियां (जांच अवधि में 332 मीट्रिक टन), उनकी कुल घरेलू बिक्रियों (5201 मी0ट0) का 6.38 प्रतिशत भाग बनती है। इसके आलोक में प्राधिकारी को अन्य उत्पादकों की बिक्रियों में कम से कम 6.38 प्रतिशत को जोड़ना चाहिए ताकि अनुमानित उत्पादन का पता लगाया जा सके।
- यह अवधारणा कि मुख्य प्रवर्तक की बिक्रियों को उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, के फलस्वरूप उत्पादन के आंकड़ों का बहुत कम प्रतिनिधित्व होगा क्योंकि इनमें न बिक्र एक्सिल, प्रतिस्थापन बाजार के लिए निर्मित एक्सिल शामिल नहीं हैं तथा एसआईएम के आंकड़ों में अनेक उत्पादकों को भी शामिल नहीं किया गया है। इसलिए यह अनिवार्य है कि प्राधिकारी वास्तविक मांग, उत्पादन और बिक्री के आंकड़ों को ही प्राप्त करें। जैसा कि पहले निवेदन किया गया है कि इन परिकलनों की अड़चनें न केवल आधार के मुद्दे पर ही बल्कि क्षति का मूल्यांकन करने पर ही होती है। बाजार उत्पादन का बाजार का हिस्सा तथा अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियों जैसे प्राचल क्षति का विश्लेषण करने के लिए अति आवश्यक हैं।

**सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का परिकलन**

- प्राधिकारी ने यह बताया है कि उन्होंने बिक्री, सामान्य और प्रशासन लागत तथा उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के बाद उत्पादन की संरचित लागत के आधार पर चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य की संरचना की है। इसमें यह उल्लेख नहीं है कि उन्होंने उत्पादन की लागत का आकलन करने के लिए कच्चे माल की लागत के परिकलन पर विश्वास किया है। यह प्रतिवादी के हित के विपरीत है क्योंकि प्रतिवादी यह टिप्पणी देने में असमर्थ होंगे कि सामान्य मूल्य का आकलन कैसे किया गया है। यदि प्राधिकारी सामान्य मूल्य का परिकलन करने के लिए घरेलू कीमतों पर विचार करते हैं तो ऐसा करना उनकी विगत निजी प्रथा

के विपरीत होगा। वास्तव में विगत प्रथा के आलोक में यह अनिवार्य होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर ही विचार किया जाए।

### विविधि मुद्दे

- यार्क की कीमतें अन्य घरेलू विनिर्माताओं की कीमतों से बहुत कम हैं। यह एक कीमत निर्धारण की कार्यनीति है कि भारतीय बाजार में कारोबार का अधिक भाग प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा को दूर रखा जाए और इसका एकमात्र कारण अकेले कारोबार करने की दिशा में चलता हो सकता है।
- बाजार में यार्क द्वारा पेश की जाने वाली क्रेडिट की सीमा का अध्ययन नहीं किया गया है।
- यह भी निवेदन किया गया है कि आंकड़ों से ऐसा पता चलता है कि घरेलू उद्योग, अन्य उत्पादकों और आयातित वस्तुओं के बीच पारस्परिक प्रतिस्पर्धा हो सकती है। इसलिए प्रतिवादी इस निवेदन के आधार को समझने में असमर्थ हैं कि संबद्ध देश से आयात के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। यह अत्यधिक अविश्वसनीय है कि ऐसे आयातों से जिनका बाजार में बहुत कम हिस्सा है, का घरेलू उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे विशेष रूप से घरेलू उद्योग, अन्य उत्पादकों और आयातित वस्तुओं के बीच पारस्परिक प्रतिस्पर्धा होने का मूल्यांकन करें। विशेष रूप से उन्हें घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों के बीच पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का मूल्यांकन करना चाहिए क्योंकि आटोमोटिव एक्सिस् लि0 और जोस्ट इंडिया आटो कंपोनेंट प्रा0 लि0 जैसी अन्य एक्सिस् उत्पादन करने वाली कंपनियों ने भी अभी हाल ही में लगभग 3-4 वर्षों में अपने प्रचालन शुरू किए हैं। ऐसा विशेष रूप से आटोमोटिव एक्सिस् लि0 के संबंध में किया जाना चाहिए जिसने एक समर्थक के रूप में कीमतों जैसे अपने विवरण प्रस्तुत किए हैं।
- 22 प्रतिशत प्रतिलाभ की क्षति रहित कीमत निर्धारण, नियोजित पूंजी का मूल्यांकन और बिक्री वारंटी पश्चात समायोजन से संबंधित तीन मुद्दे हैं।

### कारणात्मक संबंध

- यह निवेदन किया गया है कि अन्य कारक जैसे कि मांग में संकुचन, लागत में वृद्धि संबंधित पक्षकारों को बिक्रियां तथा नए संयंत्र की स्थापना के कारण निर्धारित लागत/लागत में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। यह निवेदन किया गया है कि पाटित आयातों के अतिरिक्त अन्य कारकों से उत्पन्न क्षति के प्रभाव को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। कीमत में कटौती होने तथा लाभ, नकदी प्रवाह और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ के बीच किसी प्रकार का कोई सहसंबंध नहीं हो सकता है।

### ड 2 प्राधिकारी द्वारा जांच

- दो संबंधित पक्षकारों पर पाटनरोधी शुल्क की एक दर लागू करने के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन की जांच की गई है और मै0 गुआंगडोंग एफयूडब्ल्यूए इंजीनियरिंग मैनुफैक्चरिंग कं0 लि0 (उत्पादक और निर्यातक) तथा गुआंगडोंग एफयूडब्ल्यूए हैवी इंडस्ट्रीज कं0 लि0, (उत्पादक और निर्यातक) के लिए भारित औसत पाटन और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया गया है। प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि विशिष्ट पृथक विशिष्ट पाटन मार्जिन स्वीकृत करने से निर्यात करने वाले उत्पादक ऐसी कंपनी के माध्यम से भारत को कंपनी निर्यात करने शुरू कर देंगे जिनका विशिष्ट पृथक पाटनरोधी शुल्क निम्नतर है और इससे वे पाटनरोधी उपाय की प्रवृत्ति करने में सक्षम होंगे और इस प्रकार वे निष्प्रभावी हो जाएंगे। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए एफयूडब्ल्यूए समूह से संबंधित निर्यात करने वाले उत्पादकों को एक एकल प्रयोज्यता माना गया है और तदनुसार, उन्हें एक एकल शुल्क दर स्वीकृत की गई है और इस प्रयोजनार्थ भारित औसत पाटन और क्षति मार्जिन का पृथक रूप से निर्धारण किया गया है। प्राधिकारी द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी, पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त की जा सके।

- गुणवत्ता मुद्दों के संबंध में यह निवेदन है कि अनेक बार ऐसे मुद्दे का निवारण किया गया है और सेस्टेट ने भी इस मुद्दे पर ऐसे निर्णय की घोषणा की है कि गुणवत्ता समान उत्पाद का निर्धारण करने के लिए एक प्रासंगिक नहीं है, विशेष कर जबकि निकृष्ट गुणवत्ता के दावे की मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग विश्व भर में इस उत्पाद का अत्यधिक मात्रा में निर्यात कर रहा है।
- भारतीय उत्पाद का अनुमान लगाने और आधार के संबंध में यह दोहराया जाता है कि सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में कुल भारतीय उत्पादन के बारे में सूचना सुलभ नहीं थी तथा आवेदक ने कुल भारतीय उत्पादन का अनुमान लगाने की एक कार्य प्रणाली बनाई है तथा मुख्य प्रवर्तक के उत्पादन के आंकड़ों पर विश्वास किया है जिसमें ट्रेलरों को संबद्ध किया गया है जिसमें संबंधित वस्तुओं का उपयोग सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (एस आई एम) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के बदले किया जाता है जोकि भारत में संबद्ध वस्तुओं की आवश्यकता प्राप्त करने का एक आधार है और भारत में संभावित घरेलू उत्पादन का दोबारा परिकलन किया जाता है। प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने न तो उत्पादन के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और न ही किसी वैकल्पिक कार्यप्रणाली का सुझाव दिया है। उन्होंने मुख्य प्रवर्तकों के आधार पर उच्चतर मांग का सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त उत्पाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी द्वारा 5 प्रतिशत मालसूची की अवधारणा पर उचित विचार किया था। यदि ऐसे आंकड़ों को स्वीकार कर लिया जाता तो आवेदक घरेलू उद्योग का उत्पादन घरेलू उत्पादन का 47 प्रतिशत भाग बनता तथा ऑटोमोटिव एक्सिल के समर्थन से उसका उत्पादन भारत में उत्पादन का 5 प्रतिशत से अधिक होता।
- सामान्य मूल्य की संरचना करने की कार्यप्रणाली के संबंध में यह नोट किया जाता है कि यह उत्पाद विभिन्न प्रकार के संगठनों का सम्मिश्रण है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतें उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए प्राधिकारी के पास कच्चे माल (संगठकों की) खपत और घरेलू उद्योग की कीमतों को अपनाने के सिवाय और कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था जोकि नियमावली और प्रथा के समनुरूप है।
- इस तर्क के संबंध में कि यार्क की कीमतें अन्य घरेलू विनिर्माताओं की कीमतों से काफी कम हैं और भारतीय बाजार में कारोबार के प्रमुख भाग को हथियाने के लिए प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने की कीमत निर्धारण संबंधी कार्यनीति है, यह निवेदन है कि इसकी किसी भी साक्ष्य द्वारा संपुष्टि नहीं की गई है। जांच परिणाम में दिया गया विश्लेषण भी इस तर्क का समर्थन नहीं करता है।
- घरेलू उद्योग को दिए गए क्रेडिट की सीमा कार्यशील पूंजी का एक भाग बनती है जिसका उचित अध्ययन किया गया है और इसका निदान पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार डीजीएडी में अनुसरण की जा रही सुसंगत प्रथा के अनुसार उचित प्रतिलाभ प्रदान किया गया है तथा नियोजित पूंजी का मूल्यांकन किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा बनाकर रखी गई लेखा बहियों के अनुसार वारंटी/बिक्री पश्चात सेवा का निर्धारण किया गया है और इसे क्षतिरहित कीमत से बाहर रखा गया है तथा इसे विनिर्माण पश्चात व्ययों के रूप में माना जा रहा है।
- इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उत्पादकों के बीच में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि आवेदक विचाराधीन उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है और किसी भी अन्य उत्पादक से कोई विरोध नहीं है। आयातित वस्तुओं का पहुंच मूल्य आवेदक की क्षति रहित कीमत और निवल बिक्री कीमत से अत्यधिक कम है, इसलिए प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि आयातित वस्तु की कम पहुंच कीमत के कारण घरेलू कीमत निर्धारित करनी पड़ी है। इस प्रकार यह तर्क कोई मायने नहीं रखता है कि घरेलू उद्योग को क्षति होने का कारण पारस्परिक प्रतिस्पर्धा है।
- कारणात्मक संबंध न होने ने किसी अन्य सूचक के संबंध में यह नोट किया जाता है कि मांग के पैटर्न से कोई संकुचन का पता नहीं चलता है क्योंकि यह क्षति अवधि से पूर्व अवधि में हुई है और जांच अवधि के दौरान इसमें पर्याप्त रूप से तेजी आई है और यह आधार वर्ष से अधिक हो गई है। प्राधिकारी का यह मानना है कि क्षतिविश्लेषण के प्रयोजनार्थ उत्पादन की वास्तविक लागत के अनुकूलतम के पश्चात क्षतिरहित कीमत के रूप में उत्पादन की उचित लागत है और इसलिए हितबद्ध पक्षकार के ऐसे तर्क कोई मायने नहीं रखते हैं। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी सभी प्रासंगिक कारकों की संपूर्णता से जांच करते हैं तथा सभी आर्थिक प्राचलों को प्रतिकूल कार्यनिष्पादन दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है जिससे कि आर्थिक क्षति का पता चले।

हितबद्ध पक्षकार के इस तर्क के संबंध में कि क्षति संबंधित पक्षकार को विक्रियां करने के कारण हुई हैं, प्राधिकारी ने इस आरोप की जांच की है और यह पाया है कि संबंधित पक्षकार के मामले में कीमत की वसूली बमुश्किल 2.7 प्रतिशत थी। यदि क्षति के विश्लेषण में संबंधित पक्षकार की कीमत में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है तो भी कीमत कटौती पर समग्र बमुश्किल 0.7 प्रतिशत होता।

## ढ निष्कर्ष

131 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों तथा उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि-

- (क) चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के निर्यात भारत को उनके सहयोजित सामान्य मूल्य से कम पर किए जा रहे हैं।
- (ख) दोनों विचाराधीन उत्पादों में घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।
- (ग) चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण आर्थिक क्षति हुई है।

## ण. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

132 प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्यतया पाटन की अनुचित व्यावहारिक पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में ऐसे खुले और उचित प्रतिस्पर्द्धा का वातावरण बहाल किया जा सके, जो कि देश के सामान्य हित में हो। पाटन-रोधी उपाय करने से किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए इनसे उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

133. यह माना जाता है कि पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध वस्तुओं को इस्तेमाल करके विनिर्मित किए उत्पाद के कीमत के स्तर को प्रभावित हो सकते हैं और उसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों की सापेक्ष प्रतिस्पर्द्धात्मकता कुछ हद तक प्रभावित हो सकती है। तथापि, पाटन-रोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्द्धा कम नहीं होगी। इसलिए पाटन-रोधी उपाय लागू किए जाने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्द्धा कम नहीं होगी, विशेषकर यदि पाटन-रोधी शुल्क ऐसी राशि तक सीमित रहते हैं, जो कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत पाटन-रोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन की पद्धतियों द्वारा प्राप्त किए गए अनुचित लाभ समाप्त होंगे और घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट की रोकथाम होगी तथा ये उपभोक्ताओं को उनकी व्यापक रुचि की संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता को बनाए रखने में सहायक होंगे। निचले स्तर के उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यूनतम करने के विचार से प्राधिकारी ने पाटन और क्षति मार्जिन के कमतर आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना उपयुक्त समझा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लागू करने से संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए ये उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेंगे।

## त. सिफारिशें

134. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच शुरू की गई थी और इसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को दी गई थी तथा निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सार्थक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटन-रोधी नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू की गई थी और उसका संचालन किया गया था तथा सार्थक पाटन मार्जिन के साथ-साथ ऐसे पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई आर्थिक क्षति की पुष्टि हो जाने पर, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और क्षति के प्रतिकरण के लिए निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए प्राधिकारी ऐसी सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं कि नीचे वर्णित रूप में और तरीके से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाए।

135. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम मार्जिन के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार संबद्ध देश के मूल रूप की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नीचे तालिका के कालम 8 में निर्दिष्ट राशि के बराबर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है:-

## शुल्क तालिका

क्रमांक	टैरिफ की मद	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यात क देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	मापन का यूनिट	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	8716 9010	ट्रेलर्स के लिए एक्सल	चीन	चीन	गुआंगडोंग फुवा इंजिनियरिंग मैनुफैक्चरिंग कं. लि.	गुआंगडोंग फुवा इंजिनियरिंग मैनुफैक्चरिंग कं. लि.	0.16	कि.ग्रा.	अमरीकी \$
2.	8716 9010	ट्रेलर्स के लिए एक्सल	चीन	चीन	गुआंगडोंग फुवा हैवी इंडस्ट्रीज कं. लि	गुआंगडोंग फुवा हैवी इंडस्ट्रीज कं. लि	0.16	कि.ग्रा.	अमरीकी \$
3.	8716 9010	ट्रेलर्स के लिए एक्सल	चीन	चीन	शानडोंग जिनशेंग एक्सल मैनुफैक्चरिंग कं0 लि0	शानडोंग जिनशेंग एक्सल मैनुफैक्चरिंग कं0 लि0	0.14	कि.ग्रा.	अमरीकी \$
4.	8716 9010	ट्रेलर्स के लिए एक्सल	चीन	चीन	क्रमांक 1 से 3 से इतर कोई भी संयोजन		0.46	कि.ग्रा.	अमरीकी \$
5	8716 9010	ट्रेलर्स के लिए एक्सल	चीन	चीन से इतर कोई भी अन्य देश	कोई भी	कोई भी	0.46	कि.ग्रा.	अमरीकी \$
6	8716 9010	ट्रेलर्स के लिए एक्सल	चीन से इतर कोई भी अन्य देश	चीन	कोई भी	कोई भी	0.46	कि.ग्रा.	अमरीकी \$

136. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) द्वारा यथा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और उसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3 क, 8 ख, 9 और 9 क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़ कर सभी सीमा शुल्क शामिल होंगे।

137. इस अंतिम जांच परिणाम के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण) के समक्ष दायर की जाएगी।

ए. के. भल्ला , अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30<sup>th</sup> September 2016

**Final Findings**

**Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of 'Axle for Trailers' originating in or exported from China PR**

**F. No. 14/17/2015-DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time [hereinafter also referred to as the Act] and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, [hereinafter also referred to as the Rules], as amended from time to time, thereof;

**A. Background of the Case**

2. Whereas M/s York Transport Equipment (India) Pvt Ltd., (hereinafter also referred to as the "applicant" or domestic industry) filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Act and the Rules supra, for initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of "Axle for Trailers" (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country), alleging dumping and consequent injury to the domestic industry and requested levy of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject country.

3. And whereas, the Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant to justify initiation of the investigation, issued a public notice vide notification No.14/17/2015-DGAD dated 28<sup>th</sup> December, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject anti-dumping investigation, read with corrigendum dated 1<sup>st</sup> January, 2016 therein, in accordance with the sub Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**B. PROCEDURE**

4. The procedure described herein below has been followed;

- i. Preliminary scrutiny of the application showed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the Applicant. The application was, therefore, considered as properly documented. The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the Applicant to justify initiation of the investigation, decided to initiate the investigation against imports of the subject goods from the subject country.
- ii. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of rule 5 *supra*.
- iii. Post initiation, the Authority sent a copy of the initiation notification to the embassy of the subject country in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification. Necessary extensions wherever warranted was also permitted by the Authority.
- iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra. The embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from China PR.
- v. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules;

1) Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co., Ltd.

Shandong, China PR



- 2) Guangdong FUWA Engineering Manufacturing Co., Ltd.  
Guangdong Province, China PR
  - 3) Foshan Yonglitai Axle Co., Ltd.  
Guangdong, China PR
  - 4) Alion Manufacturing & Engineering Ltd  
Henan, China PR
  - 5) Guangzhou TND Axle Co. Ltd.  
Guangdong, China.
- vi. In response to the initiation notification and intimation, the following exporters / producers from China PR have responded to the Authority by filing Exporter Questionnaire Response;
1. Guangdong FUWA Engineering Manufacturing Co., Ltd.
  2. Guangdong FUWA Heavy Industries Co., Ltd.
  3. Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co., Ltd.
- vii. Out of the above responding producers/exporters from China PR, Guangdong FUWA Engineering Manufacturing Co., Ltd and Guangdong FUWA Heavy Industries Co., Ltd. have also filed the Market Economy Treatment (MET) Questionnaire to rebut the presumption of non-market economy status of China PR as per the anti- dumping rules. However, before onsite verification both Guangdong FUWA Engineering Manufacturing Co. Ltd and Guangdong FUWA Heavy Industries Co. Ltd. withdrew their claim for conferring Market Economy Status.
- viii. Questionnaires were sent to the following known importers / users of subject goods in India calling for necessary information;
1. Transtar Handling Warehousing Private Limited
  2. King Kaveri Trading Company
  3. H.D. Trailers Pvt. Ltd.
  4. Tata International DLT Pvt. Ltd.
  5. Seamless Autotech Pvt Ltd.
  6. Black Diamond Motors Pvt. Ltd.
  7. Deccan Vehicles Pvt. Ltd.
  8. ArihantAutotrends,
  9. Shivam Motors Pvt. Ltd.
  10. Transport Solutions India Pvt Ltd
  11. VandanaTrailers& Body MFG (P) Ltd
  12. Satrac Engineering Private Limited
  13. Shree Durga Fabrication
  14. Sheetal Motors
  15. V.S.Trailers
  16. Lohr India Automotive Pvt. Ltd.
  17. Tippers & Trailers India Pvt. Ltd
  18. Jagatjit Automotive Co.Pvt. Ltd.
- ix. In response, following importers/users have responded by filing Importer Questionnaire responses and submissions;
1. King Kaveri Trading Company
  2. H.D. Trailers Pvt. Ltd.

- x. Also, following importers/users responded to the Authority by making submissions/writing letters but did not file any Importer Questionnaire Responses as applicable;
1. Satrac Engineering Private Limited
  2. Safetech Trailer Parts LLP
  3. Synergic Trailer and Auto Solutions Pvt. Ltd
  4. Shivam Motors Pvt. Ltd.
  5. Black Diamond Motors Pvt. Ltd.
  6. VandanaTrailors& Body MFG (P) Ltd
  7. MS Trailer Parts LLP
- xi. The Authority made available non-confidential version of the evidences presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- xii. Fair cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the applicant on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to domestic industry or not.
- xiii. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.
- xiv. On site verification of the information provided by the domestic industry and exporters to the extent necessary were conducted at the premises of such parties who have provided the information. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, is relied upon for the final findings.
- xv. The Authority has considered 1<sup>st</sup> April, 2014 to 30<sup>th</sup> June 2015 (15 months) as the POI so as to undertake analysis on the most recent data. Thus, investigation was carried out for the period starting from 1st April 2014 to 30th June 2015 (POI). The examination of trends, in the context of injury analysis, however, covered the periods Apr'11-Mar'12 Apr'12-Mar'13, Apr'13-Mar'14 and the period of investigation.
- xvi. Import information as per secondary sources (IBIS) has been provided in the application by the applicant. Imports as per IBIS to gauge the country wise volume and value of imports of given PUC into India in various AD investigations have been relied upon by the Authority in many past investigations also. The Authority has relied upon the import data as per IBIS provided by the applicant for this final findings. However, the data was appropriately correlated with the DGCI&S data and it was noted that there was no trend deviation.
- xvii. The Authority held a public hearing on 5<sup>th</sup> May, 2016 to hear the interested parties orally, which was attended by the interested parties/ representatives. The interested parties were asked to file written submissions and rejoinders, if any.
- xviii. The arguments made in the written submissions/rejoinders received from interested parties have been considered, wherever found relevant, in this final findings.
- xix. In accordance with the Rule 16 of the AD Rules, the essential facts considered by the Authority were disclosed to the known interested parties and comments received on the same have been duly considered, wherever found relevant, in this final findings.
- xx. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the present final findings on the basis of the facts available.
- xxi. \*\*\*In this final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxii. Exchange rate for conversion of US\$ to Rupees considered for the POI is Rs 62.13 per 1 US\$ as per customs data.

## **C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

### **C.1 Submissions made by the domestic industry**

5. The product under consideration in the present investigation is 'Axle for Trailers' originating in or exported from China PR.
6. An 'Axle for Trailer' is essentially an assemblage of a beam/bar and other components such as brake drum, brake shoes, bearings etc which connects two wheels of a Trailer and renders the functions as an axle for the Trailer.
7. The subject goods are manufactured and sold in different variants. However, the basic product characteristics and end use of all these variants remains the same and all such types of Trailer Axles is covered in the scope of the PUC since these variants constitute a homogenous PUC with comparable basic characteristics and similar functions/uses.
8. Product under consideration is a vehicle (Trailer) part and accessory, falling under Chapter 87 of the Customs Tariff Act, 1975 and further classified under custom sub-heading no. 87169010. Since the subheading is not a dedicated classification, the applicant has submitted that the customs classification is indicative only and in no way, binding upon the product scope. However, Axles for vehicles other than the Trailers are excluded from the scope of PUC. It has also been submitted by the applicant that the Axles can be broadly categorised into Drive or Live Axles and Dead or Dummy Axles. PUC falls under the Dead or Dummy Axles category and Drive or Live Axles are outside the purview of the present investigation.
9. The subject goods, which are being dumped into India, are identical to the domestic like product produced by the domestic industry. There is no known difference in applicant's product and subject goods exported from the subject country and are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods and there is no significant difference in the subject goods produced by the applicant and those exported from the subject country and both are technically and commercially substitutable.

### **C.2 Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties**

10. The Respondent submits that there are material differences in quality of the axles sold by the Respondents and the one produced by the domestic producers. In particular, the axle of the Respondent is a unique one-piece produced by FUWA Engineering Group Ltd. (which has 80% market share in China PR as per Market intelligence) using One-Piece Beam with Hot Forming Spindles Technology as opposed the welding of four (4) individual parts by the domestic industry. The latter is weak/ not stable and market intelligence suggests that it has succumbed to daily usage. Besides this, the axles sold by the Respondents also have advantages in relation to suspension functions and maintenance costs. Market intelligence suggests that there is huge customer dissatisfaction in relation to the Axles produced by the domestic industry.
11. One of the responding interested parties disputed the scope and description of the product under consideration saying there are two types of Axles i.e. live or drive axles and dead or dummy axles and PUC is only dead or dummy axles and to this extent the initiation notification has exceeded the powers conferred and is void to that extent. It has been submitted by KKTC also in its rejoinder submission that the scope of PUC and like article may be decided by the Authority based on the merits of the case.

### **C.3 Examination by the Authority**

12. The Authority notes that the product under consideration in the present investigation is 'Axle for Trailers' originating in or exported from China PR. The Authority also noted that the subject goods are manufactured and sold in different variants. However, the basic product characteristics and end use of all these variants remains the same and all such types of Trailer Axles are covered in the scope of the PUC. It has been observed that all such variants essentially constitute a homogenous product under consideration with comparable basic characteristics and similar functions/uses.
13. The Authority also notes that the product under consideration is a vehicle part and accessory, falling under Chapter 87 of the Customs Tariff Act, 1975 and further classified under custom sub-heading no. 87169010. However, since the subheading is not a dedicated classification, the customs classification is indicative only and not binding on the product scope determined for this investigation.
14. With regard to objection on the scope and description of the product under consideration the Authority notes that the initiation notification defined the PUC unambiguously as 'Axle for Trailers' and Axles for vehicles other than trailers are excluded from the scope of PUC and all other submission made by the applicant and other interested parties have also been examined.

15. Rule 2(d) of the AD Rules defines like article as follows:

*“an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has the characteristics closely resembling those of the articles under investigation”.*

16. The Authority has examined the claims and notes that there is no known difference in subject goods produced by the domestic industry and exported from subject country. The subject goods produced by the domestic industry and that imported from subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. In view of the above, the subject goods produced by the applicant are being treated as domestic like article to the product under consideration imported from subject country in accordance with Rule 2 (d) *supra* of the anti-dumping Rules.

#### **D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

##### **D.1 Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties**

Various submissions made by the exporters/importers/users/other interested parties with regard to domestic industry and standing considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:

- i. The claim of total Indian production of subject goods by the applicant does not appear to be correct.
- ii. There is substantial replacement market even exceeding the new vehicle segment for the product and there are small scale producers operating from places like Ludhiana and production for such market and producers is not been considered.
- iii. TATA Group has imported and also indigenously procured raw materials which are nothing but third party imports under TATA brand. The Authority may check whether such indigenous procurement is actually made in India or not.
- iv. The group company of the applicant i.e TATA Motors must have participated in the application.
- v. The estimated figures of Indian production have not been provided.
- vi. The Petitioner has not explained how the Petitioner has arrived at the estimates and it is not possible to understand how the Petitioner has arrived at estimates of Indian production (Estimated production by other Indian producers) based on the requirement of sales of axles as provided in their written submission.
- vii. The demand in India is incorrectly shown in the Petition. As per the data obtained by “SIAM”, the number of axles and their quantity (in MT) required in India has been calculated for the financial years 2012-2013, 2013-2014 and 2014-2015 which is as follows;

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	POI Annualised
Demand – as stated in the Petition	MT	13,892	8,762	16,639
Demand - Calculated as per SIAM Data	MT	18,593	13,109	27,644

- viii. There is gross discrepancy in the demand and the figures provided by the Petitioner are incorrect and without any evidentiary support. It must also be noted that there are producers of trucks who are not part of SIAM and their data is not included. This suggests that the demand is much higher than what is represented.

- ix. In light of the under-reporting of the total production figures, the share of the Petitioner in the domestic produce becomes further suspicious. This is highlighted by the fact that the share of production is merely 47 % in the POI even if one assumes that sales of prime movers can be used to calculate the production of axles. The same can be verified from the Table below:

Particulars	Unit	
Demand of axles (determined based on the sales of the prime movers)	MT	27, 644
Imports	MT	6,600
Production in India (Demand – Imports)	MT	21,044
Production of the Domestic Industry (as given in the Petition)	MT	9,959
Share in the domestic production (Production of DI/	MT	47.3%

- x. The Petition is supported by Automotive Axles Ltd. However, it must be noted that the supporting company is not a regular producer of Axles and produces axles only when a demand is raised.
- xi. Support by Automotive Axles Ltd is suspicious.
- xii. It is suspected that the Petitioner's output may not be a major proportion of the total domestic production.
- xiii. The Statutory Order relied on by the Petitioner is not helpful – it does not provide the number of axles required in trailers but specifies Maximum Safe Axle Weight based on the kind of vehicles that existed in 1996. The market realities were different 5 years ago where single axle trailers were popular and double axle trailers were predominantly used in all trailers.
- xiv. It must be noted that single axle trailers are being rarely used; and, if used, are not being used on public roads at all. Even if one is to assume that 10% of trailers attached to prime movers have a single axle, the estimate that 80% use 2 axles is completely contrary to market realities.
- xv. The estimate of the Petitioner that 10% of prime movers use 1 axle in the trailer, 80% use 2 and the remaining 10% use 3 is incorrect. Consequently, the total axle requirement i.e. 57,472 which has been arrived at by the Petitioner is incorrect.
- xvi. The assumption that the sales of the prime movers can be used to estimate the production will lead to a severe under-representation of the production figures as it does not account for Un-sold axles are not taken into account, Axles produced for replacement market are not taken into account, and SIAM does not include many producers of prime movers.

#### **D.2 Submissions made by the domestic industry**

17. Various submissions made by the domestic industry with regard to domestic industry and standing and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:
- The application has been filed by M/s YORK Transport Equipment (India) Pvt. Ltd on behalf of domestic industry. M/s York Transport Equipment (India) Pvt. Ltd. is the largest Indian manufacturer of the subject goods. The application has been supported by Automotive Axles Ltd. The production of the applicant companies constitutes "a major proportion" in the domestic production. The Authority, therefore, may treat applicant companies constitute eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti-Dumping Rules.
  - Apart from the applicant and the supporting company, following companies are also involved in the production of subject goods, either for market or for captive consumption. The other producers have neither supported nor opposed the present investigation as per our knowledge;
    - TATA Motors Ltd
    - Ashok Leyland Ltd
    - JOST India Auto Component Pvt. Ltd.
    - G.S. Auto International Ltd.

- iii. The information provided would show that the applicant is the largest producer of the subject goods in India and commands a major proportion in the total Indian production and fulfils the standing thresholds. While the injury information is based on the applicant alone, another Indian producer namely M/s Automotive Axles Ltd has supported the application/petition.
- iv. Certain opposing interested parties have raised some counter claims so as to dispute the submissions of the domestic industry on standing and its eligibility as the domestic industry. However, the Authority may note that such rival submissions are not factually correct and are based on an inflated estimation of total Indian production of subject goods which is not correct in view of the real picture of Indian production of subject goods.
- v. The opposing interested party i.e. KKTC has premised their argument on a factual misinterpretation of certain data published by SIAM with regard to production of prime movers in India requiring subject goods in terms of tonnage of such trailers which can be broadly divided into trailers of 35 Ton and 40 Ton and above. KKTC in their submissions has considered the data precisely as follows;

Particular	Nos of prime movers based on SIAM as per KKTC
	2014-15
<b>35 ton</b>	
Ashok Leyland	1,937
AMW Motors	1
Eicher	61
Mahindra & Mahindra	74
Tata Motors	3,292
Total Prime mover all requiring Trailer Axles	<b>5,365</b>
<b>40 ton and above</b>	
Ashok Leyland	8,044
AMW Motors	113
Eicher Volvo	316
Mahindra & Mahindra	402
Tata Motors	13,916
Total Prime mover all requiring Trailer Axles	<b>22,791</b>
<b>Total Axle requirement based on production of Prime movers as per KKTC Total = (5365*2+22791*3)</b>	<b>79,103</b>

- vi. The Indian production data as per KKTC's submissions shows that KKTC has presumed that all 35 Ton prime movers have invariably 2 axles fitted in the trailers attached to it and all 40 Ton and above have 3 axles fitted in the trailers attached to it and they have derived the requirement of axles based on such presumption which is not the reality. KKTC multiplied 5365 numbers of Prime Movers with number of axles at 2 and 22791 Prime Movers with number of axles at 3 to reach to a total requirement of 79103 axles during 2014-15. In a way, KKTC claimed that single axles are not at all used in trailers of 35 Ton and above which is not correct.
- vii. We dispute and deny the highly presumptuous estimations of KKTC to exaggerate the production figures to suit their argument and on the contrary we wish to reproduce the below data for the consideration of the Authority which is based on facts and realities of the market vis-à-vis how the subject goods are produced and sold in India. There are broadly three aspects which have been conveniently forgotten by KKTC while deriving the very high number of axle requirements as above to dispute the standing of the applicant which is discussed herein below.
- viii. The claim of KKTC amounts to a submission that no trailers of 35 Ton and above uses single axle in it. This is evident from certain snippets of trailers provided to show that there are

trailers using single axle though the tonnage is 35 and above. This it-self shows that the argument of KKTC is incorrect and the Indian production calculation of KKTC is untenable. Also, single axles can also be used in a wide range of tonnages including 40 and above etc.

- ix. Another impurity in the claim of KKTC is that they have claimed trailers of 40 tonnage and above invariably use 3 axles and it is even claimed that there is a statutory requirement to use 3 axles mandatorily for 40 tonnage and above. In this regard, the applicant places its reliance on the notification S.O.728 (E), dated 18.10.1996 notified by Ministry Of Road Transport And Highways concerning Specification of Maximum Gross Vehicle Weight and the Maximum Safe Axle Weight. This notification clearly shows the presumption adopted by KKTC that above 40 Ton trailer invariably requires 3 axles is an incorrect argument. There can be 2 axles in trailers above 40 Ton weight and so on and so forth as per the said notification and that is the market reality too. Two axles are also widely used in 40 Ton and above trailers. On this basis also, the calculation of KKTC deriving huge requirements of subject goods is untenable.
- x. A third point which was not considered by KKTC is that the conversion of number of prime movers directly into new axle requirement is not correct since some prime movers market is captured by used axles and used railway axles and the evidences of the same is also provided to the Authority. In totality, the axle number derived by KKTC is not as per the facts and reality and cannot be based upon for a fact finding exercise by the Authority as the same is highly distorted and self- serving. Thus, the applicant denies the numbers of total requirement of Trailer Axles as put forward by KKTC since the same is not in sync with the reality.
- xi. The applicant has also pursued the SIAM data available in detail for the period 2014-15 and 1st Qtr of 2015-16 concerning production of Prime Movers so as to estimate the Axle requirements in the Trailers supposed to be connected with such Prime Movers to first estimate the requirement of subject goods and based on which total Indian production of subject goods during the POI;

Particular*	Prime Mover Production (As per SIAM Data)		
	2014-15	Q1 15-16	POI
<b>35 ton</b>			
Ashok Leyland	1,937	592	2,529
AMW Motors	1	6	7
Eicher	60	14	74
Mahindra & Mahindra	72	17	89
Tata Motors	3,292	699	3,991
Total Prime mover all requiring Trailer Axles	<b>5,362</b>	<b>1,328</b>	<b>6,690</b>
<b>40 ton and above</b>			
Ashok Leyland	2,663	661	3,324
AMW Motors	108	10	118
Eicher Volvo	267	99	366
Mahindra & Mahindra	402	177	579
Tata Motors	13,916	3,743	17,659
Total Prime mover all requiring Trailer Axles	<b>17,356</b>	<b>4,690</b>	<b>22,046</b>
<b>Total Axle requirement based on production of Prime movers as per SIAM Total = (10%*1+80%*2+10%*3)</b>	<b>45,436</b>	<b>12,036</b>	<b>57,472</b>

- xii. It is our reasonable estimate that 10% of the prime movers have been having single axle trailer connected to it, 80% of the prime movers were having 2 axle trailers and another 10% required 3 axle trailers across the 30 Ton and above 40 Ton category. The table above on that basis shows the requirement of Axles at about 57,472 pieces in the POI.
- xiii. The total Indian production derived in terms of numbers and the share of the applicant is provided in the table below which shows the share of YORK in the total Indian production has been 63.20% which clearly shows YORK fulfilled the standing requirements as stipulated in the AD rule and production by YORK constitutes a major proportion in the total Indian production. It may also be noted that some part of such requirement have been in fact fulfilled by used and used railway axles which is not figured in our calculation also and inclusion of the same would further reduce the number of total new axle requirement during the POI. Taking such axles also into consideration will make the share of York even higher in the total estimated Indian production of subject goods.

Particular	Requirement of Axles as per Prime Movers data by SIAM- Qty in Nos		
	2014-15	Q1 15-16	POI
Axle Requirement	45,436	12,036	57,472
Imports From All countries	17,918	5,157	23,075
Axles Sold By Indian Producers	27,518	6,879	34,397
Petitioner's Domestic Sales	14,834	3,846	18,680
Estimated Sales by other Indian Producers	12,684	3,033	15,717
Estimated Production by other Indian Producers	13,352	3,193	16,544
Production by York	22834	5584	28,418
Total Indian Production			44,962
<b>Share of YORK</b>			<b>63.20</b>
<b>Share of YORK along with supporter</b>			<b>69.60%</b>

- xiv. The applicant has provided the details of all known producers of the subject goods in India and a reasonable methodology was adopted to gauge the total production of subject goods in India during the POI, thus, there are adequate evidences available to test the accuracy of claims of standing by the applicant. All bonafide efforts are taken by the applicant to bring on record the factual position of its standing before the Authority. Notwithstanding this, the Authority may write to all the other Indian producers and ask them to disclose the actual production of subject goods by them during the POI. Also, as an alternative option, the Authority may write to the concerned Excise department to provide the details of production of subject goods by such other companies during the POI. In the absence of actual information of production by such producers and their cooperation, the claims made by the applicant should be considered as correct and reliable and all the arguments by the opposing parties in this regard should be rejected.
- xv. An argument has been raised by the interested parties that TATA Motors Ltd is a 'related party' of the applicant and should have participated in the present investigation. However, the contention has no legal or factual tenability. The Annual Reports of TATA Motors Ltd is available in the public domain and also that of the applicant. The annual reports would clearly show that both the companies are separate legal entities under different holding companies and does not fall into the ambit of 'related party' as coined by the interested parties wherein YORK exercises some power to ask TATA Motors to participate in the present investigation. As far as YORK is concerned TATA Motors or any other producer are open to either support the petition or oppose it and YORK doesn't have any say on any of their decisions. YORK fulfils the requirements of Rule 2 (b) and discussion on participation or non- participation of TATA Motors have no consequences under the rule governing constitution of domestic



industry. The rule provides in essence for express support of producers having not less than 25% of the total production and with support more than 50 % of the total production of the like article [ Rule (5) (3) (a) and (b) read with explanation]. In the present case, YORK alone has more than 63% share in the total Indian production.

- xvi. Based on the facts as available, it is reiterated and submitted that M/s YORK Transport Equipment (India) Pvt. Ltd have the required standing and should be treated as the 'domestic industry' for the purpose of present investigation and the relevant findings.
- xvii. With regard to the claim of opposing parties that the claim of total Indian production of subject goods by the applicant does not appear to be correct and there is substantial replacement market even exceeding the new vehicle segment for the product and there are small scale producers operating from places like Ludhiana and production for such market and producers is not been considered it is submitted that the contentions are incorrect. The PUC does not have any significant replacement market because the life of an Axle is equal to that of a Trailer or more. Also, there is no quantified information about small producers running some production provided by the opposing party and such conjectures have no evidentiary value.
- xviii. With regard to the contention that TATA Group has imported and also indigenously procured raw materials which are nothing but third party imports under TATA brand and the Authority may check whether such indigenous procurement is actually made in India or not, it is submitted that the contention has no relevance since the applicant is a separate legal entity and is not a related party.
- xix. With regard to the contention that the group company of the applicant i.e TATA Motors must have participated in the application, it is submitted that the applicant fulfils the standing requirement under AD rule and in any case TATA Motors Ltd is not a related entity within the eyes of the law.
- xx. With regard to the contention that the estimated figures of Indian production have not been provided and the Petitioner has not explained how the Petitioner has arrived at the estimates and even if production of Prime Movers is to be taken as the basis to gauge production of subject goods then also the share of applicant is about 47% only, it is submitted that the opposing parties admits that the applicant alone holds about 47%. The information held as confidential is as permissible under that rule and justification for such claims is provided in the application.
- xxi. With regard to the contention that the Petition is supported by Automotive Axles Ltd, however, it must be noted that the supporting company is not a regular producer of Axles and produces axles only when a demand is raised and Support by Automotive Axles Ltd is suspicious, it is submitted that the claims are baseless. There is an express support letter provided by Automotive Axles Ltd. Also, there is no factual or legal basis in the claim that Automotive Axles Ltd is not a regular producer.
- xxii. With regard to the contention that it is suspected that the Petitioner's output may not be a major proportion of the total domestic production, it is submitted that such suspicions are out of place since the evidences shows the applicant holds majority in the Indian production. In fact, it is admitted by the opposing parties that York is the largest producer of subject goods in India.

#### **D.3 Examination by the Authority**

- 18. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under;
 

*“(2) (b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”*
- 19. It is noted that the application based on which the present anti-dumping investigation is initiated has been filed by M/s York Transport Equipment (India) Pvt Ltd on behalf of the “domestic industry” concerning the subject goods in India. It is found that the applicant M/s York Transport Equipment (India) Pvt. Ltd is the largest Indian manufacturer of the subject goods. Also, M/s Automotive Axles Ltd has expressly supported the application.

20. Apart from the applicant producer and the supporting producer as above, the applicant identified following companies as producers of subject goods in India either for captive purposes or for the merchant market.
- TATA Motors Ltd.
  - Ashok Leyland Ltd.
  - JOST India Auto Component Pvt. Ltd.
  - G.S. Auto International Ltd.
21. The Authority notes that none of the other producers above have responded to the investigation. Hence these companies neither support nor oppose the application. The explanation to Rule 5 states that "For the purpose of this rule the application shall be deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry, if it is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty per cent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition, as the case may be, to the application." In the present case support to application constitutes a major proportion of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition.
22. It has also been observed that the information about total Indian production is not readily available in the public domain and the applicant has devised a methodology to estimate the total Indian production and the share of the applicant alone and with the supporter in such estimated total Indian production. It has relied upon production data of Prime Movers to which Trailers are attached wherein the subject goods are used which is published by the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) as a basis to derive the requirement of subject goods in India and to back calculate the probable domestic production in India. SIAM data has been made available for the entire POI. Out of the total number of production of prime movers reported by SIAM, the applicant has considered about 10% as having requirement of 1 Axle in it and considered 80% as requiring 2 Axles and the remaining 10% having a requirement of 3 Axles. The number of Prime Movers considered for the POI involved various types of Trailers such as 35 Ton, 40 Ton etc. The data below on the basis as provided herein above shows the following position vis-à-vis share of the applicant alone and also along with the supporter in the total Indian production. The below table is self-explanatory as to the basis of such estimation;

Particular	Requirement of Axles as per Prime Movers data published by SIAM and as claimed by the applicant- Qty in Nos		
	2014-15	Q1 15-16	POI
<b>Axle Requirement (A) (Prime Movers production into 10%*1+80%*2+10%*3 as explained herein above)</b>	45,436	12,036	57,472
Imports From All countries (B)	17,918	5,157	23,075
Axles Sold By Indian Producers (A-B)	27,518	6,879	34,397
Petitioner's Domestic Sales	14,834	3,846	18,680
Estimated Sales by other Indian Producers	12,684	3,033	15,717
Estimated Production by other Indian Producers	13,352	3,193	16,544
Production by York	22834	5584	28,418
Total Indian Production			44,962
Share of YORK			63.20
Share of YORK along with supporter			69.60%

23. The above information shows that the applicant alone constitutes 63.20% of the total Indian production and along with the supporter the share is about 69.60%. Since the production of the applicant accounts for "a major proportion" in the total production of the subject goods in India on such basis as evident

from detailed examination, the Authority finds that the applicant satisfies the standing criteria and constitutes domestic Industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules.

24. Even if the estimates as given by the responding parties are taken as the basis, the applicant is the largest producer of subject goods in India and the applicant alone constitutes about 47% share. Thus the production of the petitioner along with the support of automotive axle exceeds 50% of the total Indian production. Moreover, the Authority has not received any response by such other known producers. Hence these companies neither support nor oppose the application. Thus in the present case support to application constitutes the major portion of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition. In this scenario, it is noted that there are no evidences available on record to reject the submissions of the domestic industry vis-à-vis their share in the total Indian production.
25. With regard to the argument that there is substantial replacement market even exceeding the new vehicle segment for the product and there are small scale producers operating from places like Ludhiana and production for such market and producers is not been considered, it is noted that the claims are unsubstantiated and no evidence to substantiate such claims are provided. It is also noted that the applicants submitted that there is not any significant replacement market for the subject goods. There is also evidence of preference and utilisation of old axle in the manufacturing of Trailers by some of the trailer manufacturers indicating life of axle is higher than the trailer and hence the contention of the respondent interested parties is rejected.
26. With regard to the contention that TATA Group has imported and also indigenously procured raw materials which are nothing but third party imports under TATA brand and the Authority may check whether such indigenous procurement is actually made in India or not, such contentions are not supported by any pursuable evidences.
27. With regard to the contention that the group company of the applicant i.e TATA Motors must have participated in the application, it is noted that M/s York Transport Equipment (India) Pvt Ltd along with the supporter is found to be the domestic industry in the present investigation as per Rule 2 (b) and the rule does not mandate anything as submitted by the other interested parties other than requirements of rule 2(b). It is also noted that the applicant has submitted that TATA Motors Ltd is a different legal entity and not a related party as envisaged in the rules in any case and the applicant satisfies the requirement of standing. On examination of the share holding pattern of the company it was observed and found that the company York Transport Equipment(India) Pvt Ltd. is held by York Transport Equipment(Asia) Pte. Ltd, Singapore which in turn is held by TRF Singapore Pte. Ltd, Singapore. TRF Ltd, India is the holding company of TRF Singapore Pte. Ltd, Singapore. The shares of TRF Ltd, India are mainly held as follows: 34.29% by Tata Steel Ltd and 0.02% by Tata Industries Limited i.e. promoter and promoter group and the rest is public shareholding. The common shareholding promoter between Tata Motors Ltd and TRF Ltd, India are Tata Steel Ltd and Tata Industries Limited and they respectively hold 2.90% and 2.50% of shares in the Tata Motors Limited. Hence it is wrong to presume Tata Motors Ltd. and York Transport Equipment (India) Pvt Ltd. are related companies as per Rule 2 (b) of the Anti-Dumping rules.
28. However, it is found that TATA International DLT Private Limited and York Transport Equipment(India) Pvt Ltd. are related companies and they have some common Directors. It is also noted that TATA International DLT Private Limited has given declaration that they have not imported the subject goods from subject country. Also TATA International DLT Private Limited is not involved in the production of the subject goods. Hence M/s York Transport Equipment (India) Pvt Ltd along with the supporter is found to be the domestic industry in the present case and there is a declaration provided by the applicant that they have not imported the subject goods from subject goods directly or through any related party per Rule 2 (b) of the Anti-Dumping rules.
29. With regard to the contention that the estimated figures of Indian production have not been provided, the Authority notes that information about total Indian production has been estimated by adding 5% inventory to the sales of other Indian producers. The sales figure of other Indian producers is taken as the difference between total Indian demand minus import of subject goods and domestic sales of the Domestic Industry.
30. With regard to the contention that the Petitioner has not explained how the Petitioner has arrived at the estimates, the Authority notes that the petition and subsequent submissions by the domestic industry is self-explanatory on this aspect.
31. With regard to the contention that even if production of Prime Movers is to be taken as the basis to gauge production of subject goods then also the share of applicant is about 47% only, the Authority notes that this submission of other interested parties shows that the claims of domestic industry along

with the support of automotive axle exceeds 50% of the domestic production and the details of claims of the domestic industry are already provided and discussed herein above.

32. With regard to the contention that the Petition is supported by Automotive Axles Ltd and it must be noted that the supporting company is not a regular producer of Axles and produces axles only when a demand is raised, the Authority notes that M/s York Transport Equipment (India) Pvt Ltd along with the supporter is found to be the domestic industry in the present investigation as per Rule 2 (b). It is also noted that PUC is normally produced against orders and the interested parties has not provided any evidence as to why M/s Automotive Axles Ltd should not be considered as regular producer of subject goods.
33. With regard to the contention that support by Automotive Axles Ltd is suspicious, it is noted that such contentions are unsubstantiated since a support letter from the supporting company is available on record of the Authority.
34. With regard to the contention that it is suspected that the Petitioner's output may not be a major proportion of the total domestic production, it is noted that such conjectures have no evidentiary value in Anti-Dumping investigations and the facts as above shows that the application fulfils the requirement of standing.

## **E. CONFIDENTIALITY**

### **E.1 Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties**

35. Certain submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties with regard to confidentiality and disclosure of information considered relevant by the Authority are as follows:
  - i. Petitioner has indulged in excessive confidentiality in the Petition, which is in violation of Article 6.5 of the WTO ADA and Rule 7(2) of the AD Rules.
  - ii. Parameters prescribed in Proforma IVA have been either kept confidential, sketchy or not provided at all, not even in indexed form and such information is critical in analysing causal link as well as ascertaining whether the domestic industry has suffered any injury.
  - iii. The annual reports of the petitioning companies are readily available on Ministry of Corporate Affairs ("MCA") website on the payment of a nominal cost. The same have not been provided. In the absence of such data, the Respondent cannot effectively rebut the allegations of injury to the Petitioning Companies.
  - iv. The details in the letters of support by Automotive Axles Ltd. have been redacted and the details have not even been provided in an indexed form when similar details have been provided for the Petitioning companies.

### **E.2 Submissions made by Domestic industry**

36. Certain submissions made by the domestic industry with regard to confidentiality and disclosure of information and considered relevant by the Authority are as follows:
  - i. Excessive Confidentiality in submissions was adopted by opposing parties. Even though we are not sure which is the correct IQR by KKTC, both the IQRs on record as well as the preliminary injury submission filed by the company suffers from excessive use of confidentiality without any justification.
  - ii. The petitioner has disclosed all the volume information in its petition and a meaningful summary were provided wherever applicable. But KKTC has not provided the actual details of import volume and not even a summary on their import prices were provided. Thus, KKTC has resorted to make baseless allegations of excessive confidentiality on the petitioner when the fact of the matter is that KKTC has not disclosed even the rudimentary information to the petitioner.
  - iii. KKTC disclosed some information in their first set of IQR and the same was treated confidential in the second set of IQR. This shows the hollowness of confidentiality argument by KKTC. KKTC should disclose actual information about their imports so that meaningful rebuttals can be provided by us. Thus, it is submitted that KKTC has resorted to excessive confidentiality depriving the petitioner from offering meaningful comments which is completely against the confidentiality provisions provided in the AD Rules.
  - iv. KKTC has kept considerable information confidential without providing any justifiable reasons. This is not permissible under the Rules as can be seen from the provisions above. Certain

instances of information which has been withheld under the garb of confidentiality are as follows:

- a. Information on total volume of imports from subject country
- b. Average price  
of imports from subject country
- c. Holding Company details
- d. Volume information on utilization of product imported
- e. P&L account not provided, not even the Registrar of Companies version of P/L is provided etc.
- f. Information on alleged imports of axle/central beam by the petitioner as per Annexure 1 of preliminary injury submission restricting us to provide any meaningful comments to such baseless allegations
- g. Annexure 3 and 3A is also nothing but some price comparison which is also held confidential restricting our rights to offer meaningful rebuttals
- v. We submit that the above list of information, though not complete, show some information which should not have been held as confidential by KKTC. While the rules require the parties providing information on a confidential basis to furnish non-confidential summary thereof, KKTC has resorted to a methodology convenient to them and literally restricted the petitioner from gauging the factual position with regard dumped imports made by them. Excessive confidentiality adopted by KKTC also contravenes the findings of the Appellate Body in European Communities-Anti-Dumping Measures on certain Iron or Steel Fasteners from China (WT/DS 397/AB/R dated 15th July, 2011) wherein the Appellate Body has interpreted Articles 6.5 and 6.5.1 of the Anti-dumping Agreement concerning confidentiality.
- vi. Excessive confidentialities were adopted by the participating exporters also and no appropriate summary of information held confidential in EQ Response and MET Response has been provided to the applicant. Very basic information such as complete legal form of the company, shareholders name, name of the related parties involved in the PUC, contact details etc are all kept confidential that too when the company is claiming MET status. This is impermissible.

### **E.3 Examination by the Authority**

37. Various submissions made by the interested parties with regard to confidentiality/disclosure of information and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:

38. With regard to confidentiality of information Rule 7 of Anti-Dumping Rules provides as follows: -

*Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules and (7) of rule 6, sub-rule (2), (3) (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.*

39. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

40. With regard to a contention that annual reports of the petitioning companies are readily available on Ministry of Corporate Affairs ("MCA") website on the payment of a nominal cost and the same have not been provided and in the absence of such data, the Respondents cannot effectively rebut the allegations of injury to the Petitioning Companies, the Authority notes that the Annual Reports of the applicant are available in the public file and the same is also available on the website of the applicant as provided in the application. Thus, the contention has no merit.

**F. MISCELLANEOUS ISSUES**

**F.1 Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties**

41. Certain miscellaneous submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties considered relevant by the Authority are as follows:
- i. Any AD investigation can be initiated upon the Designated Authority satisfying himself of the existence of sufficient evidence as per Rule 5 (3) (b) of the AD Rules. However, in the present case the applicant did not establish any ground to initiate the investigation and there are serious deficiencies in the petition which has handicapped the opposing parties from making their submissions.
  - ii. In the updated petition, only the Annexure have been updated. There is no change in the figures and the analysis in relation to injury parameters.
  - iii. No clarity as to how the IBIS transaction-wise raw import data provided by the Petitioner is being used. The Petitioner should provide the IBIS transaction-wise raw import data as well as sorted import data to the Respondent in MS-Excel format. The Authority is also requested to direct the Petitioner to provide an explanation as to how it has sorted import data from the raw import data as it is vital to analyse the trend of the imports of the subject product into India during the POI and the injury analysis period.
  - iv. Petitioner has mentioned that whenever the unit in terms of kilograms (KG) is not available in the import data, the Petitioner has converted the same into equivalents of weight using standard weight of the PUC. However, there is no mention of what the standard weight is and how the same has been arrived at.
  - v. There are gross mis-declarations/suppressions in the Petition. The Petitioner has stated central or axle beam constitutes the significant part of the subject goods and no such product has been purchased or even imported to complement the product line. However, this information is not correct. On a number of occasions, the Petitioner has imported the central/axle beam from China PR. The same is clearly evidenced by the import records obtained from a reliable source.
  - vi. York Transport Equipment (India) Pvt. Ltd., a TATA enterprise has two related companies in India namely Tata Motors Ltd and Tata International Pvt., Ltd which are dealing with the product concerned. These parties did not file any response or did not join the application. This has vitiated the domestic industry chain as applied in the case of exporters.
  - vii. In case an exporter does not file Questionnaire Response of its related producer in subject country even though it has not exported the subject goods, DGAD in the past several cases have rejected the response of participating exporter. The same analogy should be applied in the instant investigation also.
  - viii. It has been stated that Yorks has two related producers of subject goods in China PR. Mere statement by Yorks that related companies in China namely Qungdao YTE Special Products Co. Ltd. and York Transport Equipment (Shanghai) Co. Ltd., China have not exported the subject goods is not sufficient. These related companies' must have filed questionnaire response themselves or should have given details of its sales to establish that these companies have not exported the subject goods to India.

**F.2 Submissions made by Domestic Industry**

42. Certain submissions made by the domestic industry with regard to miscellaneous issues and considered relevant by the Authority are as follows:
- i. Some interested parties attended the oral hearing and made submissions, however, did not reproduce their oral submissions in writing. We request the Authority not to consider such oral submissions which are not subsequently reproduced in writing for the purpose of present investigation in view of Rule 6 (6) which says such oral information shall be taken into consideration by the Designated Authority only when it is subsequently reproduced in writing.

- ii. King Kaveri Trading Company (at place also written as King Kaveri Trading Co) has filed multiple IQRs through different legal representative and there is no confirmation as to which is the correct IQR which should be relied upon.
- iii. There is no basis to the argument that the petitioner should provide the raw as well as sorted transaction wise data in the excel format. The requirement is only to give a summary of import volume and price and rest of the arguments have no support of law. Notwithstanding this legal position which is reflected in various findings of the Authority, the petitioner has provided transaction wise import data in Annexure 1.4 of the petition by clearly identifying the PUC and Non PUC items. Also, there is no basis to the argument that standard weight of conversion was not provided. In fact, the transaction wise data contains both number of pieces and weight derived wherever applicable meaning thereby standard weight was also disclosed.
- iv. We reiterate our submission that certain purchases of minor components were made by the company and those purchases are reflected in our raw material purchase records. It is also submitted that the import data as per Zaub.com supplied by KKTC do not show that York imported central axle/beam from China PR. In any case the imports appearing in the annexure 1 enclosed by KKTC is apparently of minor components.

### **F.3 Examination by the Authority**

43. Various submissions made by the interested parties with regard to miscellaneous issues and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:
- i. With regard to the contention that in the present case the applicant did not establish any ground to initiate the investigation and there are serious deficiencies in the petition which has handicapped the opposing parties from making their submissions, the Authority notes that the investigation was initiated based on a well-documented application and after satisfying prima facie the adequacy and accuracy of the information concerning alleged dumping and injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury.
  - ii. With regard to the contention that in the updated petition, only the Annexure have been updated and there is no change in the figures and the analysis in relation to injury parameters, it is submitted that the POI was extended to make it more recent by the Authority and dumping and injury information pertaining to the extended POI has been provided to all the interested parties.
  - iii. With regard to the contention that no clarity as to how the IBIS transaction-wise raw import data provided by the Petitioner is being used and the Petitioner should provide the IBIS transaction-wise raw import data as well as sorted import data to the Respondent in MS-Excel format it is noted that there is no requirement under the rule to provide import data in a particular format including MS Excel. With regard to the methodology, it is seen that Part I of the application is self-explanatory on how the import information has been provided.
  - iv. With regard to the contention that the petitioner has not mentioned the standard weight, it is noted that the import transactions have been given. It is noted that out of the total imports of 23075 Axles in the POI 22040 were already reported in kgs and only 1035 were converted from numbers to kgs. They were converted at standard weight of 353 kgs per axle.
  - v. With regard to the contention that there are gross mis-declarations/suppressions in the Petition and on a number of occasions, the Petitioner has imported the central/axle beam from China PR and the same is clearly evidenced by the import records obtained from a reliable source, the Authority notes that the contentions are denied by the applicant. It is also noted that the evidence of import provided by the opposing party does not show that such imports are made by the applicant or there are imports of central/axle beam.
  - vi. With regard to the contention that York Transport Equipment (India) Pvt. Ltd., a TATA enterprise has two related companies in India namely Tata Motors Ltd and Tata International Pvt., Ltd which are dealing with the product concerned and these parties did not file any response or did not join the application and this has vitiated the domestic industry chain as applied in the case of exporters, it is noted that the application satisfies the requirement of standing as per the relevant rule.
  - vii. With regard to the contention that in case an exporter does not file Questionnaire Response of its related producer in subject country even though it has not exported the subject goods, DGAD in the past several cases have rejected the response of participating exporter and the same analogy should be applied in the instant investigation also, the Authority notes that such comparison have no factual or legal basis. The requirement of establishing standing and establishing reliability of

export price in an anti-dumping investigation cannot be equated and the criteria are ought to differ as provided in the rule.

- viii. With regard to the contention that Yorks has two related producers of subject goods in China PR and mere statement by Yorks that related companies in China namely Qungdao YTE Special Products Co. Ltd. and York Transport Equipment (Shanghai) Co. Ltd., China have not exported the subject goods is not sufficient and these related companies' must have filed questionnaire response themselves or should have given details of its sales to establish that these companies have not exported the subject goods to India, the Authority notes that such contentions have no legal sanctity and also the responding interested parties have not given any evidence to show export of subject goods to India from the above stated related producers.
- ix. With regard to the argument that some interested parties attended the oral hearing and made submissions, however, did not reproduce their oral submissions in writing and the Authority should not consider such oral submissions which are not subsequently reproduced in writing for the purpose of present investigation, it is noted that the position of Rule 6 (6) is very clear which says such oral information shall be taken into consideration by the Designated Authority only when it is subsequently reproduced in writing.
- x. With regard to the contention that KKTC has filed multiple IQRs through different legal representative and there is no confirmation as to which is the correct IQR which should be relied upon, the Authority notes that the company has provided a clarification on the same along with a new authorisation letter.

**G. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN.**

44. Of the three responding producers/exporters from China PR, Guangdong FUWA Engineering Manufacturing Co. Ltd and Guangdong FUWA Heavy Industries Co. Ltd. had filed the Market Economy Treatment (MET) Questionnaire to rebut the presumption of non-market economy status of China PR as per the anti- dumping rules. However, before verification visit both the producers/exporters withdrew their claim for Market Economy Status. Thus, no producers/exporters from China PR have effectively claimed MET.

**G.1 Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties**

45. The submissions concerning market economy, normal value, export price and dumping margin made by the producers/exporters/importers/other interested parties and considered relevant by the Authority are as follows;
- i. Normal value is given at US\$2 - 4 per Kg by the applicant. It does not appear correct and normal value has to be a finite number and not a range. The normal value does not appear range bound also and the variance is 100%
  - ii. Applicant had kept profit and interest in the Normal Value as confidential. The Authority should disclose those numbers and the Authority should not have permitted confidentiality on this data in the application.
  - iii. The level of comparison of Normal value and export price is improper.
  - iv. Dumping margin calculated by the applicant is erroneous.
  - v. Separate rate of duty may please be accorded to Guangdong Fuwa Engineering Manufacturing Co., Ltd., and Guangdong Fuwa Heavy Industries Co., Ltd., China PR, a fully cooperating Producer/Exporter of the subject goods into India.
  - vi. No methodology as to how the normal value has been arrived at has been provided in the Petition. Also, things like raw material costs, consumption norms used to calculate the normal value which could be easily furnished, have not been provided in the Petition.
  - vii. No evidence of adjustments made in export price such as ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight expenses, bank charges has been provided in the Petition.
  - viii. There is no mention of the efforts undertaken by the Petitioner to find the domestic prices in the third country for the purposes of calculating the normal value.
  - ix. The normal value determined for China PR is in contravention of the requirements under paragraph 7 of Annexure I of the AD Rules as the normal value has been computed based on prices paid or payable in India which is to be used as a last resort rather than the primary method.



- x. It is clear from various judgments and decisions available that in case of exports from non-market economy countries, the only correct practice to arrive at normal value is to apply the general rule i.e. the price or constructed value in a market economy third country or the price from such a third country to other countries including the country conducting the investigation. Only in those cases, where an Authority is unable to apply or exhaust the general rule, the alternative option of using some other reasonable basis can be resorted to.
- xi. The term “as is reasonably available to the applicant” does not mean that the Petitioner is at liberty not to give any evidence. The Authority acted in violation of Article 5.3 of WTO ADA by not examining the sufficiency of evidence presented along with the Petition.

### **G.2 Submissions made by the domestic industry**

46. The submissions concerning market economy, normal value, export price and dumping margin made by the domestic industry and considered relevant by the Authority are as follows;
- a. China PR should be treated as Non Market Economy country for the purpose of present investigation and Normal Value in case of Chinese producers should be determined as per the provisions of Annexure I Para 7.
  - b. Chinese producers have been denied MET status in several investigations including recently concluded investigations by both Indian Authority and other countries like EU, USA, Australia etc as a part of various anti dumping investigations by treating China PR an NME country.
  - c. Also we object to the claim of the responding exporters that they should be given different individual margins. Instead the above producers must be seen as one entity.
  - d. Responding exporter has submitted at page 2 of the EQR that the VAT refund rate on inputs during the POI was 15%. Adjustments for unclaimed VAT on exports should be adjusted from the export price of the exporter as per the consistent practice of the Authority. Also, the VAT refund rate may be taken as per actual evidences.
  - e. The information provided to the Authority shows warranty costs borne by the exporter. This straight away calls for adjustment of warranty cost while deriving net export price.
  - f. With regard to the contentions on determination of normal value and dumping margin, it is submitted that the applicant submitted normal value and dumping margin as per the available information and methods permissible specified in the AD Rule and relevant annexure to the rule. Details of such calculations are provided in the NCV application which is elaborate and contains all essential specifics. Thus, the misapprehensions and contentions of the interested parties have no basis.

### **G.3 Examination by the Authority**

47. With regard to the contention that the normal value determined for China PR is in contravention of the requirements under paragraph 7 of Annexure I of the AD Rules as the normal value has been computed based on prices paid or payable in India which is to be used as a last resort rather than the primary method, it is noted that the Authority has proceeded to calculate normal value and export and dumping margin as provided under the AD rule and not otherwise and the methodology adopted and the reasoning is self- explanatory.

#### **a) Determination of Normal Value**

48. The Authority notes that none of the producers/exporters from China PR have claimed to be operating under market economy condition for determination of normal value in case of China PR in terms of Para-6 of Annexure-1 to the Rules. Under this circumstance, the Authority is not in a position to apply Para 8 of Annexure 1 to the Rules to the Chinese producers/exporters and the Authority has to proceed in accordance with Para 7 of Annexure - I to the Rules.
49. Paragraph-7 of the Annexure-1 to the Anti-Dumping Rules provides as follows:

*“In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate*

*market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments”*

50. According to these Rules, the normal value in China can be determined on any of the following basis:
- On the basis of the price in a market economy third country, or
  - The constructed value in a market economy third country, or
  - The price from such a third country to other countries, including India.
  - If the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include reasonable profit margin.
51. The Authority notes that for determination of normal value based on third country cost and prices, the complete and exhaustive data on domestic sales or third country export sales, as well as cost of production and cooperation of such producers in third country is required. No such information with regard to prices and costs prevalent in these markets have been provided either by the applicant or by the responding exporters, nor any publicly available information could be accessed, nor the responding Chinese companies have made any claim with regard to an appropriate market economy third country at this stage. The Authority proceeds to construct the normal value based on any other reasonable basis.
52. The Authority has determined the Normal value for China PR on available facts basis in terms of second proviso of Para 7 of Annexure 1 to the AD Rules. Accordingly, the ex-works Normal Value of the product under consideration has been determined based on constructed costs of production based on the optimum cost of production of domestic industry along with selling, general & administrative costs and reasonable profits. The normal value so determined is US \$ \*\*\*/Kg.

**b) Determination of Export Price**

**i. M/s Guangdong FUWA Engineering Manufacturing Co., Ltd**

53. In the EQ Response, M/s Guangdong FUWA Engineering Manufacturing Co., Ltd, producer cum exporter, China PR has claimed to have exported \*\*\* pieces (\*\*\*) MT) of PUC for a total CIF value of US \$ \*\*\* to India. The Authority made adjustments on account of Ocean freight, marine insurance, handling charges, inland freight, credit cost, bank charges as claimed by the exporter in their EQ response besides impact of VAT refund in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for M/s Guangdong FUWA Engineering Manufacturing Co., Ltd, China PR is determined as US \$ \*\*\* per Kg.

**ii. Guangdong FUWA Heavy Industries Co., Ltd. China PR**

54. In the EQR, Guangdong FUWA Heavy Industries Co., Ltd, producer cum exporter, China PR has claimed to have exported \*\*\* pieces (\*\*\* MT) of PUC for a total CIF value of US \$ \*\*\* to India. The Authority made adjustments on account of Ocean freight, marine insurance, handling charges, inland freight, credit cost, bank charges as claimed by the exporter in their EQ response besides impact of VAT refund in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Guangdong FUWA Heavy Industries Co., Ltd, China PR is determined as US\$ \*\*\*/KG.

**iii. Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co., Ltd.**

55. In the EQR, Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co., Ltd, producer cum exporter, China PR has claimed to have exported \*\*\* pcs (\*\*\*) MT) of PUC for a total FOB value of US \$ \*\*\* to India. The Authority made adjustments on account of inland freight, credit cost, bank charges as claimed by the exporter in their EQ response besides impact of VAT refund in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co., Ltd, China is determined as US\$ \*\*\*/KG.

**iv. All other Producers/Exporter from China PR**

56. In respect of non-cooperating producer/exporters from China PR, the Authority has determined their net export price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. Accordingly, the net export in respect of the non-cooperating exporters from China PR has been determined as US\$ \*\*\*/Kg.

**c) Determination Of Dumping Margin**

57. Based on normal value and export price determined as above, the dumping margin for producers/exporters from China PR has been determined by the Authority as follows;

Particulars	Normal Value - US\$/Kg	Export price - US\$/Kg	Dumping Margin US\$/Kg	Dumping Margin Range - %
M/s Guangdong FUWA Engineering Manufacturing Co., Ltd, (Producer and Exporter)	***	***	***	30-35
Guangdong FUWA Heavy Industries Co., Ltd (Producer and Exporter)	***	***	***	
Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co., Ltd.	***	***	***	35-40
All other Producers/Exporters	***	***	***	55-60

**H. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK****i. INJURY EXAMINATION****H.1 Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties**

58. The following are the injury related submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties;
- The applicant has relied upon IBIS data which is claimed to be not covering all the ports and casted the responsibility of getting the correct and full data of imports as per DGCI&S on the Authority. The import figure provided by the applicant doesn't appear reliable.
  - The domestic industry hasn't suffered any volume injury. Gloomy picture of certain price parameters showing injury are not correct in view of the annual report of the company for 2014-15 which shows profits. Thus, there is no injury.
  - The term capacity utilisation has no relevance in this case since there is no real manufacturing activity involved.
  - There is no price undercutting in the present case and the claims of price undercutting by the applicant is not correct. Also, there haven't been any price suppression/depression effects created by the dumped imports.
  - The real position of injury of the company is available in the balance sheet of the company which is provided in the public domain. There is robust growth in terms of production, capacity, capacity utilization and domestic sales. It is evident from this that there is no injury on account of dumping but other factors are influencing the industry as whole.
  - There is variation in the NCV trend of profitability, ROCE etc as per the application and the actual profits given in the Annual Report of the applicant. This needs to be examined by the Authority and the applicant should be asked to explain the difference
  - Market share provided in the application is not correct as the demand is without taking into consideration the large replacement market. Even the import data relied upon doesn't show complete picture of import.
  - Admittedly, there is no injury on account of employment, wages and productivity.
  - There are many known importers and users of subject goods who are importing as well as indigenously procuring. The Authority should call for information from such parties.
  - Increase in inventories could be due to a strategy of the applicant to store the material for exports and the same has no other relevance.
  - In this investigation price at which Yorks has sold the subject goods to its related company in India is very important. Whether they have charged a lower price to the related company? Whether this transfer price is the main cause of injury to the applicant domestic industry?

- xii. Tata Motors has not filed response due to the fact that it is making huge profits and its cost is much lower than cost of Yorks. In case Tata Motors files the response there is strong possibility that it will lower the Non-injurious price and as per practice of DGAD, constructed Normal Value shall be based on the cost of the most efficient producer in India. Inclusion of Tata Motors as part of Domestic Industry will definitely show that negative dumping and injury margins.
- xiii. No details about any fixed costs – such as interest costs and depreciation have been provided so as to verify the reasons for which alleged losses have been incurred. This is especially important as the Petitioner Company had been set up recently and would not have been able to make up for these costs.
- xiv. There is no mention of the efforts undertaken by the Petitioner to find the domestic prices in China PR or a third country market economy for the purposes of calculating the normal value.
- xv. The manufacturing facility at Pune was set up in mid 2011 and the Jamshedpur plant of the Petitioner was the only unit in operation prior to that. This fact has not been stated in the Petition. It must be noted that this fact has a material bearing in the analysis of profit/loss as it is unlikely for a new unit to recover all the costs in the first few years of its setting up.
- xvi. Market intelligence suggests that a sizeable number of sales of such axles produced by the Petitioner have been made to Tata International Pvt Ltd. This can play an important role in assessing the reason for the alleged losses of the domestic industry.
- xvii. KKTC has been consistently selling its products at prices higher than the prices of the domestic industry and this raises suspicion on the allegation of price undercutting range indicated in the Petition and also raises suspicion on the *bona fide* of the Petitioner.
- xviii. The demand in India is incorrectly shown in the Petition. As per the data obtained by “SIAM”, the number of axles and their quantity (in MT) required in India has been calculated for the financial years 2012-2013, 2013-2014 and 2014-2015 which is as follows;

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	POI Annualised
Demand – as stated in the Petition	MT	13,892	8,762	16,639
Demand - Calculated as per SIAM Data	MT	18,593	13,109	27,644

- xix. There is gross discrepancy in the demand and the figures provided by the Petitioner are incorrect and without any evidentiary support. It must also be noted that there are producers of trucks who are not part of SIAM and their data is not included. This suggests that the demand is much higher than what is represented.
- xx. Even with the data in the Petition, injury – especially causal link cannot be established.
- xxi. The data concerning imports and demand shows that the volume of imports is in tandem with the demand that is - the import volumes are high when the demand is the high and the import volumes are low when the demand is low. The trend suggests that the volume of imports has no real impact on the domestic industry.
- xxii. There is a significant increase in the production, productivity per day, productivity per employee and the capacity utilisation. There is a gradual reduction in the imports in relation to the production in India. This suggests that the domestic industry is showing signs of growth despite imports from China PR. Imports have no impact on the domestic industry.
- xxiii. 49% utilisation is not a very meagre amount when seen in the context of the demand in the Indian market. The demand in India is around 16,639 MT and the Petitioner produces 7,967 with the said capacity utilisation. With the said utilisation, the Petitioner is almost producing almost 48% of the goods required in the Indian market. Considering the growth and the significant capacity to meet the demand in India, it cannot be said that the imports are causing injury to the domestic industry.
- xxiv. Imports from the subject country cannot cause injury with a limited market share and the losses of the domestic industry are reducing over the period of injury.

- xxv. The domestic industry is showing signs of growth despite imports from China PR
- xxvi. The domestic producers are unable to provide good quality axles and cannot meet the demand of the Indian users. The axles imported by KKTC is mainly a unique one-piece produced by FUWA Engineering Group Ltd. (which has 80% market share in China PR as per Market intelligence) using One-Piece Beam with Hot Forming Spindles Technology as opposed the welding of four (4) individual parts by the domestic industry. The latter is weak/not stable and market intelligence suggests that it has succumbed to daily usage. End users of the Axle are willing to pay more for the axles sold by KKTC which also suggests that the consumers prefer the said axles over the axles produced in India.
- xxvii. The domestic producers are unable to recover losses in light of the fixed costs. The alleged losses are on account of the costs of setting up a new plant.
- xxviii. If AD duty is imposed, the Petitioner being the only big and regular manufacturer of axles will monopolize the market and may abuse its dominant position. Giving further protection to the biggest producer of axles in India will probably give rise to adverse anti-competitive effects.
- xxix. Working capital and net fixed assets shows a very suspicious fluctuation on the Proforma IV A.
- xxx. The Petitioner has failed to establish dumping, injury and causal link in the present investigation. The data in the Petition does not support imposition of anti-dumping duties on the subject goods.

## **H.2 Submissions made by Domestic Industry**

59. The following are the injury related submissions made by the domestic industry in brief;

- a) The information with regard to Volume and Price effect and economic parameters relating to the domestic industry in Proforma IV and IVB shows that although some volume parameters such as production, capacity utilization and sales followed a positive trend, a number of other indicators relating to the financial situation of the domestic industry, namely profitability, return on investment, cash profit etc were significantly negative in the POI and did not follow any satisfactory or even reasonable trend during the POI vis-à-vis some volume improvement apparent in the same period.
- b) In fact the domestic industry has faced huge financial losses on account of aggressive dumping adopted by producers/exporter from China PR in the injury period except the base year and meagre volume growths did not help the domestic industry to achieve any reasonable profit since the price increases were prevented by dumped imports.
- c) An objective and holistic evaluation of various economic parameters would clearly demonstrate that dumped imports from subject country have caused material injury to the domestic industry.
- d) The price effect of the dumped imports has been significant on the basis of price undercutting, price suppression and price depressions as a result of which profitability of the domestic industry has deteriorated and situation of the domestic continued to be loss making after base year, thus, the domestic industry has suffered material injury.
- e) The improvements in volume parameters were all vitiated because of the below par price realization triggered by dumping and in effect the improvements in some standalone volume parameters did not create any material positive effect on the overall situation of the domestic industry as the domestic industry was forced to sell at a price which is was not remunerative and, in fact, below its cost of production. The domestic industry has, thus, suffered material injury.
- f) The price at which the product under consideration is imported into India is below its normal value resulting in significant dumping margin.
- g) The domestic industry has been compelled to offer sub-optimal prices lowering profitability to a negative level and to the level which is unviable and continuity of operation is hugely impacted.
- h) Presence of import at very low and dumped price preventing domestic industry to increase their price to the extent of increase in input cost, thus imports are suppressing the selling prices of the domestic industry and also causing depressing effect.
- i) Reduction in profits directly resulted in deterioration in return on capital employed and cash profits. The domestic industry has not been able to cover the cost of capital. Thus, losses, negative return on capital employed and also cash profit is directly due to dumped imports.
- j) The injury caused to the domestic industry is on account of dumped imports from subject country only.

- k) It is also submitted that even though significant demand for the product remained in the Indian market, the domestic industry was put in a situation of huge financial losses as an effect of injurious dumping from subject country. In fact, continuous adverse market conditions with regard to subject goods on account of dumping from China PR prevented the domestic industry from achieving any reasonable and legitimate profits and further enhancing the capacities.

### **H.3 Examination by the Authority**

60. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
61. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows.
- “The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”*
62. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties. However, the specific submissions made by the interested parties are addressed by the Authority are as below;
63. With regard to the contention that the applicant has relied upon IBIS data which is claimed to be not covering all the ports and casted the responsibility of getting the correct and full data of imports as per DGCI&S on the Authority and the import figure provided by the applicant does not appear reliable, it is noted that IBIS data has been relied upon in many past cases by the Authority Further, the import data of IBIS has been cross verified with DGCIS data. There is similar trend in volume and prices.
64. With regard to the contention that the domestic industry hasn't suffered any volume injury and the gloomy picture of certain price parameters showing injury are not correct in view of the annual report of the company for 2014-15 which shows profits, thus, there is no injury, it is noted that the information in Annual Report is for company as a whole and does not pertain to PUC alone. Facts of dumping and injury and a causal link between the same are provided at appropriate places in this final findings.
65. With regard to the contention that the term capacity utilisation has no relevance in this case since there is no real manufacturing activity involved, it is noted that the contention is unsubstantiated.
66. With regard to the contention that there is no price undercutting in the present case and the claims of price undercutting by the applicant is not correct and also, there haven't been any price suppression/depression effects created by the dumped imports, it is noted that the final findings herein below is self-explanatory on such claims.
67. With regard to the contention that the real position of injury of the company is available in the balance sheet of the company which is provided in the public domain, it is noted that the Balance sheet and profit and loss account referred pertains to company as a whole whereas the Authority has to analyse the performance parameters relating to PUC only.
68. With regard to the contention that market share provided in the application is not correct as the demand is without taking into consideration the large replacement market, it is noted that the claim is not backed with any evidences.
69. With regard to the contention that price at which York Transport Equipments (India) Pvt Ltd. has sold the subject goods to its related company in India is very important and whether this transfer price is the main cause of injury to the applicant domestic industry, the matter has been examined and It was found that related party sales in domestic market was less than 20% during POI. Further, the average selling price to the related company was marginally lower than average selling price in the domestic market. This may be due to various reasons like non-incurring of certain expenses like freight due to proximity of the unit and non-payment of commission to any intermediary for undertaking sales. Moreover, even after

excluding the sales to related parties there was positive price undercutting. Hence the main cause of injury to the applicant domestic industry is not any related party transaction as claimed by the interested parties.

70. With regard to the contention that Tata Motors has not filed response due to the fact that it is making huge profits, it is noted that M/s York Transport Equipment (India) Pvt Ltd along with the supporter is found to be the domestic industry in the present investigation as per Rule 2 (b) and the rule does not mandate anything as submitted by the other interested parties other than requirements of rule 2(b). It is also noted that the applicant has submitted that TATA Motors Ltd is a different legal entity and not a related party as envisaged in the rules in any case and the applicant satisfies the requirement of standing.
71. With regard to the contention that the manufacturing facility at Pune was set up in mid 2011 and the Jamshedpur plant of the Petitioner was the only unit in operation prior to that, it is noted that the Authority has examined the claim of injury as provided in the rules and not otherwise.
72. With regard to the contention that KKTC has been consistently selling its products at prices higher than the prices of the domestic industry and this raises suspicion on the allegation of price undercutting range indicated in the Petition and also raises suspicion on the *bona fide* of the Petitioner, it is noted that price undercutting is worked out based on the average NSR and landed price of imports and not based on reselling price to any individual buyer.
73. With regard to the contention that the data concerning imports and demand shows that the volume of imports is in tandem with the demand that is - the import volumes are high when the demand is the high and the import volumes are low when the demand is low, it is noted that imports are significant and occurring at dumped and injurious price.
74. With regard to the contention that there is a significant increase in the production, productivity per day, productivity per employee and the capacity utilisation and there is a gradual reduction in the imports in relation to the production in India and this suggests that the domestic industry is showing signs of growth despite imports from China PR. Imports have no impact on the domestic industry, it is noted that the facts emanating from this final findings is self-explanatory on such contentions.
75. With regard to the contention that imports from the subject country cannot cause injury with a limited market share and the losses of the domestic industry are reducing over the period of injury, it is noted that the facts emanating from the present final findings is self-explanatory on this contention.
76. With regard to the contention that the domestic industry is showing signs of growth despite imports from China PR, it is noted that the facts emanating from the present final findings is self-explanatory on this contention.
77. With regard to the contention that the domestic producers are unable to provide good quality axles and cannot meet the demand of the Indian users, it is noted that the applicant submitted that their product meets required quality standard and the contentions of the opposing party is not true. Also, the interested parties have not produced any evidences to show that there are material differences in the PUC imported and that domestically manufactured product.
78. With regard to the contention that the domestic producers are unable to recover losses in light of the fixed costs and the alleged losses are on account of the costs of setting up a new plant, it is noted that the argument is unsubstantiated.
79. With regard to the contention that if AD duty is imposed, the Petitioner being the only big and regular manufacturer of axles will monopolize the market and may abuse its dominant position and giving further protection to the biggest producer of axles in India will probably give rise to adverse anti-competitive effects, it is to be noted that the AD duties if imposed are only to remove the injurious effect of dumping and do not envisage any protection beyond the lower of injury or dumping margin.
80. With regard to the contention that the Petitioner has failed to establish dumping, injury and causal link in the present investigation and the data in the Petition does not support imposition of anti-dumping duties on the subject goods, it is noted that the facts emanating from the present final findings is self-explanatory on this contention.
81. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India,  
the Authority has considered such further indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc in accordance with Annexure II (iv) of the Rules supra.

**ii. VOLUME EFFECT OF THE DUMPED IMPORTS ON THE DOMESTIC INDUSTRY**

82. For assessing the injury, the Authority has examined the volume and price effects of the dumped imports of the subject goods from the subject country on the domestic industry and its effect on the price and profitability to examine the existence of injury and causal link between the dumping and injury, if any. Accordingly, the volume and price effects of dumped imports have been examined as follows:

**a. Demand and market share**

83. Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

**iii) Demand**

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI	POI Annualised
Demand	MT	16902	13923	8785	20855	16684
Indexed	Trend	100	82	52	99	99
Imports from Subject Country	MT	4,917	4,433	3,066	8,250	6,600
Imports from Other Country	MT	526	8	-	-	-
Sales of Domestic Industry	MT	4542	3517	2605	6501	5201
Sales of other Indian Producers	MT	6,916	5,965	3,114	6,104	4,883

**iv) Market Share in Demand**

84. Considering imports of subject goods from various sources and sales of subject goods of the Indian Producers, market share of subject imports in demand in India was examined. Factual position in this respect is as follows;

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI	POI Annualised
Imports from Subject Country	%	29.09	31.84	34.90	39.56	39.56
Imports from Other Country	%	3.11	0.06	-	-	-
Sales of Domestic Industry	%	26.88	25.26	29.65	31.17	31.17
Sales of other Indian Producers	%	40.92	42.84	35.44	29.27	29.27

85. It is seen from the above tables that demand of the product in the country has declined during 2012-13 and 2013-14 as compared to the base year and has picked up during POI. Applicant claimed that the dip in demand between base year and 2013-14 was the result of adverse economic situation in the country which impacted the Trailer production however the same was corrected to large extent by the POI. It is noted that the share of subject country imports which was 29.09% in the base year increased to 39.56% in the POI whereas the market share of the domestic industry which was 26.88% in the base year increased only to 31.17% during POI. Even the share of other Indian producers declined in this period. Thus, the increases in demand were all primarily absorbed by dumped imports from subject countries. Impact of dumped import from subject countries on market share of the domestic industry is evident.



**b. Import volume and market share**

86. The Authority has examined the volume of imports of the subject goods as per the transaction wise import data of the IBIS and correlated with the DGCI&S data. The Authority has relied upon the same for this final findings. On the basis of import data on record, the import volume from subject country is found to be above the de-minimis levels. Imports volume from subject country and other country has been as under:-

Particulars		Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI	POI Annualised
Volume	Subject Country	MT	4,917	4,433	3,066	8,250	6,600
	Other country	MT	526	8	-	-	-
	Total imports	MT	5,444	4,441	3,066	8,250	6,600
Market Share in Imports	Subject Country	%	90.33	99.81	100.00	100.00	100.00
	Other country	%	9.67	0.19	Nil	Nil	Nil

87. It is observed that imports from subject country increased in absolute terms and was all along more than 90% of the total imports into India throughout the injury period including the POI. In fact, imports from subject country constituted 100% except the base year and year after that. It is also noted that imports from subject country accounts for very significant proportion of the demand of the product in India. The volume of imports from the subject country increased in absolute terms and also relative to increase in demand in India during the injury period and during the POI. The imports from subject country which was 4917 MT in the base year has increased significantly in absolute terms to 6600 MT (Annualised) during the POI and also in relation to demand. The significant share of dumped imports in domestic demand and the growth of the same relative to the increase in demand is very evident.

**c. Capacity & capacity utilization**

88. Capacity and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the following table: -

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI	POI Annualised
Capacity MT	MT	16560	16560	16560	20700	16560
Capacity utilization	%	26.81	30.96	32.81	50.23	50.23

89. It is observed that capacity utilization of the domestic industry increased over the base year but remained at 50.23% during the POI. It is also noted that capacity utilization has remained at a below par level throughout the injury period. The dumped imports prevented them from operating at an optimal level of capacity utilisation. Increase in capacity utilisation if looked at as a standalone parameter would give distorted picture of actual position of injury to the domestic industry. The slight increase in capacity utilisation should be seen along with the price parameters pertaining to injury which showed sharp decline.

**d. Production**

90. Production of the domestic industry is given in the following table: -

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI	POI Annualised
Production	MT	4439	5127	5433	10,397	8,318
Demand	MT	16902	13923	8785	20855	16684
Production in relation to Demand	%	26.26%	36.82%	61.84%	49.85%	49.85%

91. Production showed increasing trend throughout the injury period. Even though the above volume parameters show an increasing trend, the associated price parameters showed sharp declines and financial losses have been suffered by the domestic industry effectively negating the benefits which ought to have been achieved by the domestic industry by virtue of increase in volume parameters. It is also noted that production in relation to demand in India which was increased to a level of 61.84% in 2013-14 declined to a level of 49.85% in the POI.

**e. Sales volume**

92. Sales volume of the domestic industry is given in the following table:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI	POI Annualised
Domestic sales	MT	4542	3517	2605	6501	5201
Demand	MT	16902	13923	8785	20855	16684
Market Share of domestic industry in Demand	%	26.87	25.26	29.65	31.17	31.17

93. Even though the sales volume shows an increasing trend, the associated price parameters showed sharp declines and financial losses have been suffered by the domestic industry. This increase in sales volume has been achieved by adjusting the price to match the landed price of imports. In essence, increase in sales volume did not create any bottom line improvement.
94. In this context of increase in volume parameters as such were not reflected in the overall performance of the domestic industry if financial parameters are also taken into consideration. Increases in volume parameters may at the best have neutralised some effect of fixed costs on performance but the same was not adequate to bring an overall improvement in the performance.
95. The Authority notes in this respect that the sales volume of the domestic industry among other volume parameters increased over the injury period and during the POI. However, as noted herein above, the increase in market share of imports from China PR has been much higher than the increase in market share of domestic industry in the Indian demand during the POI.

**f. Inventories**

96. Inventories with the domestic industry moved as follows;

	Units	2011-12	2012-13	2013-14	POI	POI Annualised
Average Stock	MT	180	221	279	332	332
Indexed		100	123	155	184	184

97. It is noted that inventories with the domestic industry increased consistently during the injury period. It is noted that this may not be a significant indicator of injury considering the fact that the subject goods are primarily produced against order.

**iii. PRICE EFFECT OF THE DUMPED IMPORTS ON THE DOMESTIC INDUSTRY**

98. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the purpose of this analysis, the weighted average cost of production (COP), weighted average Net Sales Realization (NSR) and the Non-Injurious Price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject country.

**a) Price Undercutting**

99. The net sales realization was arrived after deducting all rebates and taxes. Landed value of imports has been calculated by adding 1% handling charge and applicable basic customs duty to the CIF value of subject imports. The landed value of imports was compared with net sales realization of the domestic industry and it was found that the dumped imports are undercutting the prices of the domestic industry.

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Landed Value	Rs./KG	***	***	***	***
Net Sales realization	Rs./KG	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./KG	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	% Range	15-20	5-10	1-5	5-10

100. It is observed that landed price of imports from subject country have been significantly lower than the net sales realization of the domestic industry resulting in significant price undercutting during the injury period and in the POI. Landed price of import from subject country showed some decreases during POI after some increases between base year and immediate previous year. The price undercutting which showed some reduction in the year 2012-13 and 2013-14 once again increased in the POI.

**b) Price Underselling**

101. Authority notes that the price underselling is an important indicator of assessment of injury. Non injurious price has been worked out and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic producer by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI in accordance with Annexure III of the AD Rules. The analysis shows that the landed value of subject imports was significantly below the non-injurious price determined as follows;

Particulars	Unit	China PR
Non-Injurious Price	Rs/KG	***
Landed price	Rs/KG	109.73
Price underselling	Rs/KG	***
Underselling	%	***
Underselling	% Range	10-15

**c) Price suppression/depression**

102. The Authority examined whether the effect of the dumped imports was to depress the prices of the like article in India, or prevent price increases which would have otherwise occurred.

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Cost of production	Rs./KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	118	108
Selling Price	Rs./KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	98	102
Landed Value	Rs./KG	95.35	105.80	110.09	109.73
Trend	Indexed	100	110	115	115

103. It can be seen from the above table that while the cost of production increased from 100 in the base year to 108 in the POI, the selling price moved from 100 indexed in the base year to 102 only during the same period meaning thereby the prices were suppressed on account of the dumped prices as the domestic industry was not able to increase its prices in proportion to increase in costs. It is evident that the landed price of imports was causing price suppression of a significant magnitude showing serious price effects on the sales realization of the domestic industry apart from serious price undercutting. Thus, the dumped imports were creating price suppression effect on the domestic industry.

**d) Profit/Loss**

104. The profitability of the domestic industry is given in the following table;

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI (Annualised)
Profits	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(971)	(1266)	(315)
Profits	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(750)	(725)	(360)

105. It is noted that there have been serious distortions on the profitability of the domestic industry during the injury period and the profits declined significantly over the years whereas the domestic industry was earlier earning profits but subsequently incurred losses throughout the injury period, though the losses during POI have declined due to improvement in production and sales. It is noted herein above that the landed price of imports were creating price undercutting and underselling effects on the domestic prices in the same period. The impacts of such landed prices are evident in financial loss situation of the domestic industry.

**e) Return on capital employed**

106. Information regarding return on capital employed is given in the table below;

	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(949)	(1061)	(293)

107. The Authority notes that return on capital employed of the domestic industry has deteriorated significantly over the injury period and remained negative in the POI and the trend is comparable to that of profitability. It is also noted that the domestic industry has been incurring financial losses in the same period.

**f) Cash Flow**

108. Authority has examined the trends in cash profits in order to examine the impact of dumping on cash flow situation of the domestic industry. Information regarding cash profit of the domestic industry is given in the following table;

	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI (annualised)
Cash profits	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(325)	(325)	(135)

It is seen that the cash profits of the domestic industry steeply declined over the injury period. It is also noted that the cash profit and cash flow situation of the domestic industry recorded adverse situation.

**g) Factors affecting domestic prices**

109. Change in cost structure, competition in the domestic market and prices of competing substitutes, if any, have been examined for analyzing the factors other than dumped imports that might be affecting the prices in the domestic industry. It could not be concluded that inter-se competition or any such change in cost structure led to decline in the prices of the domestic industry.

**h) Productivity**

110. Authority notes that productivity of the domestic industry shows same trend as that of production. Productivity shows an increasing trend, and it can be construed that productivity has not been a cause any of injury to the domestic industry;

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Productivity per employee	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	114	176
Productivity per day	MT/day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	125	192

**i) Employment and Wages**

111. The employment level has shown some increases by the POI but only at very marginal levels. Overall wages per kg, however, showed declines in the POI which should be seen along with the improved productivity per employee and per day.

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Employment	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	107	107
Wages	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	81	74	88

**j) Growth**

112. The Authority notes that growth of the domestic industry was negative in a number of parameters. Growth of domestic industry in many parameters occurred when the market demand for the product showed substantial growth.

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Production (MT)	%		15.49	5.97	53.09
Domestic Sales (MT)	%		-22.58	-25.93	99.65
Profit/ (Loss) Rs lacs	%		-850	3.35	50.35
Cash Profit (Rs. Lacs)	%		-425	0.21	58.42
ROI	%		-1049	-11.81	72.42
Demand	%		-18	-37	90

**k) Ability to raise capital investment**

113. It is seen that the profitability of the domestic industry has marked sharp declines and the domestic industry has been suffering financial losses. The situation is not viable to raise additional capital investment when the ROI from the existing investments were suffering.

**I. CONCLUSIONS ON INJURY**

114. On examination of various injury parameters, the Authority concludes that imports from subject country have increased in absolute terms and also in relation to production and consumption in India. Imports of the product were undercutting the prices of the domestic industry in the market and were creating underselling and price suppression effects. Further, whereas cost of production kept increasing over the injury period, the selling price of the domestic industry could not be increased even to the levels of cost of production that the domestic industry suffered financial losses. The imports were, thus, suppressing the prices of the domestic industry and preventing the price increases that would have otherwise been occurred in the absence of dumped imports.
115. It is noted that the demand for the product and sales of the domestic industry increased significantly, however, domestic industry could not increase its profitability proportionately as dumped imports continued to hold very significant share in the market. Such dumped volumes showed increasing trend with continues price cuts prejudicing the ability of the domestic industry to pass on increase in costs to the customers and realising reasonable profits. Resultantly, the domestic industry started incurring financial losses. Even though the domestic industry could increase its sales volumes, the same did not create any positive effect on the profitability since such increased sales volumes were achieved by matching the dumped price of subject goods from subject country.
116. Profitability of the domestic industry declined continuously and the domestic industry has been making financial losses. Return on capital employed and cash profits followed the same trend as that of profits. Both return on capital employed and cash profits marked significantly negative figures in the POI.

**J. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS**

117. Having examined the existence of material injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price underselling and price suppression, and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-Dumping, the Authority has examined whether other factors listed under the AD Rules could have contributed to injury to the domestic industry. The examination of causal link has been done as follows;

**(a) Volume and prices of imports not sold at dumped prices**

118. During POI, it is noted that entire imports of the subject goods has been from subject country. Therefore, the imports from other countries cannot be considered to have caused injury to the domestic industry.

**(b) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**

119. It is noted that there is a single market for the subject goods where dumped imports from the subject country compete directly with the subject goods supplied by the domestic industry. It is also noted that the imported subject goods and domestically produced goods are like article and are used for similar applications/end uses. There is no evidence of trade restrictive practices of and competition between the foreign producers and domestic producers causing injury to the domestic industry.

**(c) Contraction of demand or Changes in the pattern of consumption**

120. The Authority notes that demand for the product showed decrease in the earlier part of the injury period and increased significantly during the POI. The Authority, thus, concludes that injury to the domestic industry was not due to contraction in demand.

**(d) Development in Technology**

121. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the domestic industry.

**(e) Export performance of Domestic Industry;**

122. The details of exports by the domestic industry is as follows;

Period	2011-12	2012-13	2013-14	POI Annualised
Volume in MT	-	***	***	***
Indexed	Nil	100	204	212
Value Rs per KG	Nil	***	***	***
Indexed	Nil	100	113	123

123. Performance of the domestic industry has been segregated for domestic and export market and profitability in the domestic market alone is considered for this final findings. Therefore, any possible decline in export performance is not a cause of any injury. The Authority has considered only domestic operations in order to ascertain impact on price parameters.

**(f) Productivity of the Domestic Industry**

124. Productivity of the domestic industry increased consistently. However, regardless of changes in productivity levels, the profitability of the domestic industry showed continued decline.
125. From the foregoing, the Authority concludes that there is no evidence of injury being caused due to other factors.

**K. FACTORS ESTABLISHING CAUSAL LINK**

126. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has been materially injured over the injury period and during the POI. The causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:
- Subject goods are imported into India at dumped prices. The dumped imports from subject country have significantly increased over the injury period. Significant increase in imports from subject country coincided with significant share in the domestic market adversely affected the ability of domestic industry to increase its market share while achieving fair and profitable price for the subject goods;
  - Dumped imports from subject country are suppressing the prices of the domestic industry. As the domestic industry has tried to align its selling prices close to the landed prices, the increase in selling prices were considerably less than increase in cost of production and resultantly the domestic industry suffered financial losses;
  - Imports from subject country are undercutting the prices of the domestic industry at significant levels. This is preventing the domestic industry from increasing its prices in line with increase in cost and so as to achieve reasonable profit. In fact, the domestic industry has been forced to reduce the prices when the cost of production increased over the injury period;
  - The price suppression effect of dumped imports is visible on significant decline in profitability to the domestic industry;
  - Deterioration in profits, return on capital employed and cash profits are direct result of dumped imports;
127. The Authority is of the view that the above grounds clearly establish existence of causal link between dumped imports from subject country and injury to the domestic industry. Thus, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury due to dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

**L. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN**

128. The Authority has determined non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules, as amended. The non-injurious price so determined has been compared with the landed prices of imports from the subject countries.

Name of Producer/exporter	NIP/Kg (US\$)	Landed Value/kg (USD)	Injury Margin	Injury margin %	IM (%) Range
Guandong FUWA Engineering Manufacturing company Ltd.	***	***	***	***	5-15
Guangdong FUWA Heavy Industries Co., Ltd.	***	***	***	***	
Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co., Ltd.	***	***	***	***	5-15
Any other producer	***	***	***	***	25-35

**M. SUBMISSIONS MADE BY THE INTERESTED PARTIES POST DISCLOSURE STATEMENT**

129. The examination of the comment to the disclosure comment is as follows:

**M.1 Comments from Domestic Industry**

130. M/s Guangdong FUWA Engineering Manufacturing Co., Ltd, (Producer and Exporter) and Guangdong FUWA Heavy Industries Co., Ltd (Producer and Exporter) are related entities and same duties should be recommended for these parties- It may be noted that M/s Guangdong FUWA Engineering Manufacturing Co., Ltd, (Producer and Exporter) and Guangdong FUWA Heavy Industries Co., Ltd (Producer and Exporter) are related entities and same duties needs to be recommended for these parties. This is the practice in the DGAD in the case of related producer/exporter and we request the Authority to follow the same practice for the purpose final finding in the present case also

**M.2 Comments from other interested parties****PUC and like article**

- Single piece axles are the most preferred axles in the country and such a product is not available in York range. The product offered by the domestic industry is inferior and substandard.
- The Respondent has been submitting to the Authority that there are material differences in quality of the axles sold by the Respondent and the one produced by the domestic producers.

**Scope of Domestic industry and standing**

- The Authority merely notes that information about total Indian production has been estimated by adding 5% inventory to the sales of other Indian producers; and the sales figure of other Indian producers is taken as the difference between total Indian demand minus imports and domestic sales of the Domestic Industry. The Authority has given no basis as to why an arbitrary 5% must be added to the sales to calculate production. In fact, the choice of 5% is even more arbitrary as the Petitioner's own inventories (332 MT in the POI) constitute 6.38% of their domestic sales (5201 MT). In light of the same, the Authority must at least add 6.38% to the sales of the other producers to arrive at the estimated production.
- The assumption that the sales of the prime movers can be used to estimate the production will lead to a severe under-representation of the production figures as it does not account for the unsold axles, axles produced for replacement market, and non-inclusion of many producers in the SIAM data. It is imperative that the Authority arrives at the actual demand, production and sales figures here. As submitted earlier, the implications of these calculations not only on the issue of standing but also to assess injury. Parameters like demand, market share of production and sales of other Indian producers which are essential for injury analysis.



Calculation of normal value and Dumping Margin

- The Authority has stated that it has constructed the Normal value for the Chinese producers on the basis of constructed costs of production, after including selling, general & administrative costs and reasonable profit margin. It does not mention what it relies on to calculate the raw material costs to arrive at the cost of production – domestic prices or international prices. This in itself prejudices Respondent as the Respondent will be unable to comment on how the normal value has been arrived at. If the Authority considers domestic prices to calculate the normal value, it goes against its own past practice. In fact, in light of the past practice, it should have necessarily considered international prices.

Miscellaneous Issues

- York prices are much lower than other domestic manufacturers. A strategic pricing to keep the competition away to garner major chunk of business in the Indian market and to move towards monopolistic position may be the reason.
- The extent of credit offered by the York in the market has not been studied.
- It is also submitted that the figures also suggest that there is inter- se competition between the domestic industry, other producers and the imported goods. The Respondent, therefore, fails to understand the basis for the submission that imports from the subject country is causing injury to the domestic industry. It is highly implausible that imports that hold a very small market share are capable of having a negative impact on the domestic industry. In light of the same, the Authority is requested to specifically assess inter- se competition between the domestic industry, other producers and the imported goods. In particular, it must assess inter- se competition between the domestic industry and the other producers as other axle producing companies such as Automotive Axles Ltd. and JOST India Auto Component Pvt. Ltd. have also recently (around 3-4 years) started their operations. This must be especially done in relation to Automotive Axles Ltd which being a supporter has provided its particulars like prices.
- There are three issues relating to Non Injurious Price-fixing of 22% return, assessment of capital employed and adjustment of after sales warranty.

Causal Link

- It has been submitted that other factors such as contraction of demand, increase in costs, sales to a related party and increase in fixed costs/costs due to setting up a new plant may have caused injury to the domestic industry. It is submitted that the injurious effects arising out of other factors besides dumped imports must be given adequate weightage. There may not be any correlation between price-under cutting and profits, cash flow and return on capital employed.

M.3 Examination by the Authority

- The submission made by the Domestic Industry with regard to imposition of single rate of antidumping duty on two related exporters has been examined and a weighted average dumping and injury margin has been worked for M/s Guangdong FUWA Engineering Manufacturing Co., Ltd, (Producer and Exporter) and Guangdong FUWA Heavy Industries Co., Ltd (Producer and Exporter) has been considered. The Authority noted that granting of individual dumping margins might enable related exporting producers to channel their exports to India through the company with the lowest individual antidumping duty enabling them to circumvent the anti-dumping measures and thus rendering them ineffective. In view of the above, the related exporting producers belonging to the same FUWA group have been regarded as one single entity and accordingly granted one single duty rate. For this purpose, weighted average dumping and injury margin has been separately worked out. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry.
- As regards quality issues, this issue has been dealt with a number of times and CESTAT has also pronounced judgements on this issue that quality is not a relevant consideration to like product determination, particularly when the claim of poor quality has not been quantified. The Authority notes that the Domestic Industry has been exporting the product globally in a significant quantity.
- As regards estimation of Indian production and standing, it is reiterated that the information about total Indian production was not readily available in the public domain and the applicant has devised a methodology to estimate the total Indian production and has relied upon production data of Prime Movers to which Trailers are attached wherein the subject goods are used in turn published by the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) as a basis to derive the requirement of subject

goods in India and to back calculate the probable domestic production in India. The opposing interested parties have neither provided the production data nor suggested any alternate methodology. They had suggested a higher demand on the basis of prime movers. Further, assumption of 5% inventory was considered reasonable by the Authority in view of the nature of the product. Even if such a figure was accepted, the Applicant domestic industry would have constituted 47% of the domestic production and along with the support of Automotive axles exceeded 50% of the production in India. More over, none of the other producers have opposed the investigation.

- As regards methodology of construction of normal value, it is noted that the product is assemblage of a variety of components for which international prices are not available. Therefore, the Authority had no option but to adopt the raw material (components) consumption and prices of domestic industry which is in consonance with the set Rules and practice.
- Regarding the contention that York prices are much lower than other domestic manufacturers and a strategic pricing to keep the competition away to garner major chunk of business in the Indian market, these have not been substantiated with any evidences. Analysis given in the finding does not also support this contention.
- Extent of credit given by Domestic Industry form part of working capital which has been duly studied and dealt with in terms of Annexure III to the AD Rules. Similarly, reasonable return has been provided and capital employed has been assessed as per consistent practice followed in DGAD. The incidence of warranty/after sales service has been worked as per books of accounts maintained by Domestic Industry and has been excluded from NIP treating it as post manufacturing expenses.
- As regards the contention that injury to the domestic industry is due to inter se competition between the domestic producers, the Authority notes that there is no such evidence provided by the interested parties. It is noted in this regard that the applicant is the largest producer of PUC and there is no opposition from any other producer. The landed value of imported articles is significantly lower than the NIP and net selling price of the applicant. Therefore, the Authority concludes that the lower landed price of the imported article triggers the domestic price. As such, the contention that inter-se competition is causing injury to the domestic industry does not hold.
- As regards other indicator of absence of causal link, it is noted that the demand pattern does not show contraction as it fell during early part of the injury period and picked up considerably during POI exceeding that of the base year. The Authority considers the fair cost of production as non-injurious price after optimising the actual cost of production for the purpose of injury analysis, therefore, the contention of the interested party does not have any strength. Moreover, the Authority examines all the relevant factors in totality and all the economic parameters need not show adverse performance to indicate material injury. As regards the contention of the interested party that injury has been inflicted by sales to the related party, the Authority examined this allegation and found that the price realisation in the case of related party was hardly 2.7%. Even if the price of the related party is increased by 2.7% in the injury analysis, overall impact on price undercutting would be hardly 0.7%.

## **N. Conclusions**

131. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

- (a) The products under consideration have been exported to India from China PR below their associated Normal values.
- (b) The domestic industry has suffered material injury.
- (c) The material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from China PR.

## **O. Indian industry's interest & other issues**

132. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

133. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the antidumping measures, particularly if the levy of the anti- dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline

of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. With a view to minimize the impact on the downstream industry, the Authority has considered it appropriate to recommend anti-dumping duty based on the lower of the dumping and injury margins. The Authority notes that the imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

#### **P.Recommendations**

134. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established definitively positive dumping margins concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject country and as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports; the Authority is of the view that imposition of definitive duty is required to offset dumping and injury in the instant matter. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti-dumping duties concerning imports of the subject goods from the subject country in the form and manner described here under.
135. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the antidumping duty equal to the amount indicated in Col 8 of the table below is recommended to be imposed concerning all imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

#### **Duty Table**

S.no.	Tariff Item	Description Of Goods	Country of Origin	Country Of Expert	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	87169 010	Axle for Trailers	China	China	Guangdong FUWA Engineering Manufacturing Co., Ltd.	Guangdong FUWA Engineering Manufacturing Co., Ltd.	0.16	Kg	US\$
2.	87169 010	Axle for Trailers	China	China	Guangdong FUWA Heavy Industries Co. Ltd.	Guangdong FUWA Heavy Industries Co. Ltd.	0.16	Kg	US\$
3.	87169 010	Axle for Trailers	China	China	Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co., Ltd.	Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co., Ltd.	0.14	Kg	US\$
4.	87169 010	Axle for Trailers	China	China	Any combination other than Sl. No 1 to 3 above		0.46	Kg	US\$
5.	87169 010	Axle for Trailers	China	Any country other than China	Any	Any	0.46	Kg	US\$
6.	87169 010	Axle for Trailers	Any country other than China	China	Any	Any	0.46	Kg	US\$

136. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

137. An appeal against the order of the Central Government arising out of this Final Findings Notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

A K BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority